*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

कुछ सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं में धीमी संवृद्धि के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था गति खो रही है और उच्च आवृत्ति संकेतक आने वाले समय में और अधिक गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत में, 2023-24 की तीसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि छह-तिमाही के उच्चतम स्तर पर थी, जो मजबूत गति, मजबूत अप्रत्यक्ष करों और कम सब्सिडी द्वारा संचालित थी। संरचनात्मक मांग की उच्च दृश्यता और स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक तुलन पत्र, आगे चलकर संवृद्धि को गति देने वाली ताकतें होंगी। भले ही मुख्य मुद्रास्फीति में व्यापक नरमी के साथ मुद्रास्फीति ढलान पर है, लघु स्तरीय खाद्य मूल्य के पुनरावृत्त दबाव हेडलाइन मुद्रास्फीति में 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर तेज गिरावट में बाधक हैं।

परिचय

कुछ सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं में और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में भी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि धीमी पड़ने और मामूली संकुचन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था गति खो रही है। उच्च आवृत्ति संकेतक आने वाले समय में और अधिक गिरावट का संकेत देते हैं। जबकि व्यावसायिक गतिविधि उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं में कुछ मामूली सुधार दिखा रही है, संपत्ति क्षेत्र और बढ़ते लोक ऋण सहित देश-विशिष्ट कमजोरियों के बीच बाहरी मांग कम बनी हुई है। श्रम बाजार में वृद्धि बनी हुई है, लेकिन इसमें नरमी के संकेत दिख रहे हैं, खासकर वेतन वृद्धि के मामले में। कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। साथ ही, बढ़ी हुई श्रम गतिशीलता, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग श्रम उत्पादकता और व्यवसाय निर्माण को बढ़ा रहे हैं। ये घटनाक्रम 29 फरवरी 2024 को साओ पाउलो, ब्राजील में पहली जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के अध्यक्ष के वक्तव्य में प्रतिबिंबित हुए थे, जिसमें कहा गया था कि *"वैश्विक अर्थव्यवस्था में सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना बढ़ गई है, देशों और क्षेत्रों में मतभेदों के बावजूद संवृद्धि में सुदृढ़ता दिख रही है।"*

हेडलाइन और कोर दोनों में मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में स्थिर सेवाओं की कीमतें लक्ष्य के सापेक्ष इसे अभी भी ऊंचा बनाए हुए हैं। अभिसरण में 2025 तक देरी होने की संभावना है। तदनुसार, अधिकांश केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों को स्थिर रख रहे हैं, जबकि यह स्वीकार कर रहे हैं कि अगला कदम संभवतः लैटिन अमेरिका के कई केंद्रीय बैंकों की दिशा में कटौती होगी। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर लगातार नीचे जा रही है या नहीं, इस पर आने वाले डेटा का सावधानीपूर्वक आकलन करने के महत्व पर जोर दे रहे हैं। इससे यह अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है कि प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति रुख को कितने समय तक बनाए रखने की आवश्यकता है। जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित था, जापान ऋणात्मक नीति दरों से बाहर निकल गया। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए चीन में प्रमुख उधार दरों और आरक्षित निधि आवश्यकताओं में बड़ी कटौती की गई है।

केंद्रीय बैंक की लंबे समय से चले आ रहे संकेतों के बावजूद बाजार मौद्रिक नीति की राह में आसन्न गिरावट को लेकर उत्साहित है। हाल ही में, दर में कटौती के सटीक समय को लेकर बाजार की उम्मीदें कम हो गई हैं, हालांकि आने वाले डेटा और नीति टिप्पणियों के साथ उनमें उतार-चढ़ाव जारी है। जनवरी रीडिंग तक मुद्रास्फीति की संख्या ने बाजार सहभागियों को 2024 में व्यापक दर में कटौती पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। फिर भी, बाजार के केंद्रीय बैंकों से आगे निकलने के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिससे बाजार में अचानक हलचल हो सकती है।

प्रमुख एई में सरकारी बांड का प्रतिफल जनवरी 2024 में अपने निचले स्तर से बढ़ गया है, आंशिक रूप से केंद्रीय बैंक के संकेतों के कारण प्रारंभिक दर में कटौती की उम्मीदों को पीछे

---

* यह आलेख माइकल देवब्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, शाहबाज़ खान, विश्वजीत मोहंती, खुशी सिन्हा, कुणाल प्रियदर्शी, हर्षिता केशान, रमेश कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, हरेंद्र बेहेरा, अरिजीत शिवहरे, सुगंती डी, विजया अग्रवाल, आकाश राज, देबप्रिया साहा, शिवम, शैलजा भाटिया, शेषाद्रि बनर्जी, कार्तिकेय भार्गव, दिलप्रीत शर्मा, अवनीश कुमार, कमल गुप्ता, अंजलि मारिया जोस, शुभम अग्निहोत्री, प्रियंका सचदेव, अक्षरा अवस्थी, विनीत कुमार श्रीवास्तव, समीर रंजन बेहरा और रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

धकेल दिया गया है। फिर भी, बांड की कीमतें अभी भी केंद्रीय बैंकों की तुलना में अधिक नरम मूल्यांकन दर्शाती हैं। फिर भी, सार्वजनिक ऋण का बढ़ता स्तर बांड सतर्कता के पुनरुत्थान के लिए संभावना प्रदान कर सकता है जो बाद में बाजार को क्रूर बिकवाली में बदल सकता है। वास्तव में, बांड बाजार की अस्थिरता इक्विटी बाजार की अस्थिरता से अधिक हो गई है। पृष्ठभूमि में, मात्रात्मक सख्ती (क्यूटी) चुपचाप काम कर रही है, जिससे वित्तीय स्थितियों को अत्यधिक आसान बनाने और बड़े घाटे से जूझ रहे केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट को सहारा देने में मदद मिल रही है। कॉर्पोरेट स्प्रेड और अधिक संकुचित हो गया है। निजी इक्विटी बायआउट कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले बांड और ऋण के साथ निजी क्रेडिट बाजारों में जुटाए गए ऋण को पुनर्वित्त करके कॉर्पोरेट बांड बाजारों में सुधार और ब्याज लागत पर बचत का लाभ उठा रही हैं। मौद्रिक सहजता की संभावना, बड़े कॉरपोरेट्स की मजबूत लाभप्रदता और एआई से संबंधित प्रत्याशित उत्पादकता लाभ के कारण शेयर बाजारों और अधिक आम तौर पर जोखिमपूर्ण संपत्तियों में तेजी आई है।

विदेशी मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर में बढ़त हुई है, जो आंशिक रूप से 2023 के अंत में देखी गई कमजोरी को उलट रहा है, क्योंकि दर में कटौती की उम्मीदों को पीछे धकेल दिया गया है। यूरो और येन कमजोर हुए हैं। ईएमई को बांड द्वारा संचालित, उत्साहपूर्ण पोर्टफोलियो प्रवाह जारी है। ईएमई स्टॉक हालिया घाटे को मिटाने के लिए तैयार हैं, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) ईएम इंडेक्स 2023 के करीब कारोबार कर रहा है। लाभ प्रौद्योगिकी शेयरों द्वारा संचालित हो रहा है। निरंतर भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने भंडार को फिर से समायोजित करने की मांग और स्थिर मुद्रास्फीति सुरक्षित आश्रय की तलाश में सोने की कीमतों को बढ़ा रही है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 1 मार्च को कुछ वृद्धिशील परिणामों के साथ अबू धाबी में संपन्न हुआ, जो राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीतियों की ओर ध्यान में बदलाव को दर्शाता है। सदस्यों ने फिलहाल डिजिटल उत्पादों पर शुल्क नहीं लेने का फैसला किया। डब्ल्यूटीओ में सेवाओं पर घरेलू नियमों पर एक नया बहुपक्षीय समझौता अपनाया गया। 72 देश बहुपक्षीय समझौते का हिस्सा हैं। भारत सहित कई देश इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि यह डब्ल्यूटीओ के बहुपक्षीय व्यापार ढांचे और इसलिए इसकी वैधता को कमजोर कर सकता है। कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी और विवाद निपटान सुधारों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा को अवरुद्ध कर दिया गया था क्योंकि यह एक गैर-व्यापार मुद्दा है और डब्ल्यूटीओ के बहुपक्षीय व्यापार ढांचे के अधिदेश से बाहर है।

इस सदी के अंत तक, दुनिया के लगभग हर देश की जनसंख्या कम हो सकती है। स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति और गरीबी में गिरावट के कारण लोग अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी कम हो रहे हैं। पिछली आधी सदी में वैश्विक प्रजनन दर[1] आधी होकर 2.3 हो गई है। हालाँकि, अधिकांश एई में प्रजनन दर 2.1[2] की प्रतिस्थापन दर से नीचे गिर गई है, जिसके परिणामस्वरूप कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट आई है, जिसके महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं। विकासशील देश भी इसी तरह नीचे की ओर जा रहे हैं। प्रजनन दर में दीर्घकालिक गिरावट, महिला श्रम शक्ति में बढ़ती भागीदारी और शिक्षा, बेहतर कल्याण प्रणाली और कम बचपन मृत्यु दर जैसे सामाजिक-आर्थिक रुझानों का परिणाम है। यह उच्च पालन-पोषण लागत का भी प्रतिबिंब है, जिसमें आर्थिक व्यय या ख़ाली समय में बच्चे की देखभाल की अवसर लागत भी शामिल है। गिरती जन्म दर का असर सिकुड़ती कार्यबल पर पड़ने वाली वृद्ध आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा और पेंशन खर्च का अधिक बोझ होगा, जिससे सार्वजनिक वित्त पर अधिक कर और दबाव पड़ेगा। हालाँकि कुछ देश प्रसव-प्रोत्साहन नीतियां अपना रहे हैं, लेकिन जन्मों में गिरावट लाने वाली आर्थिक और सामाजिक ताकतों के दीर्घावधि में उलट होने की संभावना नहीं है। आप्रवासन एक समाधान हो सकता है, लेकिन राजनीति कठिन बनी हुई है। इसके बजाय, पुराने कर्मचारियों, एआई और ऑटोमेशन को कम युवा लोगों द्वारा पैदा की गई सुस्ती को उठाना होगा।

भारत में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के

1 प्रति महिला जन्मों की कुल संख्या।

2 प्रतिस्थापन दर समय के साथ जनसंख्या को समान स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रजनन दर है। इस दर पर, मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है।

फरवरी 2024 के अंत में जारी डेटा ने जोरदार उलटफेर किया। अक्टूबर-दिसंबर 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद छह-तिमाही की उच्च दर पर विस्तारित हुआ, जो मजबूत गति, मजबूत अप्रत्यक्ष करों और कम सब्सिडी द्वारा संचालित था। जनवरी-मार्च 2024 (धारा III) के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का हमारा पूर्वानुमान चौथी तिमाही के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन में देखा गया है, जो बताता है कि पूरे वर्ष 2023-24 के लिए एनएसओ का अनुमान पार हो जाएगा और दर 8 प्रतिशत के करीब होगी। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) उत्साहजनक मांग स्थितियों, प्रौद्योगिकी में बढ़ते निवेश, दक्षता लाभ और अनुकूल बिक्री वृद्धि को दर्शाते हैं। व्यावसायिक विश्वास का समग्र स्तर निकट अवधि की संभावनाओं के बारे में मजबूत आशावाद की ओर इशारा करता है।

2023-24 की तीसरी तिमाही में कुल मांग निवेश-प्रेरित थी, जिसमें निजी पूंजीगत व्यय चक्र के पुनरुत्थान के कुछ संकेत थे। कई क्षेत्रों में क्षमता उपयोग उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां नए निवेश की आवश्यकता है। संरचनात्मक मांग की उच्च दृश्यता और स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट संभावित रूप से प्रेरक शक्तियाँ होंगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं ने फरवरी 2024 तक वर्ष 2023-24 के लिए अपने संयुक्त पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 92 प्रतिशत हासिल कर लिया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे अधिक लंबाई के साथ-साथ चार-लेन सड़कों का निर्माण होने की संभावना है - गति या पहुंच-नियंत्रित राजमार्ग - 2037 तक एक विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क बनाने की दिशा में।

कुल मांग का सबसे बड़ा खंड - निजी अंतिम उपभोग व्यय - तीसरी तिमाही त्योहारी सीज़न के साथ पड़ने के बावजूद कम रहा। इसके अलावा, तिमाही के दौरान सरकारी अंतिम खपत में गिरावट आई। बाजार अनुसंधान से संकेत मिलता है कि घरेलू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र में अगले छह महीनों में मध्यम वृद्धि का अनुभव हो सकता है। दूसरी ओर, प्रीमियम उपभोक्ता व्यवसायों के लिए मांग का दृष्टिकोण मजबूत है और मध्यम अवधि में संवृद्धि की लय बनी रहने की उम्मीद है। इससे पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। छोटे शहरों में अवसरों के कारण जीवनशैली क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि हो रही है, और इन बाजारों में प्रवेश करने वाली कंपनियां प्रथम-प्रवर्तक होने का लाभ उठा रही हैं। नए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) की जानकारी से पता चलता है कि टिकाऊ वस्तुओं और विवेकाधीन उत्पादों पर प्रति व्यक्ति खर्च ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में बढ़ रहा है, 2011-12 के बाद से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 4 प्रतिशत (धारा III, बॉक्स बी) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से 1.5 गुना बढ़ गई है। वर्ष की पिछली तिमाहियों की तुलना में निवल निर्यात में कमी आई है।

आउटपुट पक्ष पर, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार दोहरे अंकों में हुआ, जो कि इनपुट लागत में गिरावट के कारण कॉर्पोरेट्स की निरंतर उच्च लाभप्रदता को दर्शाता है। इंडिया इंक का ब्याज कवरेज अनुपात - ब्याज और कर से पहले की कमाई (ईबीआईटी) को ब्याज व्यय से विभाजित किया गया - अक्टूबर-दिसंबर 2023 में लगातार तीसरी तिमाही में विस्तारित हुआ, कच्चे माल की कीमतों और लागत दक्षता में नरमी से मदद मिली, भले ही टॉपलाइन वृद्धि मध्यम रही।[3] कंपनियां ऑटोमोबाइल, सीमेंट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, आतिथ्य, तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और बिजली सहित कई क्षेत्रों में ब्याज कवरेज अनुपात में सुधार हुआ है। विनिर्माण आधार का भी विस्तार हो रहा है। उदाहरण के लिए, संपूर्ण सेमीकंडक्टर चिप मूल्य श्रृंखला - डिज़ाइन; पैकेजिंग और फैब्रिकेशन- ने देश में अपनी उपस्थिति बना ली है।

निर्माण गतिविधि मजबूत रही। सेवाओं ने महामारी से पहले की प्रवृत्ति की वृद्धि दर को बनाए रखा, कई घटकों ने क्रमिक रूप से गति पकड़ी। महामारी से प्रेरित अंतराल के बाद कॉर्पोरेट यात्रा फिर से शुरू होने के साथ, आतिथ्य उद्योग को एक स्वस्थ राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, जो औसत दरों (एआरआर) में 5-7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि और 73-74 प्रतिशत की अधिभोग द्वारा बढ़ी है। इस बीच, खुदरा क्षेत्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, घरेलू ब्रांड तेजी से परिचालन बढ़ा रहे हैं। 2023 में, भारत के शीर्ष आठ शहरों में खुदरा पट्टे कुल 7.1 मिलियन वर्ग फुट थे, जिसमें घरेलू ब्रांडों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत थी। ग्रेड ए मॉल

[3] द इकॉनॉमिक टाइम्स, 13 मार्च 2024।

का परिचालन खुदरा स्थान 68.3 मिलियन वर्ग फुट का है और निर्माणाधीन क्षमता में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के पुनरुत्थान ने भी ग्रेड ए कार्यालयों की मांग को मजबूती से विस्तार करने में मदद की है। समग्र पट्टे में उच्च कर्षण ने इस खंड में सूचीबद्ध कंपनियों के प्रदर्शन में सहायता की है।

दूसरी ओर, कृषि और संबद्ध गतिविधियों से उत्पादन अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान संकुचन में चला गया क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की कमी के कारण खरीफ की फसल प्रभावित हुई और चारे की कमी ने पशुधन क्षेत्र को प्रभावित किया। हालाँकि, आगे देखते हुए, कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ अपेक्षित हैं। विभिन्न वैश्विक मौसम मॉडल भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जून तक ला नीना स्थापित हो जाएगा और आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम से पहले अल नीनो निष्क्रिय हो जाएगा। इन राष्ट्रीय आय घटनाक्रमों का संपूर्ण विवरण और विश्लेषण खंड III में प्रस्तुत किया गया है।

इसके बाद, एनएसओ तीसरे संशोधित अनुमान को हटाकर जीडीपी के छह के बजाय पांच अनुमान प्रदान करेगा। अंतिम पुनरीक्षण तीन के बजाय वित्तीय वर्ष पूरा होने के दो वर्ष बाद जारी किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, 29 फरवरी 2024 को जारी किया गया 2021-22 का नंबर अंतिम है और 2022-23 का अंतिम नंबर 2025 में जारी किया जाएगा। त्रैमासिक रिलीज कैलेंडर अपरिवर्तित रहता है।

वास्तविक क्षेत्र के इन घटनाक्रमों के कारण वित्तीय बाज़ार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रुक-रुक कर होने वाले सुधारों के बावजूद, व्यापक आधार वाली तेजी के कारण स्टॉक तेजी के बाजार में चल रहे हैं। जबकि लार्ज कैप बढ़ रहे हैं, मिड और स्मॉल-कैप और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में एक दशक में सबसे छोटी हिस्सेदारी (16.3 प्रतिशत) है, जो म्यूचुअल फंड सहित घरेलू संस्थानों की बढ़ी हुई खरीदारी को दर्शाता है।[4] भारतीय रुपये में बढ़ोतरी हो रही है और यह सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक है। अक्टूबर-दिसंबर 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष-दर-वर्ष 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी से भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। जनवरी 2024 में सौदे के मूल्य के संदर्भ में विलय और अधिग्रहण में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल-मध्य मार्च 2023-24 के दौरान पोर्टफोलियो प्रवाह ईएमई में ऐसे सभी प्रवाह का पांचवां हिस्सा था। बॉन्ड प्रतिफल 9 महीने के निचले स्तर पर है। कॉरपोरेट बॉन्ड बेहतर कट-ऑफ के साथ मजबूत मांग में हैं। वैश्विक बांड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बांडों को शामिल करने से भारत में निवेश चाहने वाले बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए ऑफशोर रुपया-मूल्य वाले बांडों की मजबूत मांग बढ़ रही है।

इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी) द्वारा वित्त पोषित वर्ल्ड डेटा लैब द्वारा विश्व पॉवर्टी क्लॉक के नवीनतम वास्तविक समय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अपनी 3 प्रतिशत आबादी को अत्यधिक गरीबी से ऊपर लाया है। 'एस्केप रेट' दुनिया में गरीबी में कमी की वर्तमान दर की गणना करता है, जिसमें सीमा आय के रूप में प्रति दिन 2.15 अमेरिकी डॉलर लिया जाता है। ये निष्कर्ष पहले उद्धृत एचसीईएस 2022-23 में भी परिलक्षित होते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल करता है। घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में दिया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जबकि अंतिम खंड में निष्कर्ष टिप्पणियाँ दी गई हैं।

II. वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भू-राजनीतिक तनाव, अस्थिर वित्तीय स्थितियों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति से घिरा हुआ है। हमारा मॉडल-आधारित नाउकास्ट ति1:2024 (चार्ट II.1) के दौरान वैश्विक संवृद्धि की गति में गिरावट की ओर इशारा करता है।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) में फरवरी 2024 में और वृद्धि देखी गई, जो इसे अपने ऐतिहासिक औसत (चार्ट II.2ए) से ऊपर था। भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक भी फरवरी में 19 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया,

[4] बिजनेस स्टैंडर्ड, 4 मार्च 2023।

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक पूर्वानुमान (ति-द-ति)

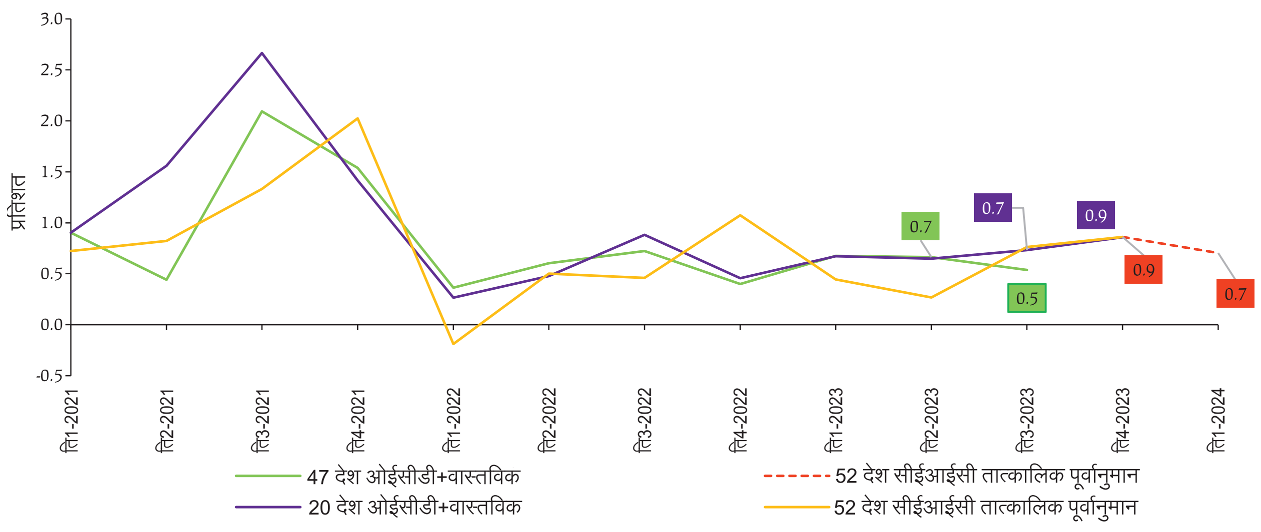

स्रोत: सीईआईसी; ओईसीडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

जिसका मुख्य कारण साइबर हमलों के बढ़ते दायरे, पैमाने और परिष्कार, गाजा में चल रहे युद्ध से प्रेरित मध्य पूर्व में तनाव और ताइवान पर अमेरिका-चीन तनाव के बढ़ने की संभावना (चार्टII.2बी) से उत्पन्न होने वाले जोखिम थे।[5] लाल सागर में चल रही शत्रुता के कारण कंटेनर शिपिंग की लागत में तेजी आई है, जिससे एक प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग में व्यवधान पैदा हुआ है और फरवरी में भी यह उच्च स्तर पर बना रहा, हालांकि क्रमिक गिरावट (चार्ट II.2सी) रही।

यू.एस. और यू.के. में उपभोक्ता भावनाएँ कम हुईं, लेकिन यूरो क्षेत्र में सुधार हुआ जहाँ रोजगार की उम्मीदें मोटे तौर पर

चार्ट II.2: आपूर्ति शृंखला दबाव और भू-राजनीतिक जोखिमों में प्रवृत्तियां

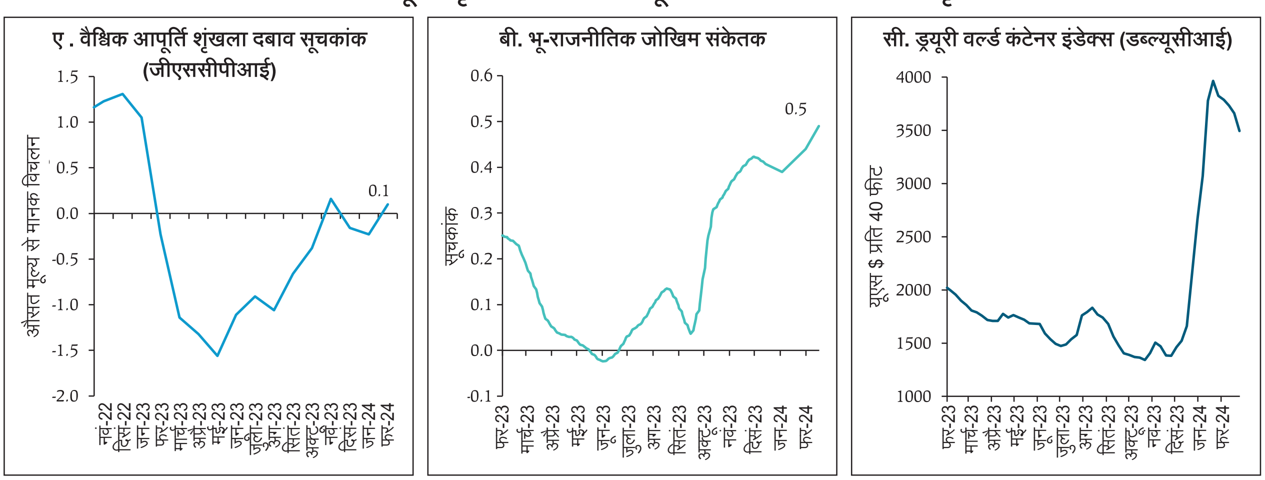

टिप्पणियाँ: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों से संबंधित डेटा दर्शाता है।
2. डब्ल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों को इंगित करता है। समग्र डाटा मात्रा के हिसाब से 8 शिपिंग मार्गों के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है और प्रति 40-फुट कंटेनर यूएसडी में सूचित करता है।

स्रोत: फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, जनवरी 2024; और ब्लूमबर्ग।

[5] ब्लैकरॉक जियोपॉलिटिकल रिस्क डैशबोर्ड, 23 फरवरी, 2024।

चार्ट II.3: उपभोक्ता अभिमत और वित्तीय स्थितियां

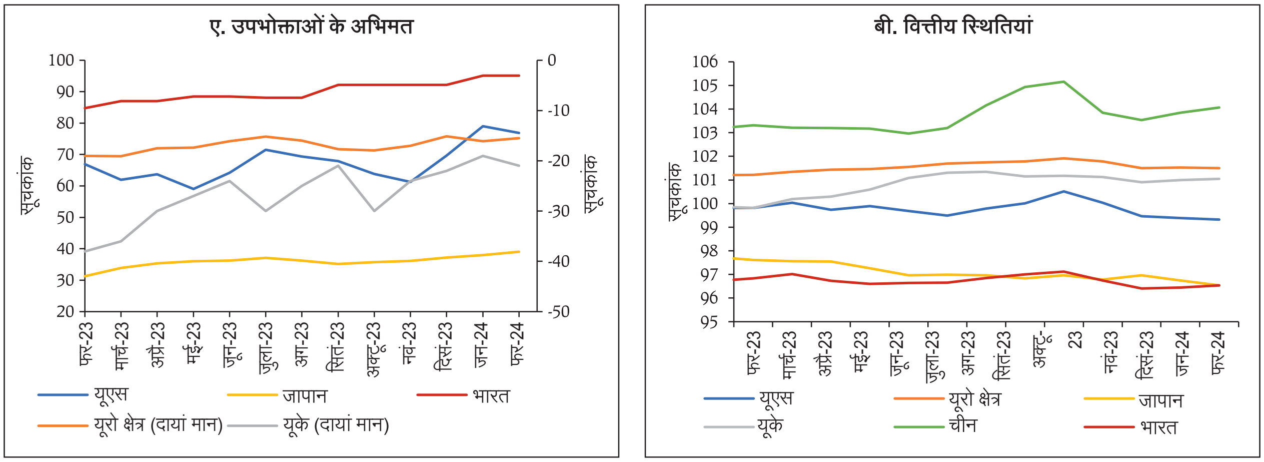

टिप्पणियां : 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरोज़ोन और यूके: (-)100 आत्मविश्वास की अत्यधिक कमी, 0 तटस्थता और 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और अमेरिका: मूल्य जितना अधिक होगा, उपभोक्ता का विश्वास उतना अधिक होगा।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

स्थिर रहीं। केंद्रीय बैंकों द्वारा नीति में जल्द ढील दिए जाने की उम्मीदों को संशोधित करने के कारण भौगोलिक क्षेत्रों में वित्तीय स्थितियाँ कठिन रहीं (चार्ट II.3)।

वैश्विक समग्र पीएमआई फरवरी 2024 में बढ़कर 52.1 हो गया - जो जून 2023 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है-जनवरी में 51.8 से। सर्वेक्षण में शामिल सभी छह उप-क्षेत्रों - व्यावसायिक सेवाएँ; उपभोक्ता वस्तुएँ और सेवाएँ; वित्तीय सेवाएँ; मध्यवर्ती वस्तुएँ; और निवेश वस्तुएँ - ने मई 2023 के बाद पहली बार एक साथ उत्पादन में वृद्धि दर्ज की। व्यावसायिक गतिविधि में वृद्धि की तेज़ दर के कारण फरवरी में सेवा पीएमआई बढ़कर 52.4 के सात महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गई। 18 महीनों तक लंबे समय तक संकुचन के बाद, नए ऑर्डर, उत्पादन और खरीद के स्टॉक के कारण फरवरी में विनिर्माण पीएमआई 50.3 पर वापस विस्तार क्षेत्र में आ गया (चार्ट II.4)।

फरवरी 2024 में निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई बढ़कर 49.6 हो गया, जो इसके विनिर्माण घटक के 19 महीने के उच्चतम 49.4 पर पहुंचने से प्रेरित था। इस बीच, सेवा निर्यात ऑर्डर सूचकांक विस्तार क्षेत्र में मामूली रूप से घटकर 50.4 पर आ गया (चार्ट II.5)।

कृषि उत्पादों, विशेष रूप से अनाज की कीमतों में गिरावट के कारण फरवरी में वैश्विक गैर-तेल वस्तुओं की कीमतों में नरमी आई, जिसके कारण ब्लूमबर्ग कमोडिटी मूल्य सूचकांक में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई (माह-दर-माह) [चार्ट II.6ए]। हालाँकि, फरवरी में कच्चे तेल की कीमतों में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि ओपेक+ सदस्यों ने तेल उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती को जून 2024 के अंत तक बढ़ा दिया, हालांकि वे मार्च 2024 के अंत

चार्ट II.4 : वैश्विक पीएमआई

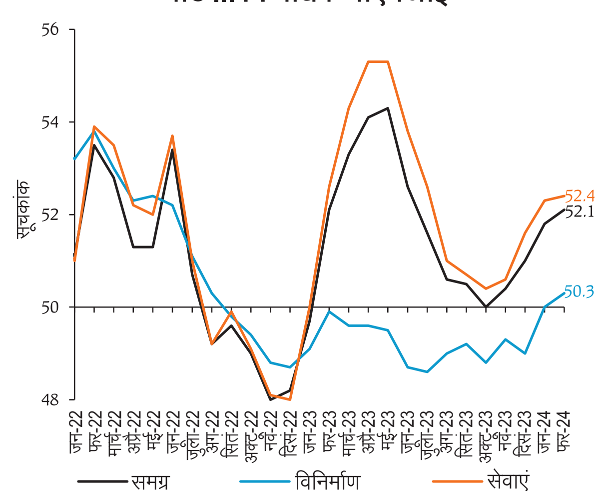

नोट : 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार तथा इसके विपरीत स्थिति को दर्शाती है।
स्रोत : एस एंड पी ग्लोबल

चार्ट II.5 : वैश्विक पीएमआई : निर्यात आदेश

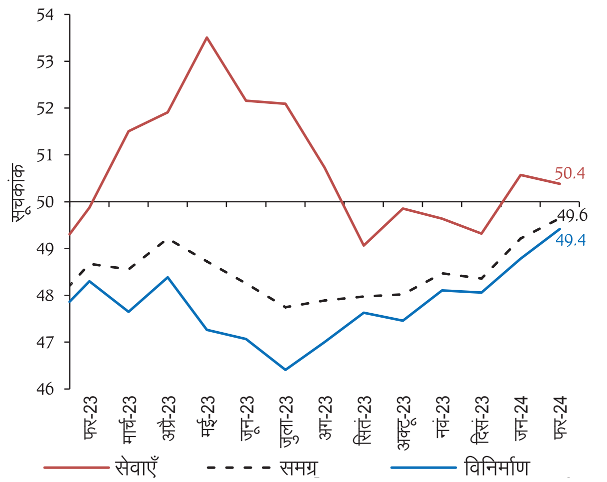

नोट : 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार तथा इसके विपरीत स्थिति को दर्शाती है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

में समाप्त होने वाले थे (चार्ट II.6बी)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में फरवरी में 0.7 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से अनाज (-5.0 प्रतिशत) और वनस्पति तेलों (-1.3 प्रतिशत) की कीमतों में कमी के कारण हुआ। सूचकांक एक वर्ष पहले के इसी मूल्य से 10.2 प्रतिशत नीचे था (चार्ट II.6सी)। फरवरी में सोने की कीमतें अस्थिर रहीं और मार्च में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई (चार्ट II.6डी)।

हेडलाइन मुद्रास्फीति ने प्रमुख एई में धीरे-धीरे नरमी जारी रखी, जो कई देशों में लक्ष्य के करीब पहुंच गई। हालाँकि, अमेरिका में, मुख्य रूप से मोटर बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं की मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2024 में 3.2 प्रतिशत हो गई। हेडलाइन व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 2.6 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2024 में 2.4 प्रतिशत हो गई, जो लगभग तीन वर्षों में सबसे कम है। फ्लैश अनुमान के अनुसार, फरवरी में यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति घटकर 2.6 प्रतिशत हो गई। जनवरी में 2.8 प्रतिशत से (चार्ट II.7ए)। यूके में, सीपीआई

चार्ट II.6: पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें

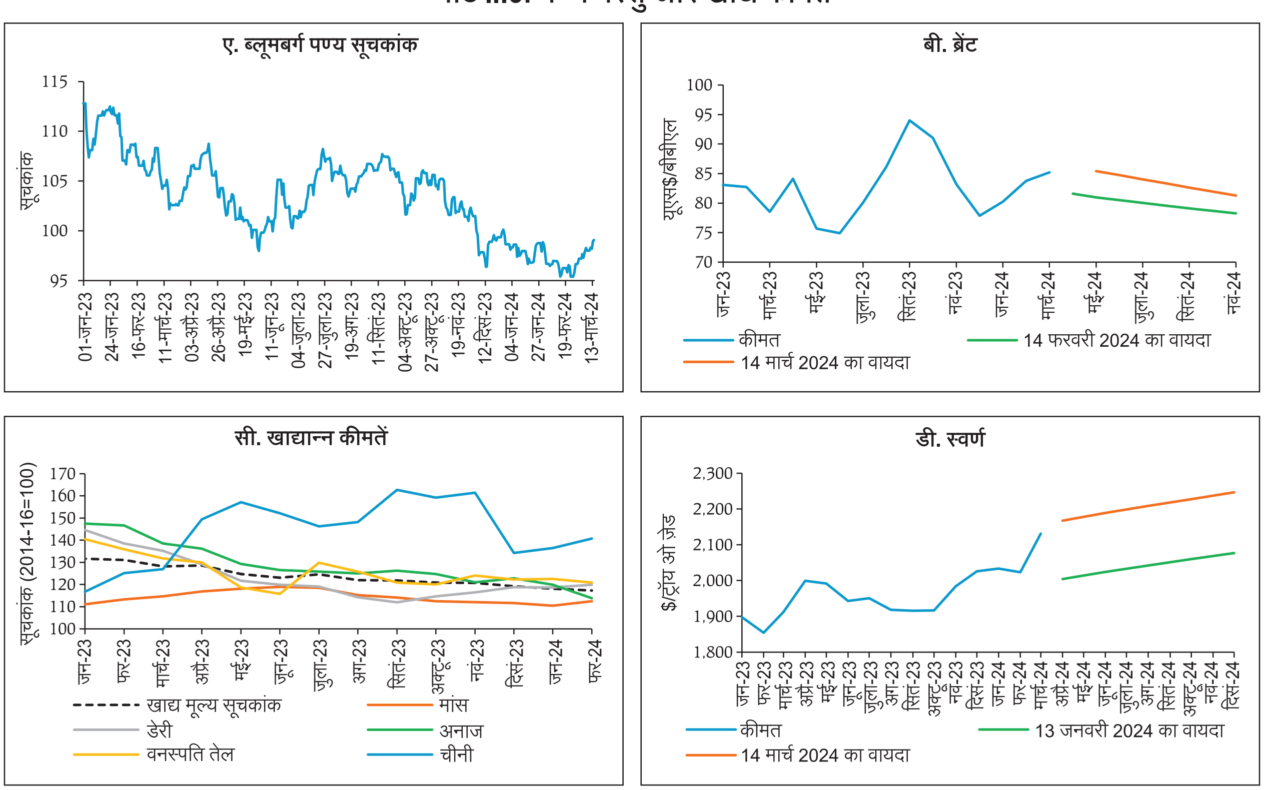

स्रोत: ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

मुद्रास्फीति जनवरी में 4.0 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि जापान की मुद्रास्फीति (ताजा भोजन को छोड़कर) जनवरी में दिसंबर में 2.3 प्रतिशत से कम होकर 2.0 प्रतिशत हो गई।

ईएमई के बीच, दक्षिण अफ्रीका में जनवरी में और रूस में फरवरी में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि ब्राजील में मुद्रास्फीति फरवरी में लगातार दूसरे महीने स्थिर रही (चार्ट II.7बी)। हालाँकि, चीन में, चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान भारी खर्च के कारण जनवरी में 0.8 प्रतिशत की अपस्फीति से फरवरी में मुद्रास्फीति बढ़कर 0.7 प्रतिशत हो गई - 11 महीनों में इसका उच्चतम स्तर। प्रमुख एई में कोर और सेवाओं की मुद्रास्फीति कम हुई लेकिन हेडलाइन मुद्रास्फीति (चार्ट II.7सी और II.7डी) से अधिक रही।

प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों की तीखी टिप्पणियों के कारण महीने की शुरुआत में भावनाओं में कुछ गिरावट के बावजूद फरवरी में वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी आई। एमएससीआई विश्व इक्विटी सूचकांक फरवरी में 4.2 प्रतिशत बढ़ गया, जो एई (4.1 प्रतिशत) में बढ़त को दर्शाता है क्योंकि कमाई उम्मीद से अधिक मजबूत साबित हुई, जिसमें 'मैग्नीफिसेंट 7'[6] (चार्ट II.8ए) भी शामिल है। फरवरी में ईएमई के लिए एमएससीआई में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, चीन में मजबूत रैली, शॉर्ट सेलिंग पर नए नियम और ईएमई में पूंजी प्रवाह में वृद्धि।

यूएस जी-सेक प्रतिफल, 10-वर्षीय और 2-वर्षीय दोनों, फरवरी में 7 बीपीएस (चार्ट II.8बी) के प्रसार में वृद्धि के साथ बढ़ी। मुद्रा बाजारों में, फरवरी में अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.9 प्रतिशत (माह-दर-माह) मजबूत हुआ। दूसरी ओर, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक फरवरी में अपेक्षाकृत स्थिर रहा (चार्ट II.8सी और II.8डी)।

दुनिया भर में, केंद्रीय बैंक अवस्फीति के अंतिम पड़ाव पर चलते समय सतर्क रहते हैं, खासकर एई में। अधिकांश एई

चार्ट II.7: मुद्रास्फीति - एई और ईएमई

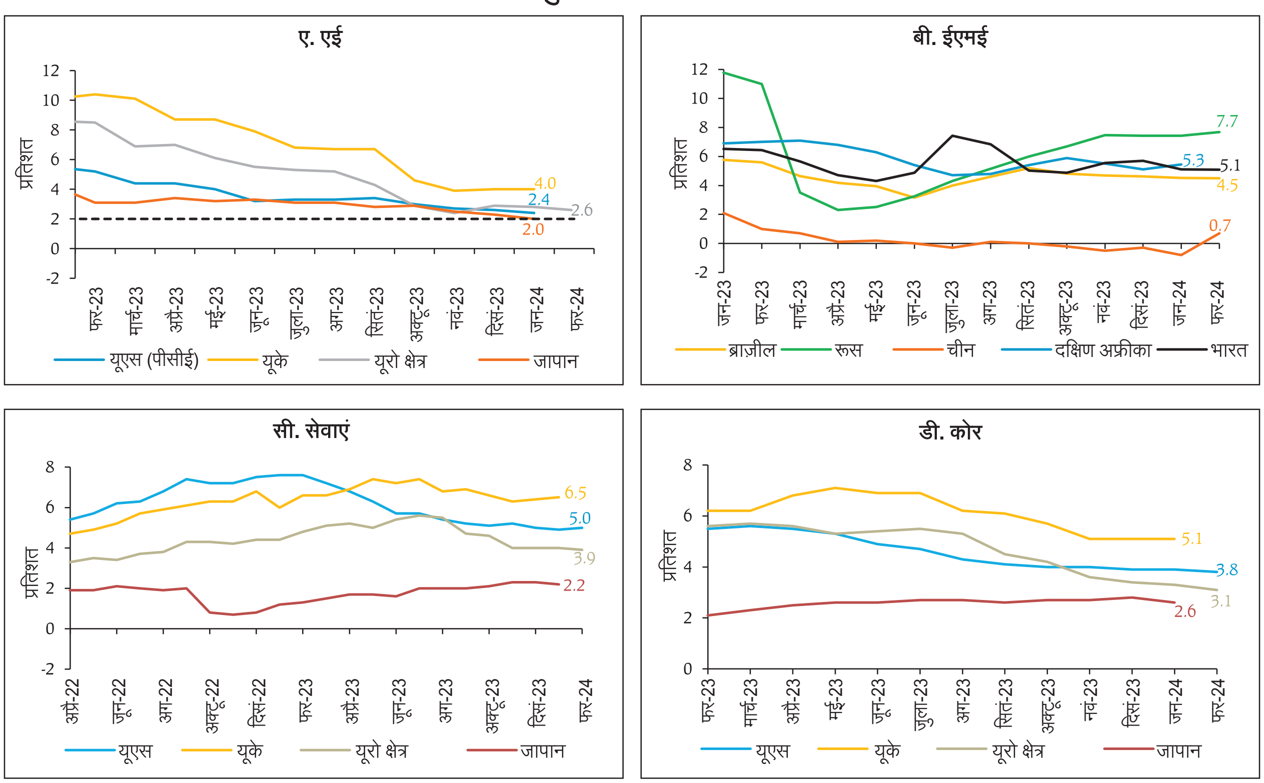

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

6 मैग्निफ़िसेंट 7 स्टॉक ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल पैरेंट अल्फाबेट, अमेज़ॅन, एनवीडिया, मेटा प्लेटफ़ॉर्म और टेस्ला को संदर्भित करते हैं।

चार्ट II.8 वैश्विक वित्तीय बाजार

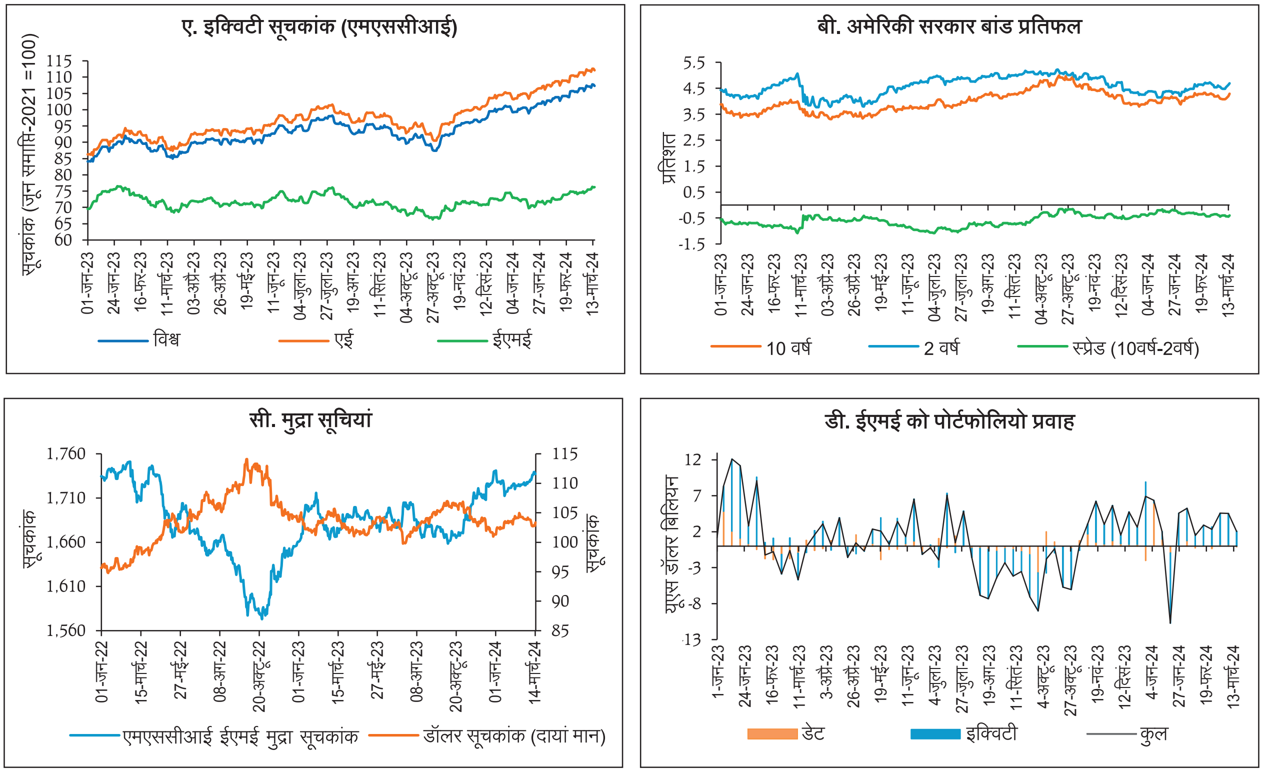

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

केंद्रीय बैंकों ने अपनी नवीनतम बैठकों में अपनी नीतिगत दरें स्थिर रखीं (चार्ट II.9ए)। हालाँकि, कई ईएमई केंद्रीय बैंकों ने अपना आसान रास्ता जारी रखा जो 2023 के अंत में शुरू हुआ (चार्ट II.9बी)।

चार्ट II.9: नीति दरों में परिवर्तन

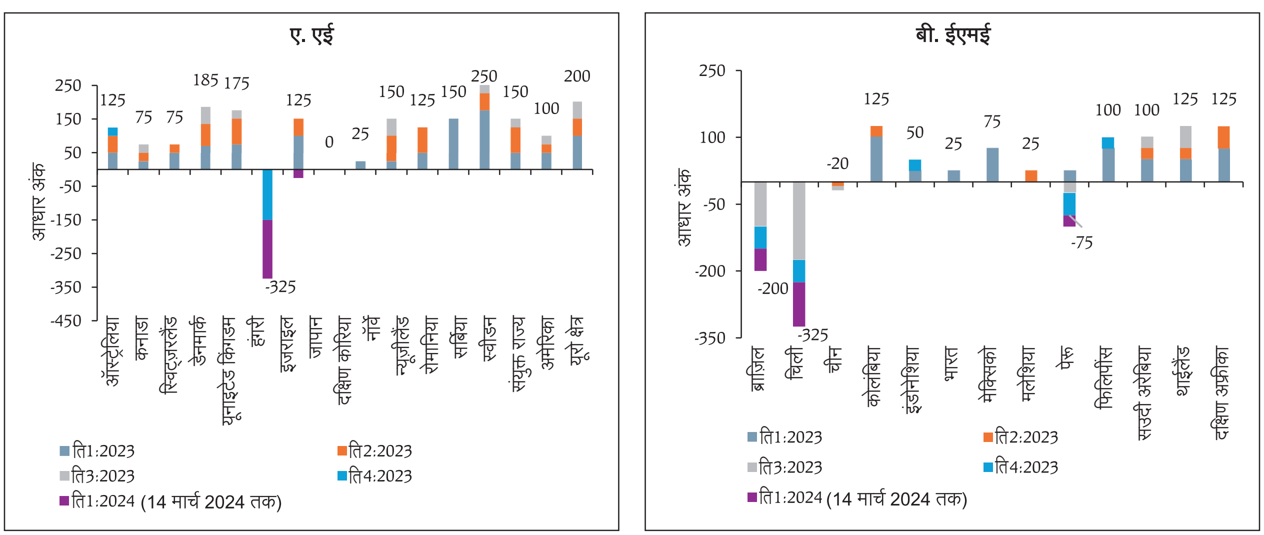

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहले वर्णित आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के रूप में बाहरी प्रतिकूलताओं के बीच मजबूत वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.1ए)। जनवरी में थोड़ी नरमी देखने के बाद फरवरी 2024 में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई और 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अब 7.2 प्रतिशत (चार्ट III.1बी और III.1सी) है।

अगले वर्ष की ओर देखते हुए, इन-हाउस डायनेमिक स्टोचैस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम (डीएसजीई) मॉडल[7] के अनुमानों से पता चलता है कि 2024-25 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4 प्रतिशत पर मजबूत रहने की संभावना है।[8] इस दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2024-25, 2023-24 के लिए अनुमानित 5.4 प्रतिशत से कम, जिसमें अधिकांश गिरावट छमाही1:2024-25 में हुई (सारणी III.1 और चार्ट III.2)।

सारणी III.1 : आधारभूत अनुमान

(व-द-व प्रतिशत में)

अवधि	जीडीपी संवृद्धि	सीपीआई मुद्रास्फीति
ति1:2024-25	8.1	4.7
ति2:2024-25	6.6	4.4
ति3:2024-25	8.0	4.3
ति4:2024-25	7.1	4.3
वित्त वर्ष 2024-25	**7.4**	**4.4**

कुल मांग

29 फरवरी 2024 को एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) ने 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रखी - पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) से 30 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी)। संशोधन मोटे तौर पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में 10 बीपीएस से 10.3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी और एफएई में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से एसएई में सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के निवल निर्यात से कम दबाव से उत्पन्न होता है।

ति3:2023-24 के दौरान, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछली तिमाही के 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 8.4 प्रतिशत और ति3:2022-23 में 4.3 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण खपत में

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी संवृद्धि तत्कालिक पूर्वानुमान

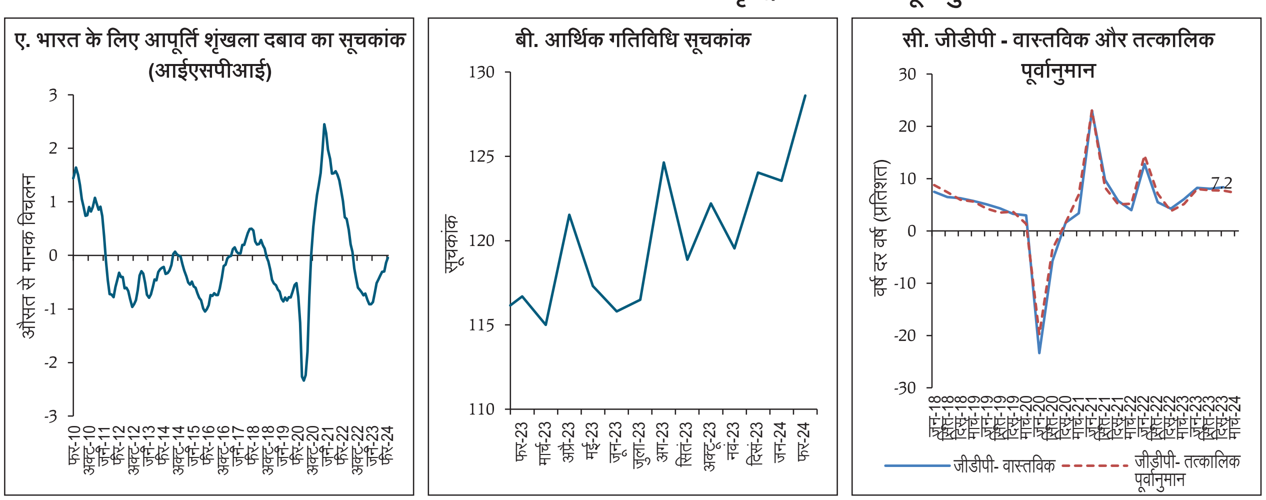

नोट: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्तियों को लेते हुए किया गया। ईएआई फरवरी 2020 में 100 तक बढ़ गया और अप्रैल 2020 में 0 था जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।
स्रोत: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

7 कार्यप्रणाली पर विवरण के लिए, शेषाद्रि बनर्जी, हरेंद्र बेहेरा और माइकल देवब्रत पात्र (2023), "भारत के लिए एक प्रोटोटाइप डायनेमिक स्टोचैस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल", आरबीआई बुलेटिन जुलाई देखें।

8 आधारभूत अनुमानों की गणना 2023-24 और 2024-25 के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और मुद्रास्फीति को मानकर की जाती है, जैसा कि आईएमएफ ने विश्व आर्थिक आउटलुक के जनवरी 2024 के अपडेट और अपरिवर्तित नीति रेपो दर और यूएस फेड फंड दर में चालू और अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत परअनुमान लगाया है।

चार्ट III.2: जीडीपी संवृद्धि का फैन चार्ट और सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान

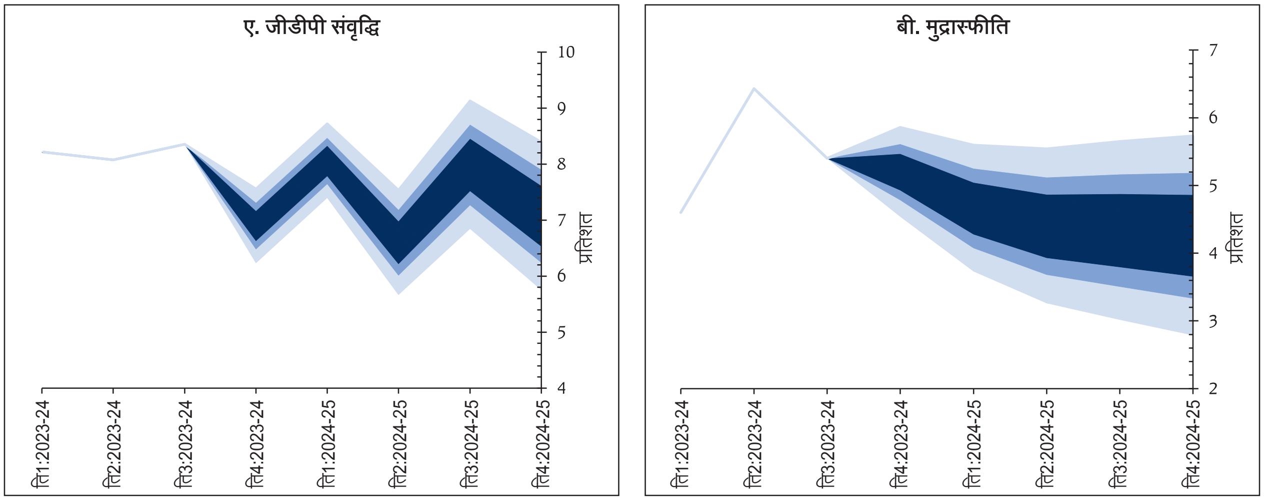

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पुनरुत्थान के नेतृत्व में, 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान निजी खपत की वृद्धि 3.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। जीएफसीएफ ने दोहरे अंक की वृद्धि (10.6 प्रतिशत) दर्ज करना जारी रखा, जो इस्पात खपत और पूंजीगत वस्तु उत्पादन के इसके अनुमानित संकेतकों में प्रतिबिंबित हुआ। कमजोर वैश्विक मांग स्थितियों के बीच निर्यात वृद्धि धीमी रही। निर्यात से अधिक आयात वृद्धि के कारण, बाहरी क्षेत्र ने ति3: 2023-24 में कुल मांग को 1.2 प्रतिशत अंक नीचे कर दिया (चार्ट III.3)।

उच्च आवृत्ति संकेतक फरवरी 2024[9] में घरेलू मांग की स्थिति में निरंतर वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। फरवरी 2024 में ई-वे बिल में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.4ए)। टोल संग्रह में 15.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [चार्ट III.4बी]।

चार्ट III.3 जीडीपी संवृद्धि में भारित योगदान

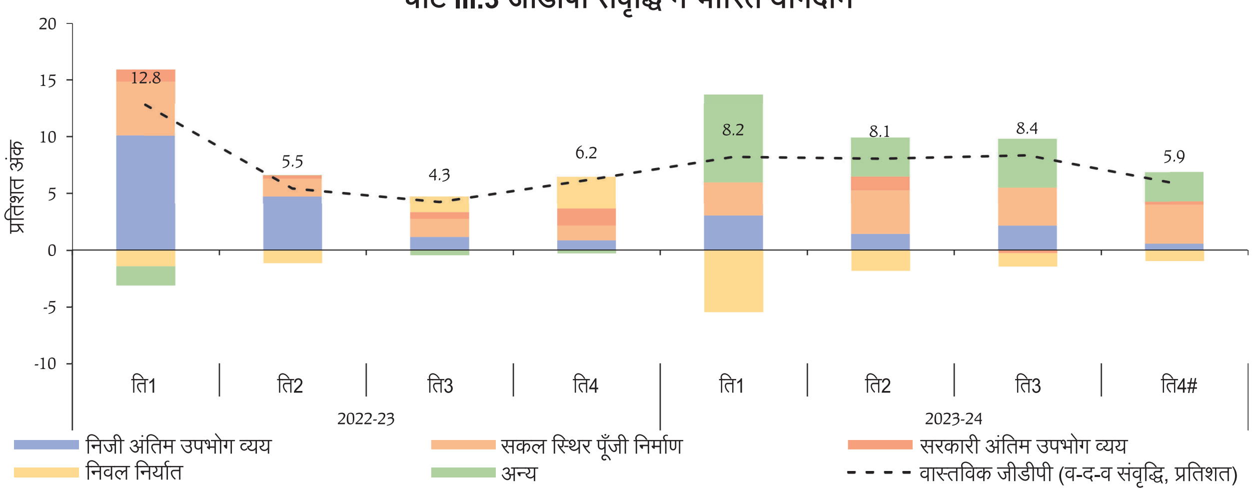

टिप्पणी : 1. अन्य में स्टॉक, मूल्य में परिवर्तन और सांख्यिकीय असंगति शामिल है।
2. # अव्यक्त संवृद्धि।
स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

9 तुलनात्मक उद्देश्य के लिए, फरवरी 2024 के मासिक डेटा को लीप वर्ष प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है। समायोजन (28/29) के गुणज द्वारा किया जाता है।

चार्ट III.4: ई-वे बिल और टोल वसूली

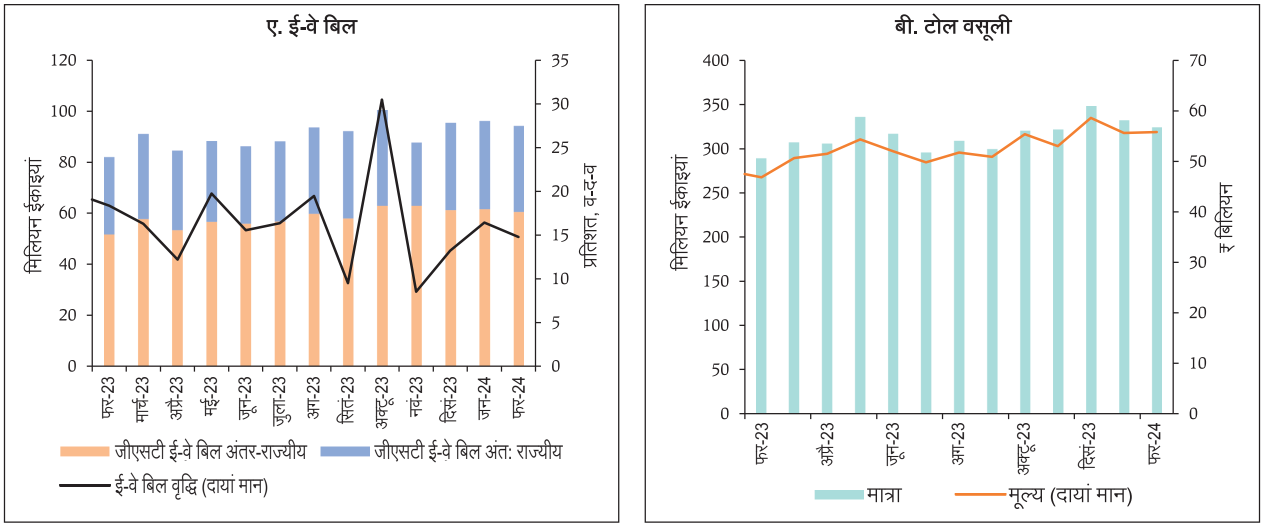

स्रोत: जीएसटीएन; और आरबीआई।

फरवरी 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 24.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व दोपहिया वाहनों और यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि (चार्ट III.5ए) से हुआ। जबकि ट्रैक्टर निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, घरेलू बिक्री धीमी रही

चार्ट III.5 ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक

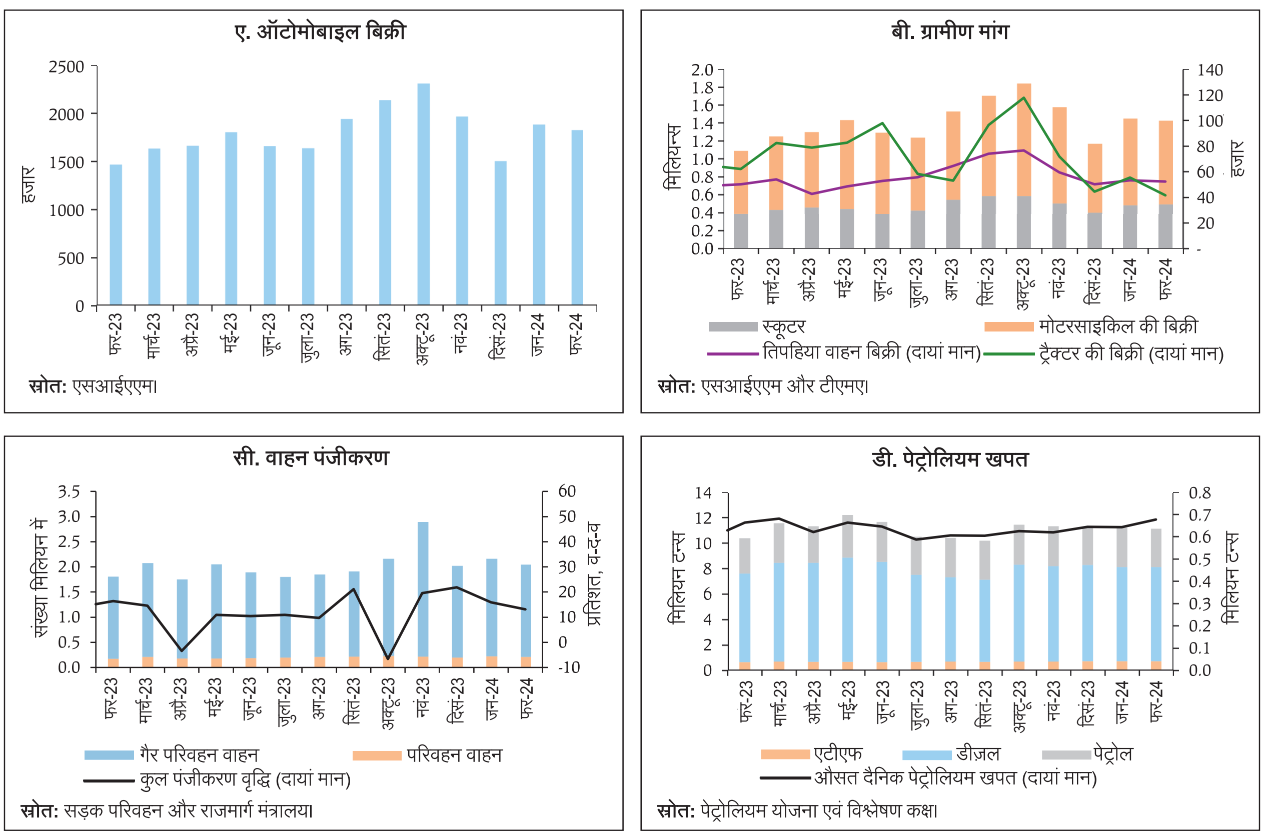

चार्ट III.6 : खुदरा बिक्री वृद्धि

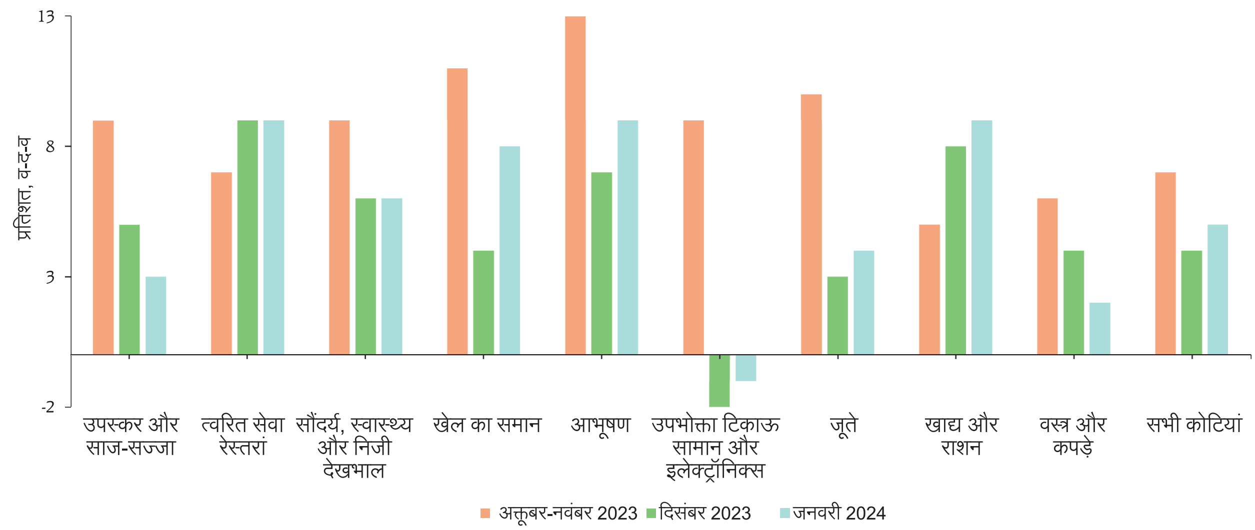

स्रोत : रिटेलर एसोसियेशन ऑफ इंडिया।

(चार्ट III.5बी)। फरवरी में वाहन पंजीकरण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.5सी)। औद्योगिक और परिवहन गतिविधि में निरंतर गति के कारण औसत दैनिक पेट्रोलियम खपत में सालाना 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.5डी)।

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (चार्ट III) द्वारा किए गए नवीनतम व्यापार सर्वेक्षण के अनुसार, दिसंबर 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में खुदरा बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में सुधार हुआ, जो मोटे तौर पर त्वरित सेवा रेस्तरां, खेल के सामान, व्यक्तिगत देखभाल, आभूषण, भोजन और किराने का सामान द्वारा संचालित है। हालाँकि, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स की खुदरा माँग कम रही।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर (यूआर) फरवरी में 8.0 प्रतिशत थी (चार्ट III.7ए)। श्रम बल

चार्ट III.7: श्रम बाजार स्थितियां

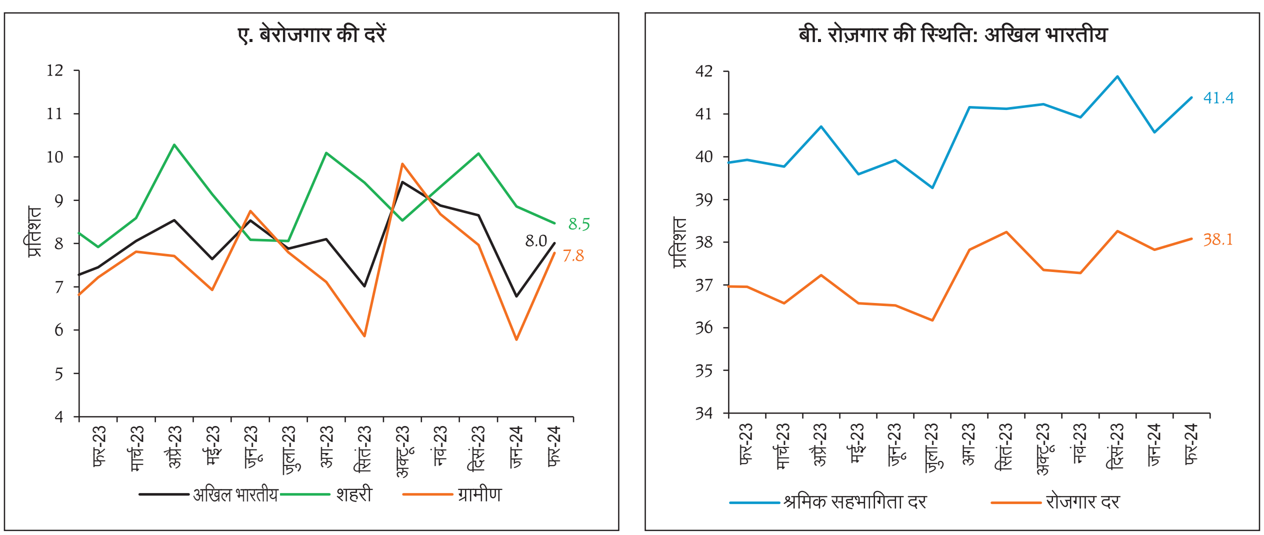

स्रोत: सीएमआईई।

चार्ट III.8 : श्रम बाज़ार संकेतक* : पीएलएफएस कैलेण्डर वर्ष (जन-दिसं 2023)

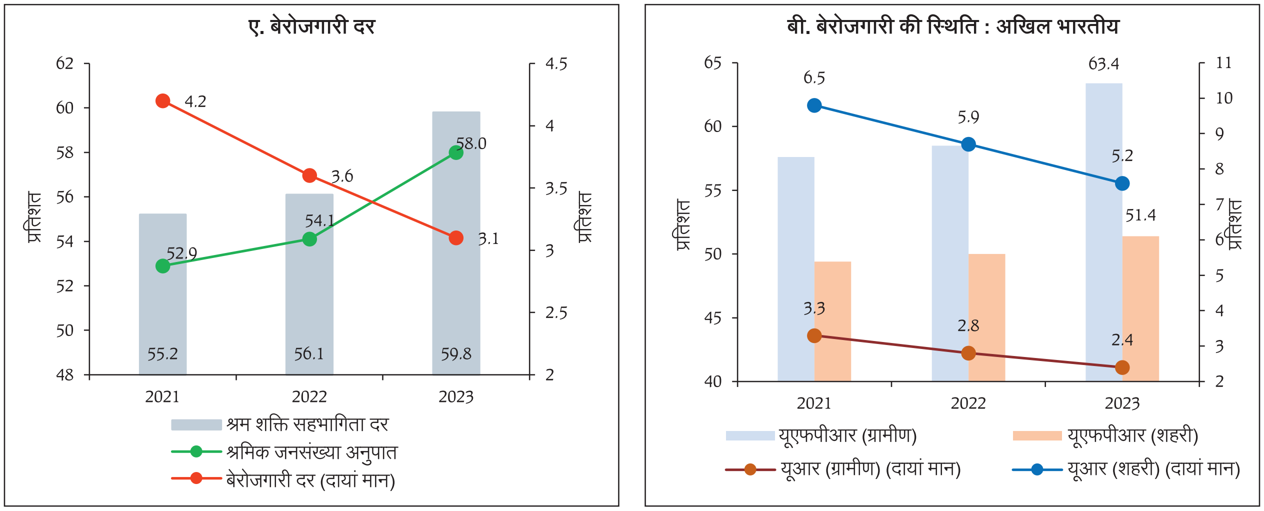

टिप्पणी : *सभी संकेतक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए हैं और सामान्य स्थिति (मुख्य गतिविधि स्थिति+सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति) में हैं।
स्रोत: एमओएसपीआई।

भागीदारी दर (एलएफपीआर) और रोजगार दर (ईआर) में पिछले महीने की तुलना में मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.7बी)।

हाल ही में कैलेंडर वर्ष 2023[10] के लिए जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा से पता चला है कि श्रम बाजार संकेतकों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया है। अखिल भारतीय स्तर पर, एलएफपीआर[11] 2022 में 56.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 59.8 प्रतिशत हो गया, जो 2017-18 में सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। विशेष रूप से, महिला एलएफपीआर पिछले वर्ष के 33.9 प्रतिशत से बढ़कर 41.3 प्रतिशत हो गई है। महिला डब्ल्यूपीआर में उल्लेखनीय सुधार के साथ श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) भी 2023 में बढ़कर 58.0 हो गया (2022 में 32.8 से 2023 में 40.1)। 2023 में बेरोजगारी दर (यूआर) गिरकर 3.1 प्रतिशत हो गई - यह पीएलएफएस शृंखला में सबसे कम है (चार्ट III.8ए)।

ग्रामीण क्षेत्रों में, एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर बढ़कर क्रमशः 63.4 और 61.9 हो गया, जबकि यूआर गिरकर 2.4 प्रतिशत हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एलएफपीआर में 2022 में 37.5 प्रतिशत से 2023 में 47.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। शहरी क्षेत्रों में, एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर क्रमशः 51.4 और 48.8 तक बढ़ गई, जबकि यूआर में कमी आई (चार्ट III.8बी)।

विनिर्माण और सेवाओं के लिए पीएमआई द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार, संगठित क्षेत्र में रोजगार का दृष्टिकोण फरवरी 2024 में कम रहा। जबकि विनिर्माण रोजगार लगातार दूसरे महीने संकुचन में रहा, सेवा रोजगार ग्यारह महीने के निचले स्तर पर आ गया (चार्ट III.9)।

चार्ट III.9 : पी एम आई रोजगार सूचकांक

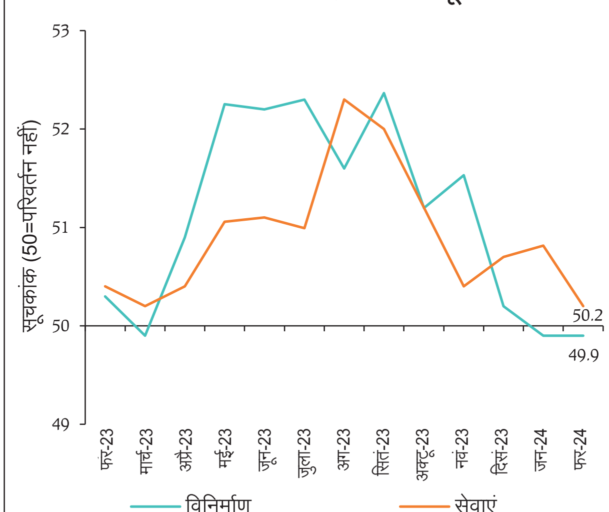

नोट: 50 से ऊपर का पीएमआइ मान विस्तार दर्शाता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

[10] पीएलएफएस प्रमुख श्रम बल संकेतक कैलेंडर वर्ष 2023.pdf (mospi.gov.in)।

[11] 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार मापन किया गया।

चार्ट III.10 : मनरेगा का मासिक कार्य मांग स्वरूप

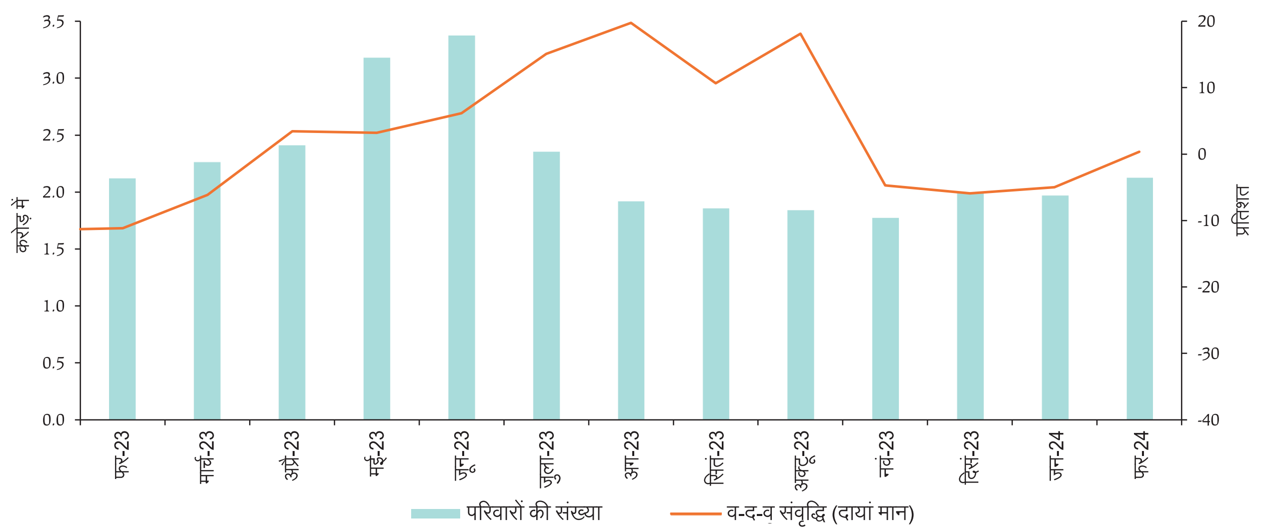

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मांगे गए काम में फरवरी में 0.3 प्रतिशत (माह-दर-माह) की वृद्धि देखी गई, जो रबी फसल की बुआई के पूरा होने के साथ कम कृषि श्रम मांग को दर्शाता है (चार्ट III.10)।

फरवरी 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात लगातार तीसरे महीने 11.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 41.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो ग्यारह महीने का उच्चतम स्तर है (चार्ट III.11)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 22 वस्तुओं (निर्यात बास्केट का 83.2 प्रतिशत हिस्सा) ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर

चार्ट III.11 : भारत का व्यापार निर्यात

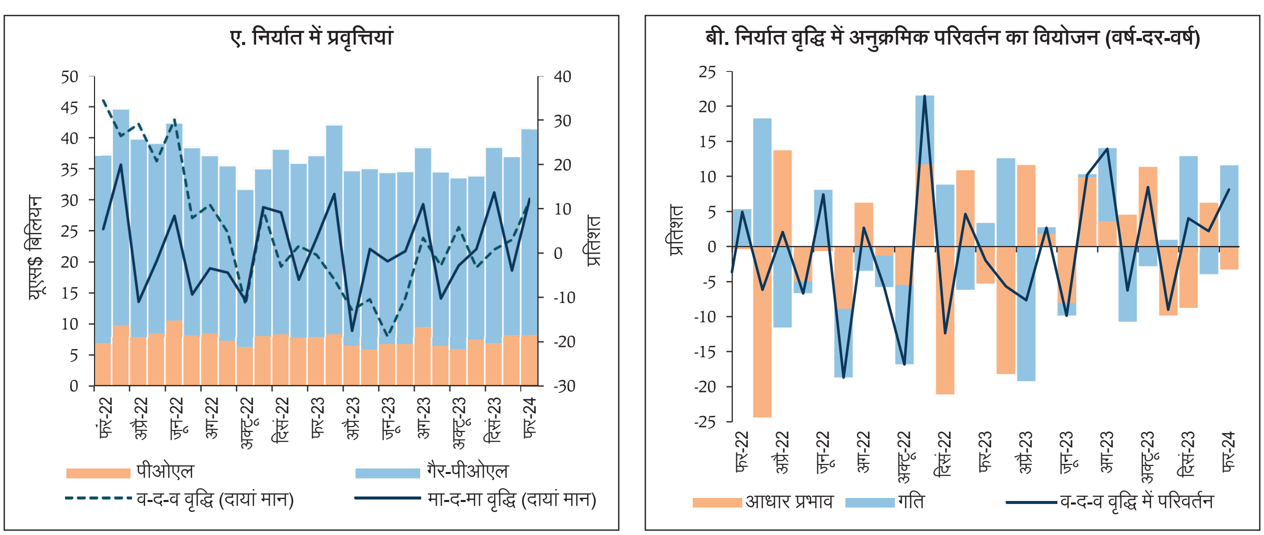

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.12 : भारत का व्यापार निर्यात – तुलनात्मक योगदान (फरवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2024)

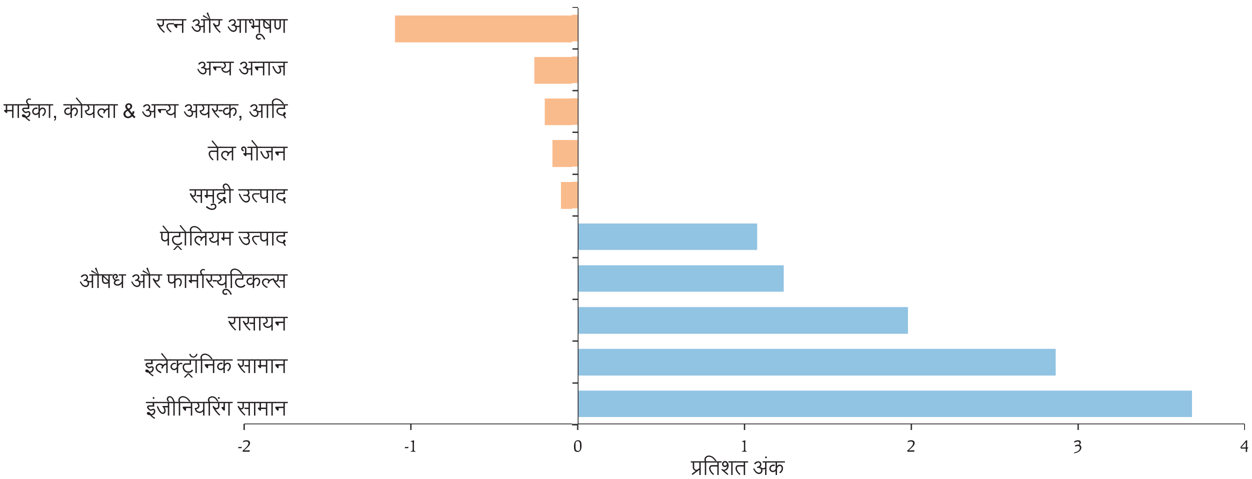

स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

विस्तार दर्ज किया। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैविक और अकार्बनिक रसायन, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पादों ने निर्यात वृद्धि का समर्थन किया, जबकि रत्न और आभूषण, अन्य अनाज, अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, तेल भोजन और समुद्री उत्पादों ने फरवरी में समग्र निर्यात को नीचे खींच लिया (चार्ट III.12)।

लगातार दूसरे महीने व्यापारिक वस्तुओं का आयात बढ़ा और फरवरी में यह 60.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। आयात में तेजी ने ऋणात्मक आधार प्रभाव को संतुलित किया, जिससे सालाना आधार पर 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.13)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 17 वस्तुओं (आयात बास्केट का 77.4 प्रतिशत हिस्सा) में वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट III.13 : भारत का पण्य आयात

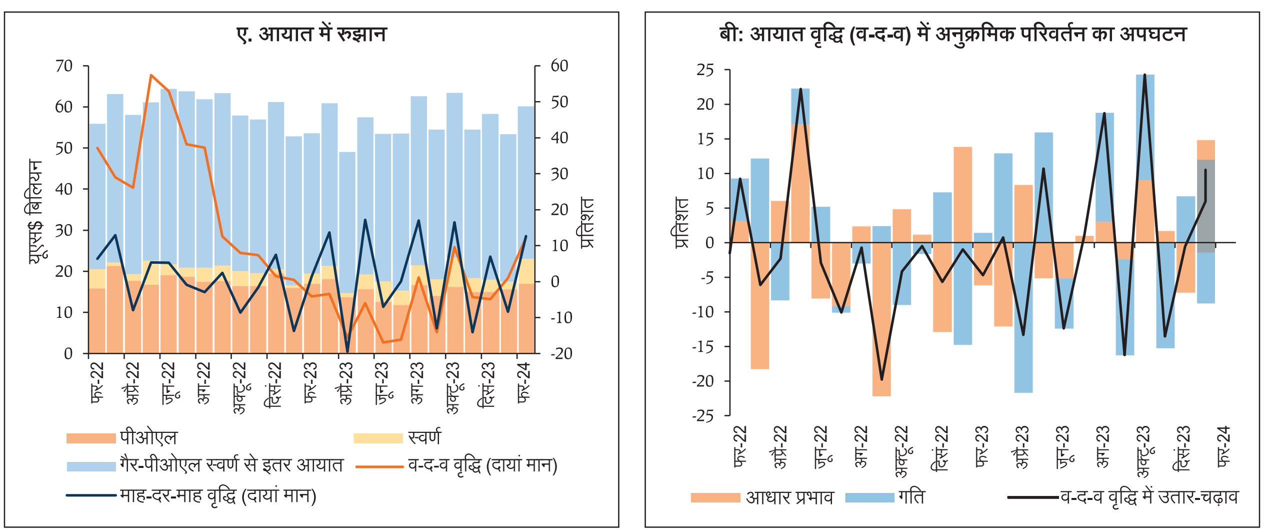

स्रोत: पीआईबी, डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.14: भारत का पण्य आयात - तुलनात्मक योगदान (फरवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2024 में)

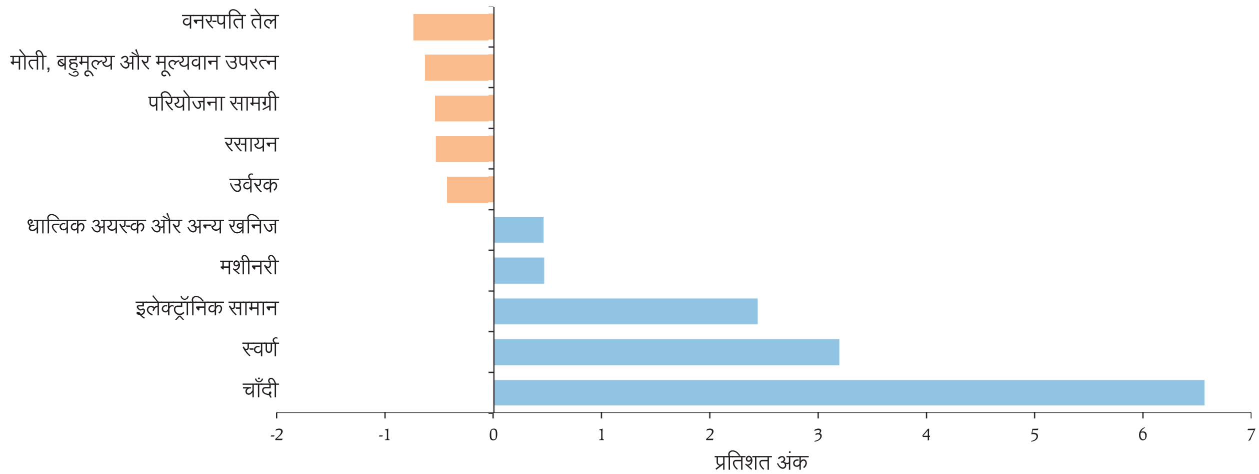

स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

फरवरी में सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और धातु अयस्कों और अन्य खनिजों के कारण आयात वृद्धि में बढ़ोतरी हुई, जबकि वनस्पति तेल, मोती, कीमती रत्न और मूल्यवान उपरत्न, परियोजना सामग्री, रसायन और उर्वरक के कारण वृद्धि में कमी आई (चार्ट III.14)।

आयात में वार्षिक और अनुक्रमिक वृद्धि के कारण निर्यात वृद्धि में गिरावट आई, जिससे पण्य व्यापार घाटा जनवरी के 16.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर फरवरी में 18.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। कुल व्यापारिक घाटे में पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकेंट (पीओएल) घाटे का हिस्सा फरवरी में 10 महीने के उच्च स्तर 46.2 प्रतिशत पर पहुंच गया (चार्ट III.15)।

चार्ट III.15: भारत के पण्य व्यापार घाटे का अपघटन

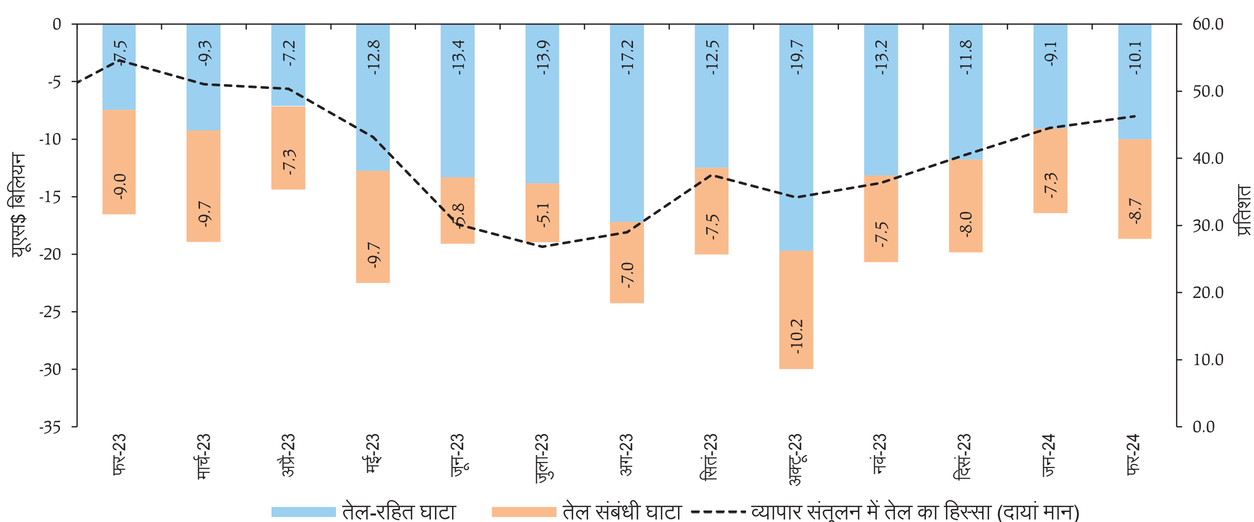

स्रोत: पीआईबी; और डीजीसीआईएस।

चार्ट III.16: पण्य-वार व्यापारिक घाटा

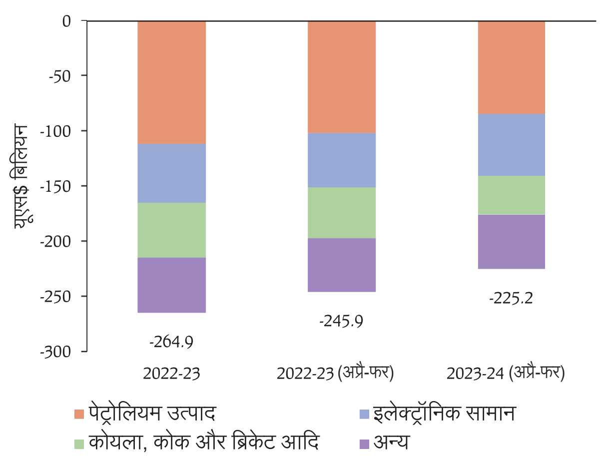

नोट: फरवरी 2024 में कोयला, कोक और ब्रिकेट्स का निर्यात जनवरी के समान स्तर पर माना गया है।

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.17: यूरोपीय मुख्य व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ भारत का व्यापार

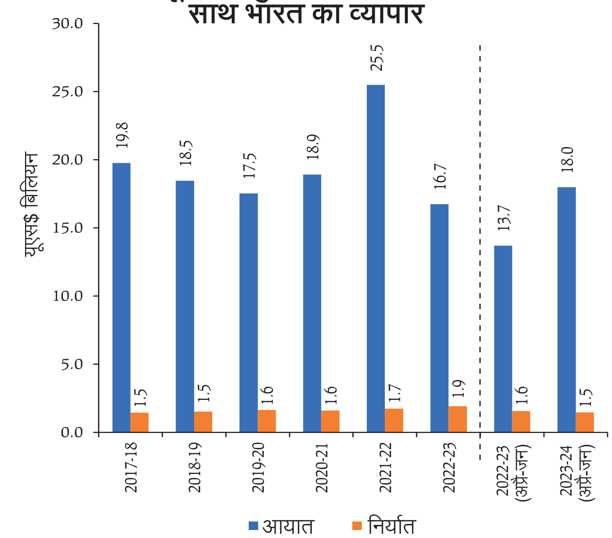

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात 395.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो 3.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) संकुचित हुआ, जबकि व्यापारिक आयात 5.3 प्रतिशत की दर से 620.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष-दर-वर्ष) तक घट गया। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान पण्य व्यापार घाटा कम होकर 225.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 245.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस घाटे के सबसे बड़े स्रोत पेट्रोलियम उत्पाद और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान थे (चार्ट III.16)।

भारत ने 10 मार्च 2024 को यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए।[12] ईएफटीए के साथ भारत की व्यापारिक स्थिति घाटे (व्यापार घाटा)[13] की है – 2022-23 में देशों के इस गुट (ब्लॉक) से 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया गया जबकि निर्यात 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट III.17)। ईएफटीए में स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो भारत के कुल आयात के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार है (जिसमें 80 प्रतिशत हिस्सा स्वर्ण का है)। ईएफटीए से प्रमुख आयातित वस्तुओं में सोना, पेट्रोलियम गैस, कोयला, सोयाबीन तेल और औषधि उत्पाद शामिल हैं, जबकि प्रमुख निर्यात में जैविक रसायन, कीमती रत्न और मूल्यवान उपरत्न, जहाज, नाव और प्लवमान संरचनाएं, ऑप्टिकल उपकरण और परमाणु रिएक्टर शामिल हैं। टीईपीए का उद्देश्य अगले 15 वर्षों में ईएफटीए से भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई और एक मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना है।

सॉफ्टवेयर सेवाओं, यात्रा सेवाओं और कारोबारी सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के कारण, जनवरी 2024 में 31.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेवा निर्यात में 10.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि सेवाओं का आयात 0.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो सॉफ्टवेयर सेवाओं और यात्रा सेवाओं के आयात में वृद्धि से प्रेरित था (चार्ट III.18)। इसके परिणामस्वरूप, जनवरी में निवल सेवा निर्यात आय 22.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) संशोधित अनुमानों (आरई) का 63.6 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के 67.8 प्रतिशत से कम था। इसका कारण

[12] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2013169. ईएफटीए में चार सदस्य देश शामिल हैं, अर्थात् स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन।

[13] ईएफटीए में, भारत की आइसलैंड के साथ पण्य व्यापार अधिशेष की स्थिति है।

चार्ट III.18: सेवाओं का निर्यात और आयात: वृद्धि

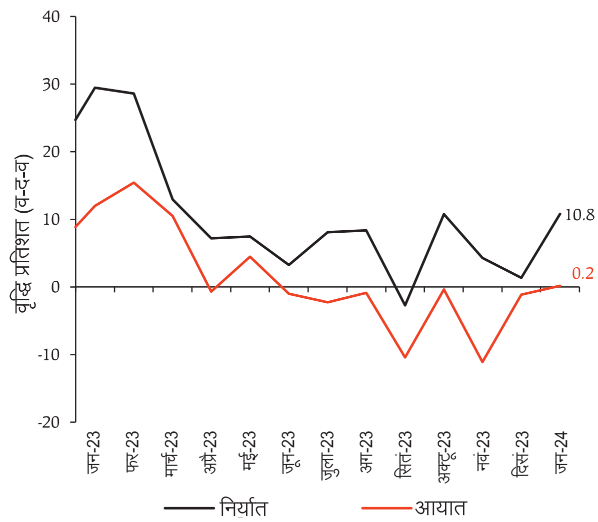

स्रोत: आरबीआई।

था – निम्न राजस्व व्यय और प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि। व्यय पक्ष पर, पूंजीगत व्यय में 26.5 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राजस्व व्यय वृद्धि 1.4 प्रतिशत (व-द-व) पर निहित रही [चार्ट III.19ए]। पूंजीगत परिव्यय (यानी, ऋण और अग्रिम को छोड़कर पूंजीगत व्यय) में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के व्यय की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ (चार्ट III.19बी)।

प्राप्तियों के क्षेत्र में, अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23.5 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, आय कर और निगम (कॉरपोरेट) कर संग्रह में क्रमशः 27.3 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अनुपालन में वृद्धि, उच्च अग्रिम कर संग्रह और कर आधार के विस्तार को दर्शाता है।[14,15,16] अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 4.7 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि के साथ, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) और सीमा शुल्क राजस्व में क्रमशः 9.0 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर, पिछले वर्ष की इसी अवधि के संबंध में, अप्रैल-जनवरी 2023-24 में उत्पाद शुल्क में 6.0 प्रतिशत की गिरावट आई है। समग्र रूप से, प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत वृद्धि के कारण, सकल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई (चार्ट III.20)।

अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान कर-रहित राजस्व संग्रह में 46.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण

चार्ट III.19: सरकारी व्यय (अप्रैल-जनवरी)

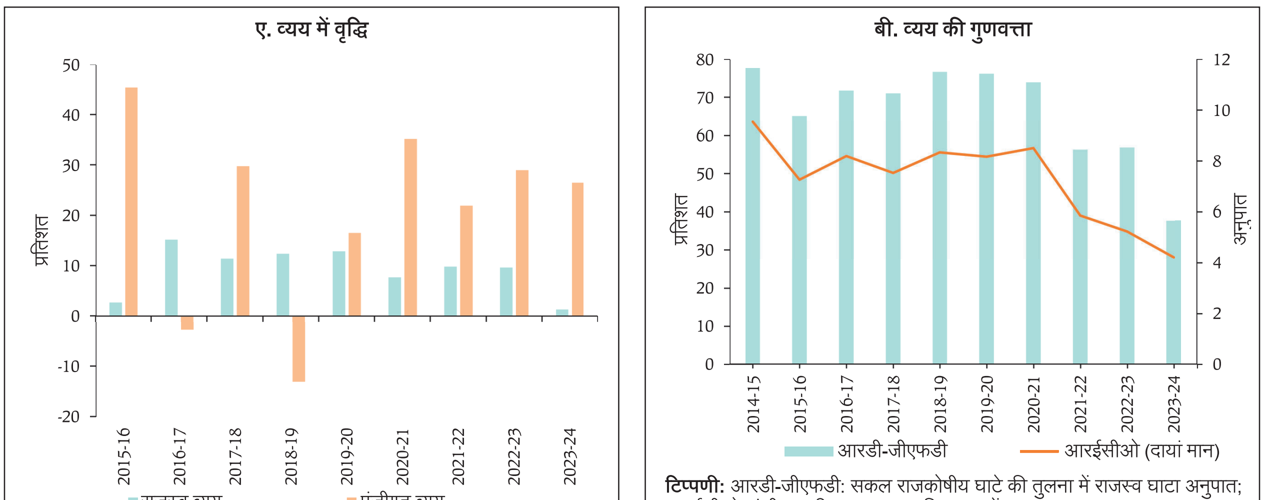

स्रोत: भारत के महालेखा नियंत्रक (सीजीए)।

टिप्पणी: आरडी-जीएफडी: सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटा अनुपात; आरईसीओ: पूंजीगत परिव्यय अनुपात की तुलना में राजस्व व्यय।
स्रोत: सीजीए।

14 पीआईबी, वित्त मंत्रालय, 1 जनवरी 2024।

15 पीआईबी, वित्त मंत्रालय, 18 दिसंबर 2023।

16 पीआईबी, वित्त मंत्रालय, 26 अक्टूबर 2023।

चार्ट III.20: कर राजस्व (अप्रैल-जनवरी 2023-24)

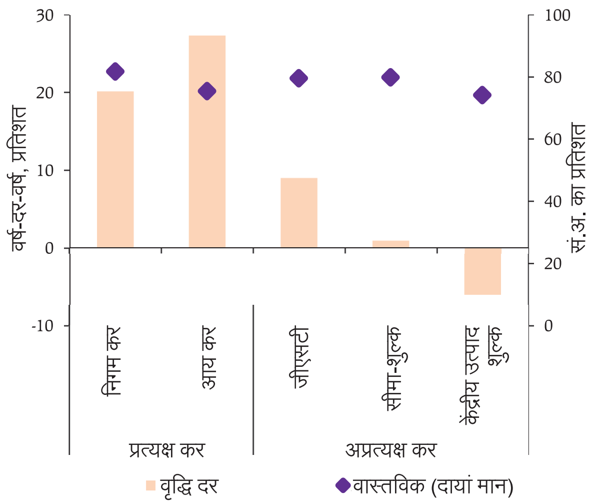

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

चार्ट III.21: कर-रहित राजस्व (अप्रैल-जनवरी)

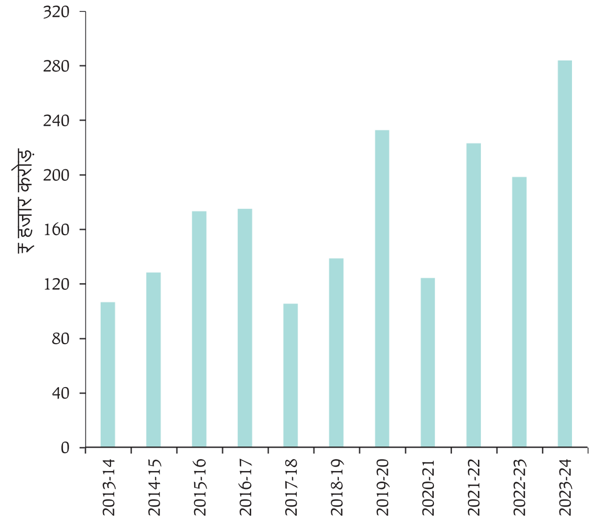

स्रोत: सीजीए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बजट से अधिक अधिशेष हस्तांतरण है (चार्ट III.21)।[17] दूसरी ओर, कर्ज-रहित पूंजीगत प्राप्तियां (मुख्य रूप से विनिवेश प्राप्तियों सहित) में 40.2 प्रतिशत की गिरावट आई।[18] कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों में 13.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में 2023-24 के लिए अनुदान की पूरक मांग की दूसरी खेप प्रस्तुत की, जिसमें ₹78,673 करोड़ (₹77,429 करोड़ का राजस्व व्यय और ₹1,244 करोड़ का पूंजीगत व्यय) का अतिरिक्त नकद व्यय शामिल था। हालांकि, इस अतिरिक्त नकदी व्यय की भरपाई उच्च राजस्व संग्रह द्वारा किए जाने की उम्मीद है, जो बजट किए गए राजकोषीय घाटे पर इसके प्रभाव को सीमित करेगा।

फरवरी 2024 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) 12.5 प्रतिशत (व-द-व) बढ़कर ₹1.68 लाख करोड़ हो गया। अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह (₹18.4 लाख करोड़) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक था (चार्ट III.22)।

अप्रैल-जनवरी 2023-24 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) उनके बजट अनुमानों (बीई) के 67.5 प्रतिशत तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.6 प्रतिशत अंक अधिक है

चार्ट III.22: मासिक जीएसटी राजस्व

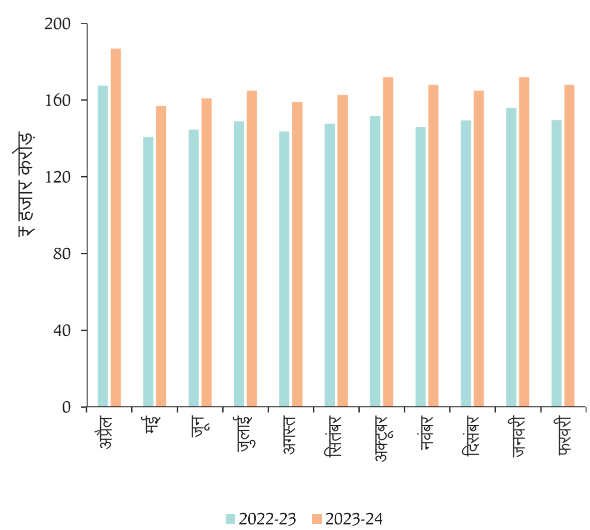

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)।

[17] 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार को ₹87,416.22 करोड़ का अधिशेष हस्तांतरित किया, जो पिछले वर्ष हस्तांतरित राशि (₹30,307.45 करोड़) और केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान के लाभांश/अधिशेष हस्तांतरण के तहत बजटीय राशि (₹48,000 करोड़), दोनों से अधिक है।

[18] अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान, सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों के रूप में ₹12,555 करोड़ जुटाए, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹38,671 करोड़ जुटाए गए थे।

चार्ट III.23: राज्यों के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-जनवरी)

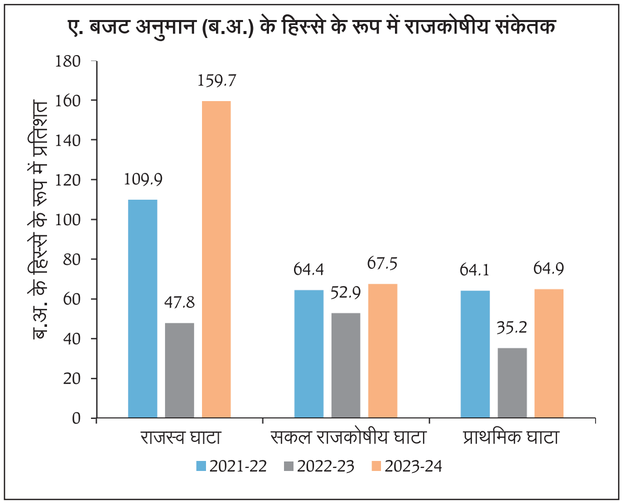

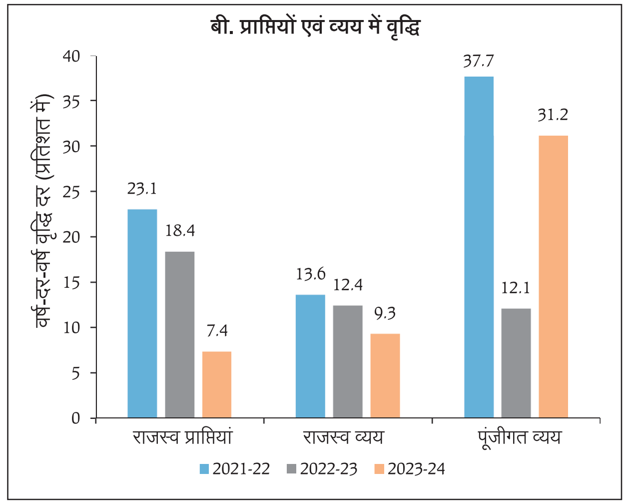

टिप्पणी: ये डेटा 24 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: सीएजी।

(चार्ट III.23ए)। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में मंदी और पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रेरित थी (चार्ट III.23बी)। प्राप्तियों के स्तर पर, राज्यों के कर राजस्व और कर-रहित राजस्व में क्रमशः 13.2 प्रतिशत और 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा राशि की समाप्ति और वित्त आयोग के अनुदान में धीरे-धीरे कमी के कारण केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान में कमी आई (चार्ट III.24ए)।

व्यय के स्तर पर, राज्यों के पूंजीगत व्यय में 31.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसे पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना से सहायता मिली। जनवरी 2024

चार्ट III.24: राज्यों के राजस्व और व्यय (अप्रैल-जनवरी)

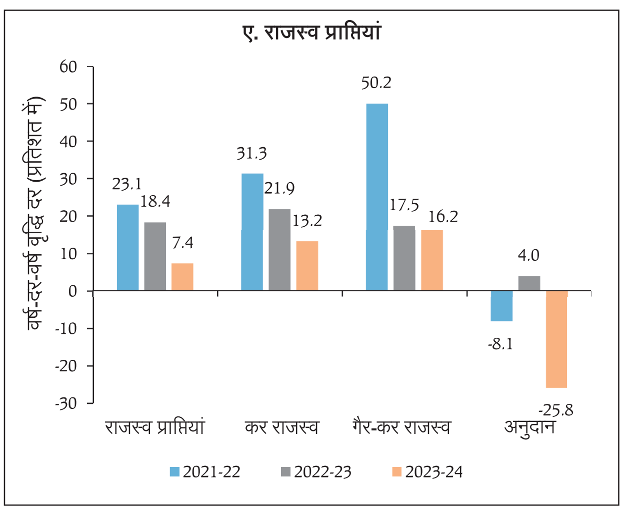

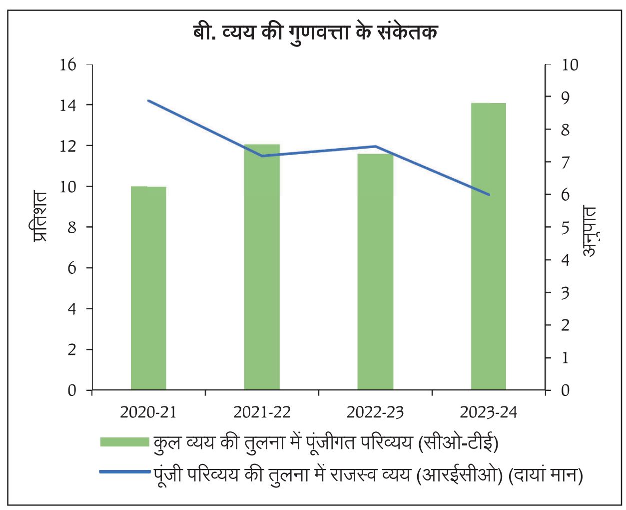

टिप्पणी: ये डेटा 24 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: सीएजी।

तक, केंद्र सरकार ने ₹1.11 लाख करोड़ (2023-24 के लिए आबंटित ₹1.3 लाख करोड़ में से) को मंजूरी दी थी, जिसमें से ₹66,745 करोड़ पहले ही राज्यों को वितरित किए जा चुके हैं।[19] दीर्घकालीन पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वर्धन ने राज्यों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार किया है (चार्ट III.24बी)।

सकल आपूर्ति

मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी गई सकल आपूर्ति, एसएई (एफएई के समान) के अनुसार 2023-24 में 6.9 प्रतिशत बढ़ी। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के कारण वृद्धि हुई, जबकि कृषि में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। तिमाही आधार पर, वास्तविक जीवीए वृद्धि पिछली तिमाही के 7.7 प्रतिशत से घटकर, 2023-24 की तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.25)।

औद्योगिक क्षेत्र ने 2023-24 की दूसरी और तीसरी तिमाही में लगातार दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए मजबूत गति बनाए रखी। वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 11.6 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि के साथ विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक जीवीए वृद्धि का प्राथमिक चालक बना रहा, जो सूचीबद्ध कॉरपोरेट विनिर्माण फर्मों के बढ़े हुए लाभ मार्जिन से सहायता प्राप्त है। खनन और उत्खनन में गतिविधि स्थिर रही। सेवा क्षेत्र ने उप-क्षेत्रों में व्यापक-आधारित समुत्थानशीलता के साथ वृद्धि दर्ज की। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने और रिहायशी आवास की मांग में तेजी आने से निर्माण गतिविधि में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाओं और वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाओं में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में सामान्य कमी आई।

चार्ट III.25: जीवीए वृद्धि में भारित योगदान

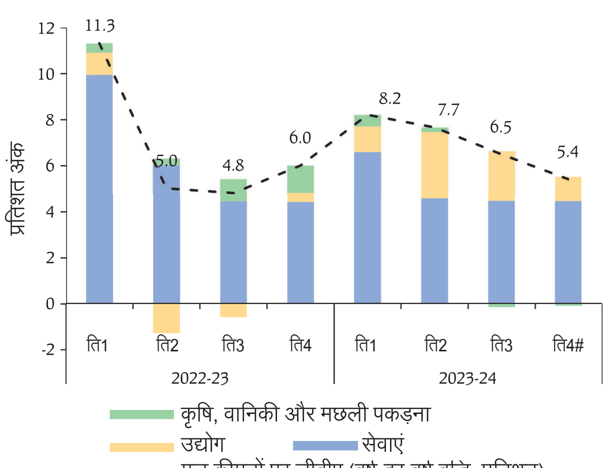

टिप्पणी: #: अंतर्निहित वृद्धि।
स्रोत: एनएसओ।

कृषि फसल उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) में वर्ष 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 309.3 मिलियन टन रहा, जो 2022-23 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 1.3 प्रतिशत कम है। इस कमी का कारण खरीफ और रबी फसल उत्पादन, दोनों में क्रमशः 1.0 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की कमी है। हालांकि, गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 112.0 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष के अंतिम अनुमानों की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक है। अधिकांश अन्य फसलों ने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में गिरावट दर्ज की (चार्ट III.26)।

प्रथम अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार, 2023-24 के दौरान बागवानी उत्पादन के लिए 355.3 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है, जो 2022-23 के अंतिम अनुमानों से 0.1 प्रतिशत कम है। वर्ष 2022-23 में उत्पादन 355.5 मिलियन टन

चार्ट III.26: 2023-24 में कृषि उत्पादन (एसएई)

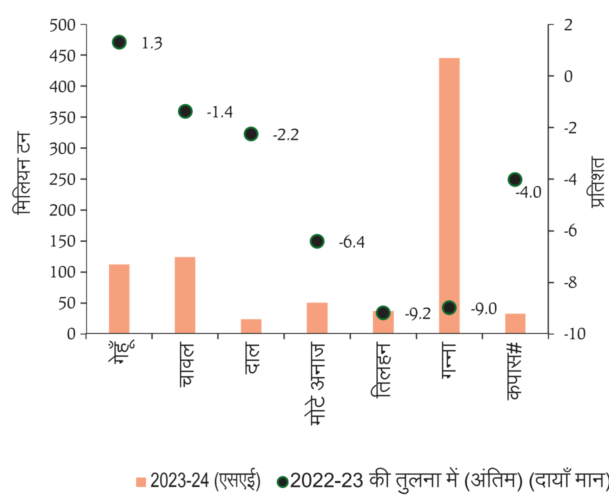

टिप्पणी: # प्रत्येक के लिए 170 किलोग्राम की मिलियन गठरियाँ (बेल)।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

[19] https://doe.gov.in/sites/default/files/Monthly%20Summary%20Report%20of%20Department%20of%20Expenditure%20for%20the%20month%20of%20January%2C%202024.pdf

चार्ट III.27: बागवानी उत्पादन

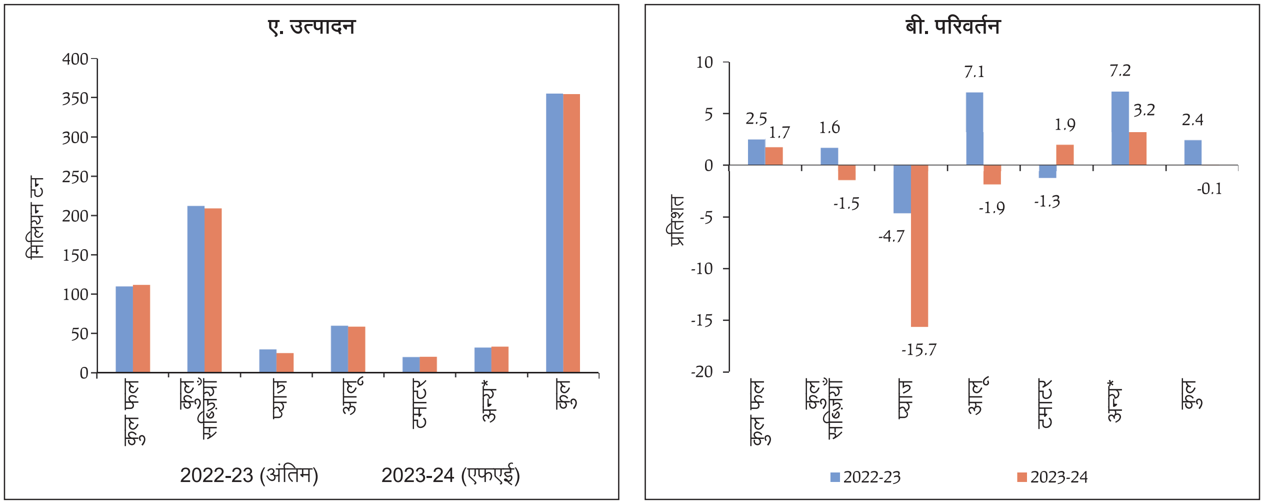

टिप्पणी: *: अन्य में बागान फसलें, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे शामिल हैं।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

था, जो 2021-22 की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक था (चार्ट III.27)।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के नवीनतम दृष्टिकोण[20] के अनुसार, मार्च-मई 2024 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान होने की संभावना है।[21] मार्च में गेहूं की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों (राजस्थान को छोड़कर) में सामान्य से अधिक तापमान की संभावना कम है, जो गेहूं की तैयार फसल के लिए अच्छा है (चार्ट III.28)। प्रबल अल नीनो की स्थिति के भी आगामी मौसम के दौरान सामान्य होने की उम्मीद है और यह इसके बाद तटस्थ हो सकती है।

चार्ट III.28: मार्च के लिए तापमान संभावना (संभावित पूर्वानुमान)

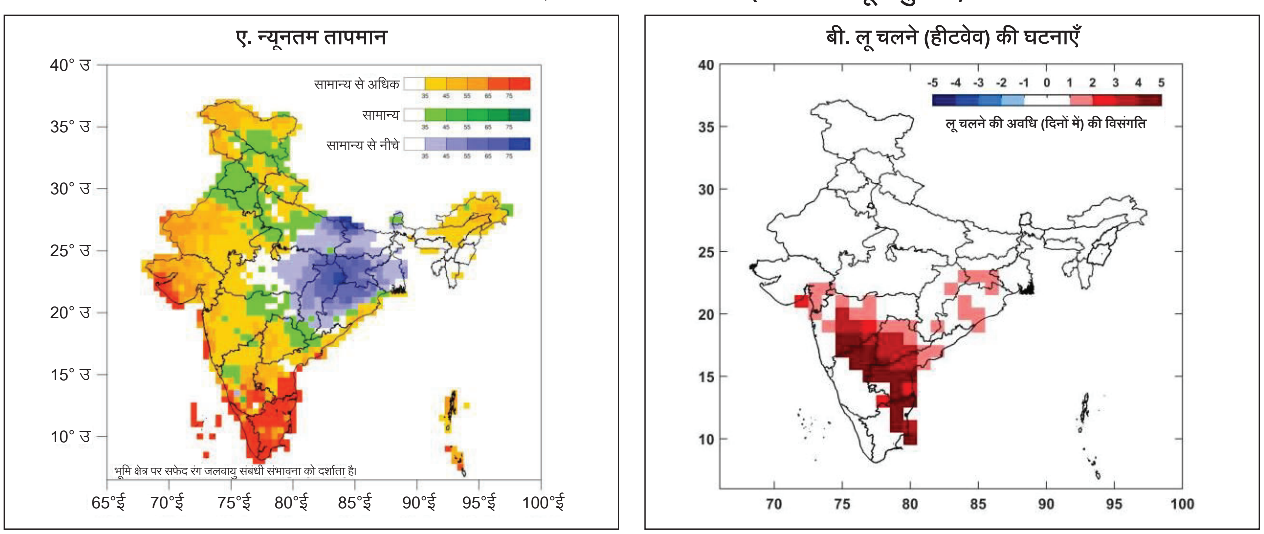

स्रोत: आईएमडी।

[20] 1 मार्च 2024 को जारी 'ग्रीष्म ऋतु के मौसम (मार्च से मई) के दौरान मौसमी तापमान' के दृष्टिकोण में प्रस्तुत किए गए

[21] https://internal.imd.gov.in/press_release/20240301_pr_2850.pdf

14 मार्च 2024 तक अखिल भारतीय जलाशय स्तर, कुल जलाशय क्षमता का 40 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के स्तर के साथ-साथ दशकीय औसत स्तर से कम था (चार्ट III.29)।

खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2023-24 के तहत चावल की खरीद 14 मार्च 2024 तक 442.8 लाख टन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत कम थी। प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में चालू सीजन के लिए गेहूं की फसल आनी शुरू हो गई है। आगामी रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2024-25 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद 300-320 लाख टन की सीमा में तय की गई है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य संस्थानों के पास 01 मार्च 2024 तक खाद्यान्न का स्टॉक, चावल के बफर मानदंड का 7.6 गुना और गेहूं के लिए 0.7 गुना पर बना रहा।[22]

गेहूं की कीमतों को 2021-22 और 2022-23 के दौरान लू चलने (हीटवेव) के कारण दबाव का सामना करना पड़ा। फरवरी 2023 में गेहूं की खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति 25.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद, सरकार की दक्ष आपूर्ति प्रबंधन नीतियों जैसे गेहूं के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस-डब्ल्यू) की सहायता से, गेहूं की कीमतों में मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान काफी कम हो गई और फरवरी 2024 में 2 प्रतिशत तक पहुंच गई (बॉक्स ए)।

चार्ट III.29: जलाशय स्तर (14 मार्च 2024 तक)

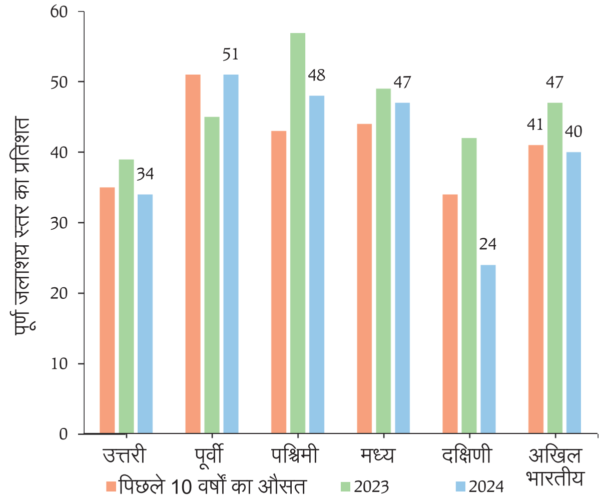

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

बॉक्स ए: गेहूं के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस-डब्ल्यू): कीमतों पर प्रभाव

हाल के वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति के प्रबंधन में कीमतों में वृद्धि को सामान्य करने के लिए आपूर्ति पक्ष की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण रही हैं। इन उपायों में ओएमएसएस-डब्ल्यू का संचालन करना, निर्यात प्रतिबंध लगाना, गेहूं व्यापारियों पर स्टॉक रखने की सीमा लगाना और भारत ब्रांड आटा[23] की बिक्री शामिल है (चार्ट ए1)। वर्ष 2023-24 (28 फरवरी तक) के दौरान, सरकार ने 36 साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित

चार्ट ए1: गेहूं की खुदरा कीमत में रुझान

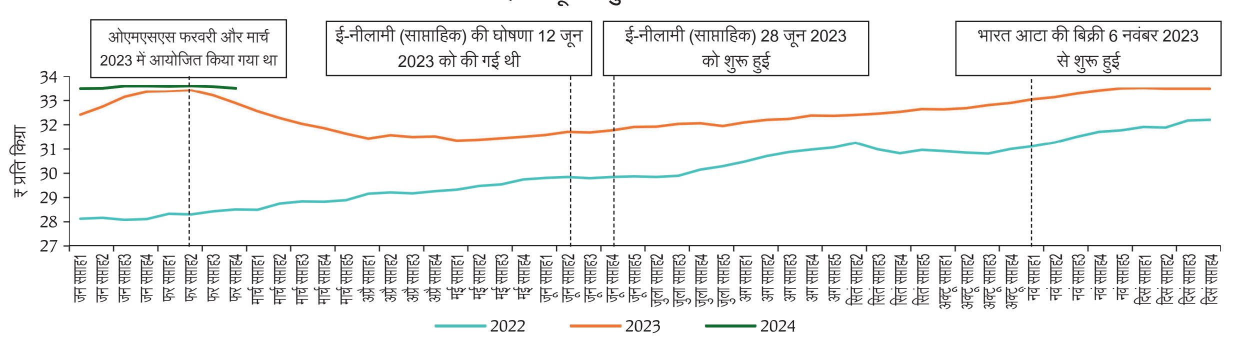

टिप्पणी: दैनिक खुदरा कीमतों को साप्ताहिक औसत कीमतों में बदल दिया गया।
स्रोत: सीईआईसी।

(जारी..)

[22] चावल और गेहूं के लिए जनवरी-मार्च तिमाही के लिए बफर मानदंड क्रमशः 76.1 लाख टन और 138 लाख टन है।

[23] केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2023 से मोबाइल वैन के साथ-साथ केंद्रीय भंडार, नाफेड और एनसीसीएफ के स्टोर के माध्यम से ₹27.5/किग्रा की एमआरपी पर भारत ब्रांड आटा की बिक्री की घोषणा की।

की। ओएमएसएस-डब्ल्यू के तहत भारी मात्रा में बिक्री (ऑफलोडिंग) के लिए निर्दिष्ट 101.5 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं में से 95 एलएमटी गेहूं 28 फरवरी 2024 तक बेचा गया था।[24]

मंडी कीमतों पर खुला बाजार बिक्री योजना की घोषणा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ एक घटना अध्ययन (ईवेंट स्टडी) किया गया था:

$$P_{id} = \alpha_i + \beta_{1d} * OMSS_d + \varepsilon_{id}$$

जहां P_{id}, जिले i में समय d (दैनिक) में दर्ज गेहूं की परिवर्तित मंडी कीमतों[25] (यानी, थोक मूल्य) का लॉग है; α_i राज्य-जिला-विशिष्ट निश्चित प्रभाव है; $OMSS_d$ एक डमी वैरिएबल है जो ओएमएसएस परिचालनों की घोषणा के बाद प्रत्येक दिन के लिए 1 का मान लेता है और अन्यथा की स्थिति में 0 का मान लेता है और ε_{id} एरर टर्म है। परिणाम दर्शाते हैं कि समग्र स्तर पर, गेहूं के लिए ओएमएसएस परिचालनों की घोषणा का मंडी की गेहूं कीमतों पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और ऋणात्मक प्रभाव पड़ा (सारणी ए1)। दूसरे शब्दों में, कीमतों में गिरावट आई।

इसके अलावा, ओएमएसएस-डब्ल्यू के तहत वास्तविक खरीद के प्रभाव की जांच डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) दृष्टिकोण का उपयोग करके की गई थी। 13 राज्यों में जिलों को कवर करते हुए, 2021-2023 के लिए गेहूं की दैनिक खुदरा कीमतों पर जिला स्तरीय पैनल डेटा का उपयोग करते हुए, जिलों में ओएमएसएस-डब्ल्यू ई-नीलामी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का अनुमान लगाया गया था:

$$P_{idy} = \alpha_i + \beta_1 OMSS_{id} + \beta_2 Treatment\ Year_{iy} + \beta_3 (OMSS * Treatment\ Year)_{idy} + \varepsilon_{iyd}$$

सारणी ए1. घटना अध्ययन विश्लेषण के परिणाम

	गेहूं का मंडी मूल्य (मॉडल)	गेहूं का मण्डी मूल्य (अधिकतम)
गेहूं के लिए ओएमएसएस	-0.004** (0.00)	-0.008*** (0.00)
स्थिरांक	7.763*** (0.00)	7.826*** (0.00)
राज्य-जिला निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ
प्रेक्षणों की संख्या	10,328	10,317
आर-स्क्वायर्ड	0.630	0.703

टिप्पणियाँ: 1. मजबूत मानक त्रुटियाँ (जिला स्तर पर समूहित) कोष्ठक में रिपोर्ट की गई हैं।
2. *, **, *** 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।
3. नीति घोषणा से पहले और बाद की अवधि क्रमशः 1 मई से 11 जून 2023 और 12 जून से 27 जून 2023 तक ली गई है।

सारणी ए2: डिफरेंस-इन-डिफरेंस विश्लेषण के परिणाम

	मॉडल 1
	गेहूं का खुदरा मूल्य (2021-2022 के औसत के मुकाबले 2023 में)
गेहूं के लिए ओएमएसएस × ट्रीटमेंट ईयर	-0.007*** (0.003)
ओएमएसएस प्रभाव: दिनांक एफई$	0.005** (0.003)
ट्रीटमेंट इफेक्ट: वर्ष एफई	0.011*** (0.003)
प्रेक्षणों की संख्या	182,063
आर-स्क्वायर्ड	0.894
निश्चित प्रभाव	राज्य × जिला, वर्ष का सप्ताह, सप्ताह का दिन, भारत आटा#

टिप्पणियाँ: 1. मजबूत मानक त्रुटियाँ (जिला स्तर पर क्लस्टर) कोष्ठक में रिपोर्ट की गई हैं।
2. *, **, *** 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।
3. नीति घोषणा से पहले और बाद की अवधि क्रमशः 1 मार्च से 11 जून 2023 और 12 जून से 31 दिसंबर 2023 तक ली गई है।

$: निश्चित प्रभाव

भारत आटा$_{\text{आईडी}}$ ($Bharat\ Atta_{id}$) एक डमी वैरिएबल है जिसका मान प्रत्येक जिले के लिए 6 नवंबर 2023 के बाद के दिनों के लिए 1 है और अन्यथा 0 है।

जहां P_{idy}, वर्ष *y* में जिले *i* में *d* (दैनिक स्तर पर) दर्ज गेहूं की परिवर्तित खुदरा कीमतों का लॉग है; $OMSS_{id}$ एक डमी वैरिएबल है जो प्रत्येक जिले के लिए ओएमएसएस-डब्ल्यू परिचालनों की घोषणा से पहले और बाद के प्रत्येक दिन के लिए 0 मान लेता है; ट्रीटमेंट ईयर एक डमी वैरिएबल है जो वर्ष 2023 के लिए 1 का मान लेता है (ओएमएसएस-डब्ल्यू परिचालन के लिए) और 0, अन्यथा प्रत्येक जिले *i* के लिए; a_i निश्चित प्रभावों का एक वेक्टर है और ε_{iyd} एरर टर्म है। यह DiD डिज़ाइन 2023 (उपचार अवधि/ट्रीटमेंट ईयर) में 12 जून को ओएमएसएस-डब्ल्यू शुरू होने से पहले और बाद में मूल्य परिवर्तन की तुलना 2021 और 2022 (नियंत्रण अवधि) के औसत खुदरा मूल्य में परिवर्तन के साथ करता है। हमारा महत्वपूर्ण चर (गेहूं के ट्रीटमेंट ईयर के लिए ओएमएसएस * ट्रीटमेंट ईयर), जो अन्य कारकों को नियंत्रित करते हुए ओएमएसएस-डब्ल्यू के प्रभाव को मापता है, एक ऋणात्मक और महत्वपूर्ण गुणांक है, जो दर्शाता है कि ओएमएसएस के माध्यम से गेहूं जारी करने की सरकार की नीति के कारण खुदरा कीमतों में गिरावट आई है (सारणी ए2)।

संदर्भ: डी. सुगंधी, जी.वी. नथनएल और बिस्वजीत मोहंती (2024) "गेहूं की कीमतों पर ओएमएसएस की घोषणा और कार्यान्वयन का प्रभाव", अनुलेखित।

[24] उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) और विशेष विनिर्देशों के अंतर्गत (यूआरएस) के लिए आरक्षित कीमतें क्रमशः ₹2,150 प्रति क्विंटल और ₹2,125 प्रति क्विंटल पर निर्धारित की गई थीं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), 31 जनवरी 2024)।

[25] यह एगमार्कनेट पोर्टल पर मंडियों द्वारा रिपोर्ट की गई मॉडल और अधिकतम कीमतें हैं।

चार्ट III.30: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

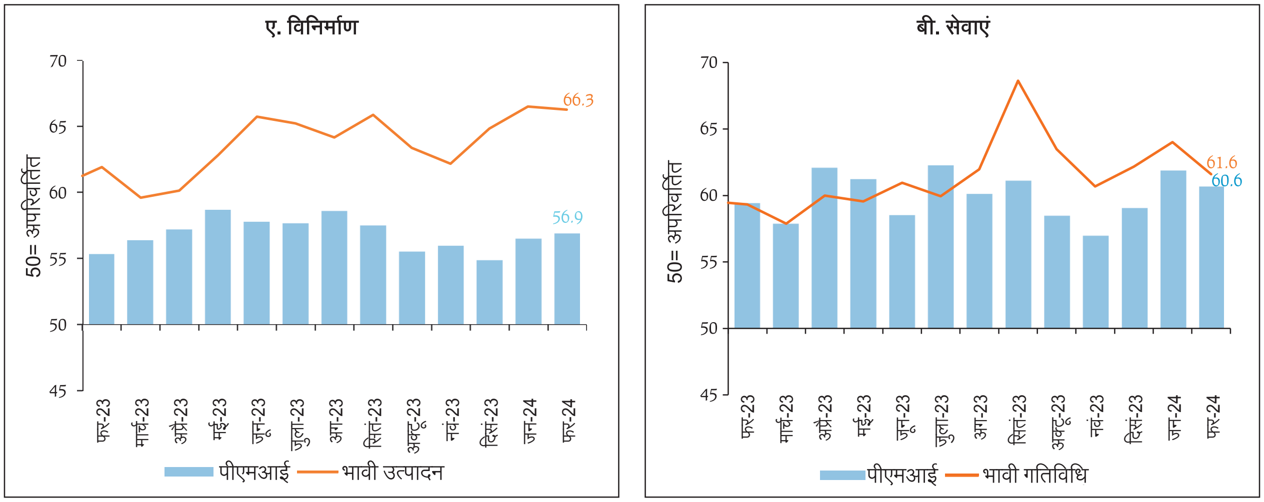

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं दर्शाता है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है तथा इसके विपरीत होता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए हेडलाइन पीएमआई, फरवरी 2024 में पांच महीने के उच्च स्तर 56.9 पर पहुंच गया, जो कि जनवरी के 56.5 से भी अधिक था – जो उत्पादन और नए ऑर्डर में वृद्धि द्वारा समर्थित था (चार्ट III.30ए)। सेवा क्षेत्र में पीएमआई ने 60.6 के साथ मजबूत विस्तार करना जारी रखा यद्यपि अनुक्रमिक कमी देखी गई (चार्ट III.30बी)।

सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री ने 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान नॉमिनल टर्म्स में 3.7 प्रतिशत (व-द-व) की निम्न वृद्धि दर्ज की, जो कि पिछली तिमाही में 4.2 प्रतिशत थी। यह मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, विद्युत उत्पादों और सीमेंट में सामान्यता और रसायनों में संकुचन से प्रेरित थी[26] (चार्ट III.31ए और बी)। आय पक्ष में, 2023-24 की तीसरी तिमाही में 14.5 प्रतिशत (व-द-व) की सांकेतिक योजित सकल मूल्य (जीवीए) वृद्धि मुख्य रूप से लाभ द्वारा प्रेरित थी (चार्ट III.31सी) - विनिर्माण कंपनियों के परिचालन लाभ में अनुक्रमिक और वार्षिक, दोनों आधारों पर सुधार हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की बिक्री में गिरावट जारी रही क्योंकि उद्योग उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में धीमी वृद्धि और कृत्रिम मेधा (एआई) जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के प्रभाव से जूझ रहा था। आईटी कंपनियों की राजस्व वृद्धि तीसरी तिमाही में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछली तिमाही में 5.9 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 19.4 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, गैर-आईटी सेवा कंपनियों की बिक्री 12.9 प्रतिशत की उच्च वृद्धि पथ पर रही, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से 'थोक और खुदरा व्यापार' और 'परिवहन और भंडारण सेवाओं' ने किया।

परिवहन गतिविधि के संकेतकों ने एक मिश्रित तस्वीर प्रदर्शित की। फरवरी 2024 में रेल भाड़ा राजस्व में 6.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो लौह अयस्क और कंटेनर

[26] रासायनिक उद्योग की बिक्री में 13.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जिसे छोड़कर सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि 6.4 प्रतिशत रही।

चार्ट III.31: कॉरपोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन

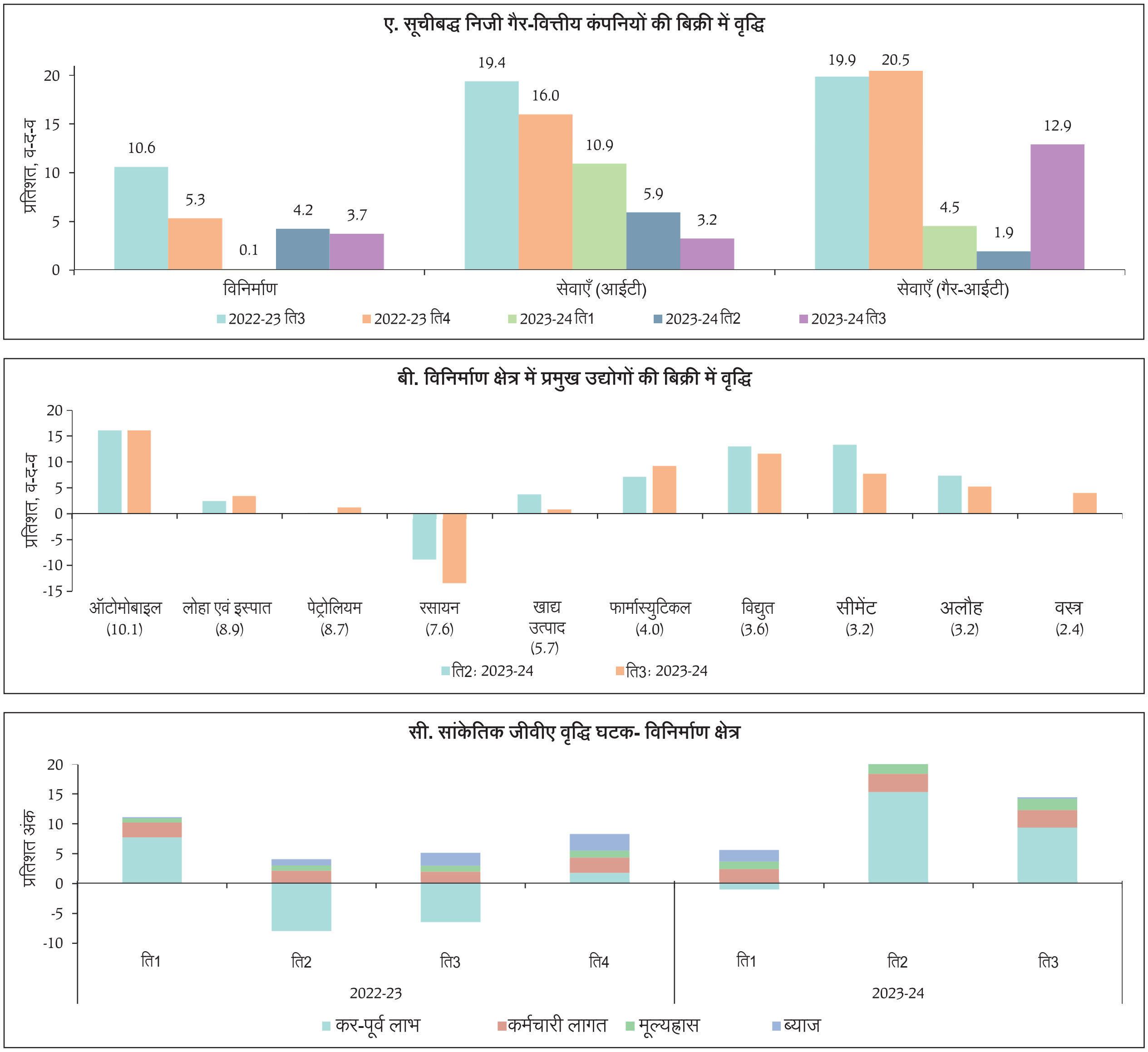

टिप्पणी: वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए परिणाम 2,580 सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों (1,685 विनिर्माण, 706 गैर-आईटी सेवाएं और 189 आईटी कंपनियां) पर आधारित हैं। कोष्ठक में दी गई संख्याएँ, सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों में उद्योगों की बिक्री हिस्सेदारी को दर्शाती हैं।
स्रोत: कैपिटलाइन; और आरबीआई स्टाफ गणना।

सेवाओं की माल ढुलाई से प्रेरित है (चार्ट III.32ए)। हालांकि, पीओएल और कोयला टन भार में गिरावट दर्ज होने से फरवरी 2024 में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट III.32बी)।

चार्ट 32: रेलवे यातायात और पोर्ट कार्गो

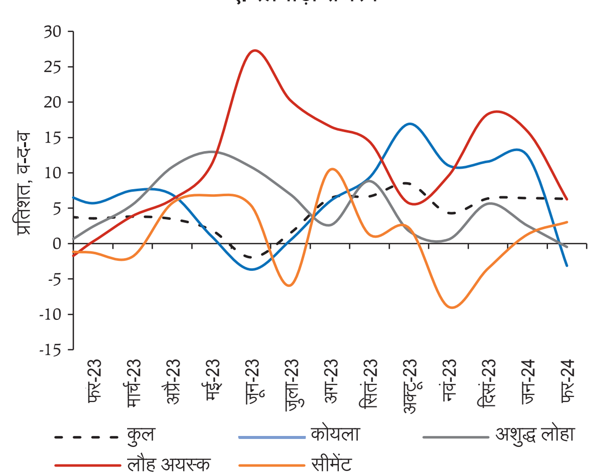

स्रोत: रेल दृष्टि।

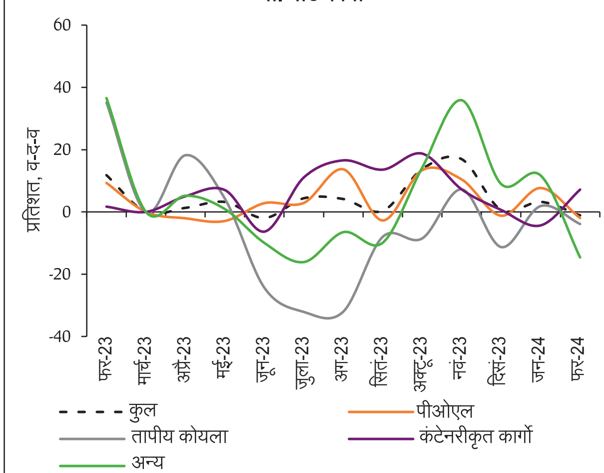

स्रोत: इंडियन पोर्ट्स असोसिएशन।

निर्माण क्षेत्र के संकेतकों में, फरवरी 2024 में स्टील की खपत में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और जनवरी 2024 में सीमेंट उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.33)।

सेवा क्षेत्र के लिए विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों ने फरवरी 2024 में मजबूत वृद्धि दर्ज की (सारणी III.2)।

चार्ट III.33: इस्पात खपत और सीमेंट उत्पादन

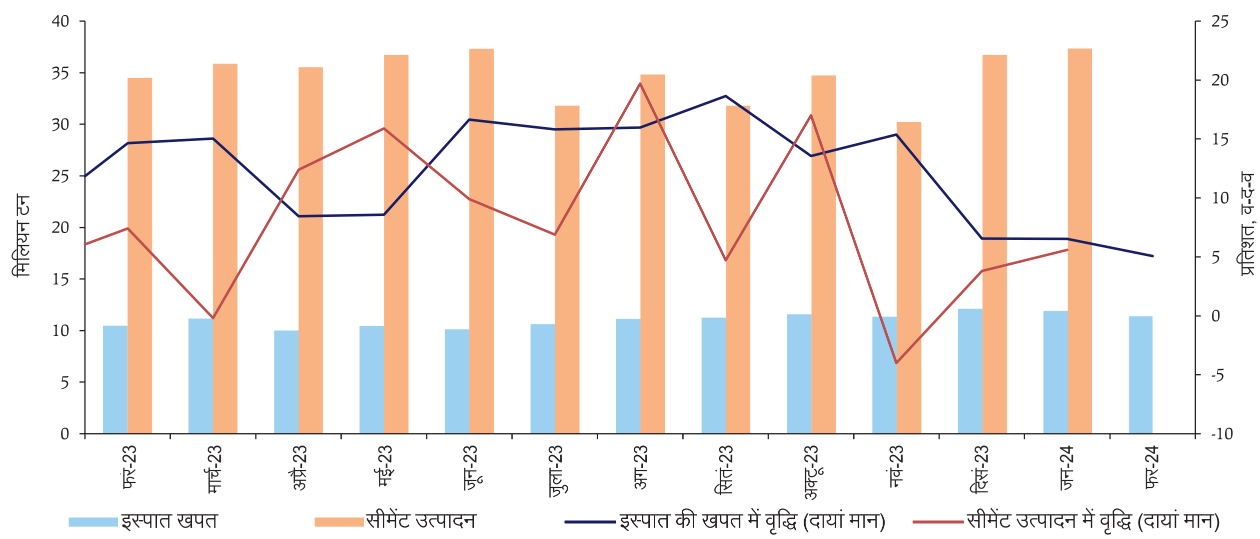

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

सारणी III.2: उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	अप्रै-23	मई-23	जून-23	जुला-23	अग-23	सितं-23	अक्टू-23	नवं-23	दिसं-23	जन-24	फर-24
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	12.9	14.9	1.6	2.9	11.6	3.1	17.3	4.3	3.2	13.9	5.7
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	15.1	17.4	1.7	-7.2	0.6	0.8	20.1	31.3	16.0	26.2	30.0
	तिपहिया वाहन बिक्री	104.2	70.4	98.6	78.9	68.8	47.0	42.1	30.8	30.6	9.5	4.6
	ट्रैक्टर बिक्री	-11.1	1.2	4.2	6.1	1.1	-14.7	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-33.0
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	-3.3			6.9			3.2				
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	3.5	1.9	-1.9	1.5	6.4	6.7	8.5	4.3	6.4	6.4	6.3
	पोर्ट कार्गो यातायात	1.3	3.5	0.4	4.3	4.4	0.3	13.8	17.0	0.7	3.2	-1.1
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात *	7.6	-4.5	-5.6	-4.1	6.0	-4.5	10.6	9.0	8.7	10.0	-10.5
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात *	-4.8	2.7	2.7	1.0	7.4	2.7	15.0	4.9	12.2	19.3	21.2
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	22.6	15.7	19.2	26.3	23.6	19.3	10.7	8.7	8.1	5.0	0.0
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात *	43.0	37.2	26.5	23.6	21.5	19.6	17.5	19.8	18.1	17.0	13.5
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	12.2	19.7	15.5	16.4	19.5	9.5	30.5	8.5	13.2	16.4	14.8
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर्राज्यीय)	16.2	23.0	18.8	20.8	22.6	12.4	30.0	22.7	14.2	17.9	17.0
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	5.9	14.3	9.9	9.1	14.4	4.9	31.2	-16.2	11.4	13.8	11.0
	होटल अधिभोग दर @	63.2	61.9	64.0	60.9	60.9	61.0	62.5	63.0	70.0		
	प्रति कमरा औसत राजस्व	21.2	15.8	14.0	14.2	13.9	18.3	14.8	15.9	12.8		
	पर्यटक आगमन	53.7	41.3	24.0	13.6	22.6	17.5	19.8	16.8	7.8		
निर्माण	इस्पात खपत	8.4	8.6	16.7	15.8	16.0	18.6	13.6	15.4	6.5	6.5	5.1
	सीमेंट उत्पादन	12.4	15.9	9.9	6.9	19.7	4.7	17.0	-4.0	3.8	5.6	
पीएमआई सूचकांक #	सेवाएं	62.0	61.2	58.5	62.3	60.1	61.0	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6

टिप्पणी: #: स्तरों में डेटा। *: फरवरी 2024 डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। @: डेटा दर में है, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर में नहीं।
स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी; आईएचएस मार्किट; एसआईएएम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और संयुक्त संयंत्र समिति।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)[27] में होने वाले वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ावों द्वारा मापी जाने वाली हेडलाइन मुद्रास्फीति, फरवरी 2024 में 5.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही क्योंकि अनुकूल आधारभूत प्रभावों के कारण लगभग 15 आधार अंकों (बीपीएस) की धनात्मक गति पूरी तरह से बेअसर हो गई थी। खाद्य और मूल समूहों (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर) में माह-दर-माह वृद्धि क्रमशः लगभग 10 आधार अंक और 25 आधार अंक थी, जबकि ईंधन समूह ने लगभग 10 आधार अंकों की ऋणात्मक गति देखी (चार्ट III.34)।

खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी के 7.6 प्रतिशत से फरवरी में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई। उप-समूहों के संदर्भ में मांस और मछली, अंडे, सब्जियों और चीनी में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई जबकि अनाज, दूध, फल, दाल, मसाले, गैर-मादक पेय पदार्थ और तैयार भोजन के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई। खाद्य तेल की कीमतों में अपस्फीति बनी रही (चार्ट III.35)।

मुख्य रूप से एलपीजी और पीडीएस केरोसिन की कीमतों में क्रमशः 13.3 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत की गिरावट के कारण, ईंधन और बिजली समूह में फरवरी में (-) 0.8 प्रतिशत पर अपस्फीति बनी रही, जो जनवरी के (-) 0.6 प्रतिशत से अधिक थी। हालांकि, बिजली की कीमतों में सालाना आधार पर 10.4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

मूल मुद्रास्फीति जनवरी में 3.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी में 3.4 प्रतिशत हो गई- जो कि चार वर्षों में इसका

[27] 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.34: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक

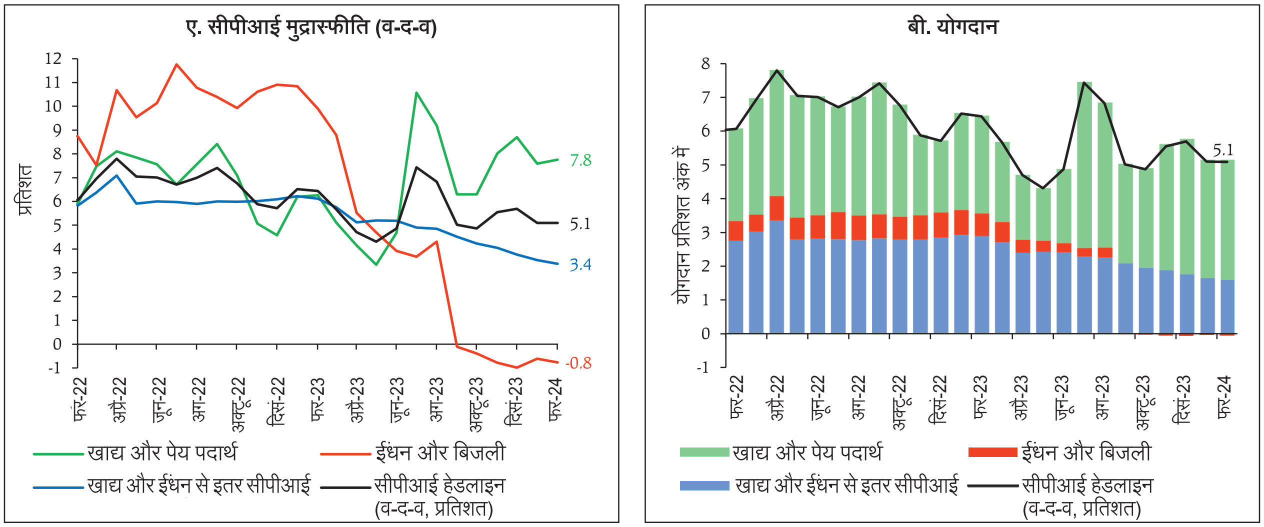

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सबसे निम्नतम स्तर है। सभी उप-समूहों में कमी देखी गई (चार्ट III.36)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, फरवरी में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 10 आधार अंकों की गिरावट के साथ 4.8 प्रतिशत हो गई। अधिकांश राज्यों में 4-6 प्रतिशत के बीच मुद्रास्फीति दर्ज की गई (चार्ट III.37)।

चार्ट III.35: वार्षिक मुद्रास्फीति (व-द-व) और उप-समूहों में गति (माह-दर-माह)

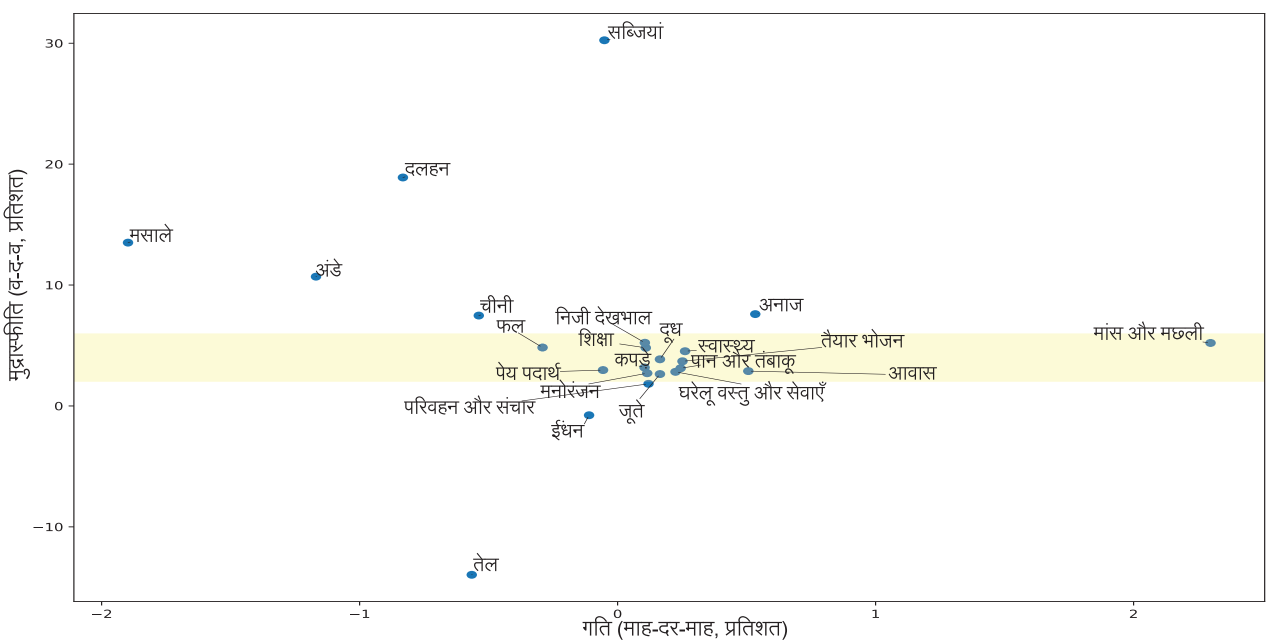

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.36: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (जनवरी 2024 की तुलना में फरवरी 2024)

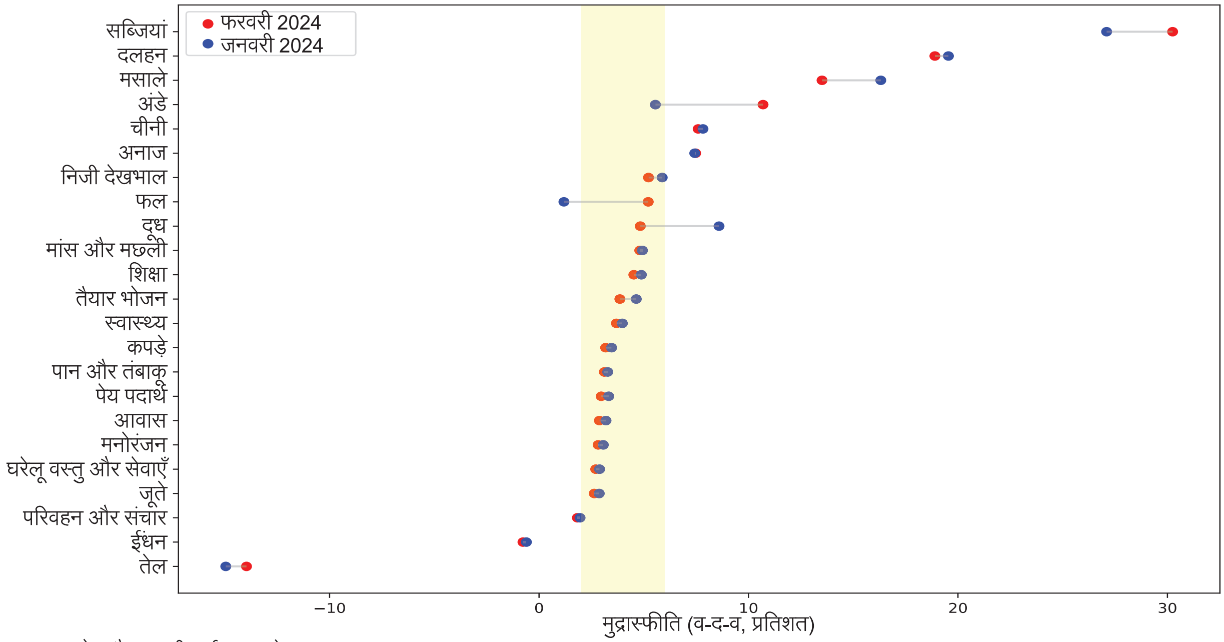

स्रोतः एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

मार्च के लिए अब तक (15 तारीख तक) उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा से पता चलता है कि अनाज, मुख्य रूप से गेहूं, की कीमतों में गिरावट आई है। जहां दलहन की कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि दर्ज की गई, वहीं खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। प्रमुख सब्जियों में, टमाटर की कीमतों में मार्च में अब तक गिरावट आई है, जबकि प्याज और आलू की कीमतों में पिछले तीन महीनों में गिरावट के बाद तेजी दर्ज की गई है (चार्ट III.38)।

चार्ट III.37: फरवरी 2024 में मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण (सीपीआई- संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

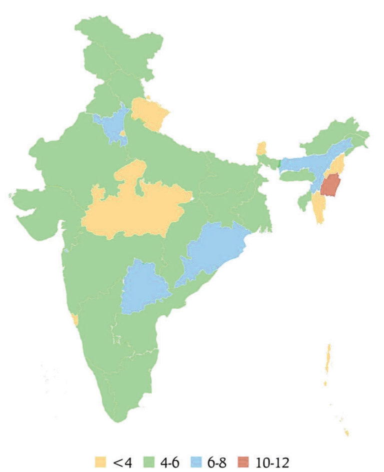

टिप्पणी: मानचित्र केवल उदाहरणात्मक उद्देश्यों के लिए है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चीनी की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के विपरीत, फरवरी 2024 में चीनी की घरेलू कीमतें स्थिर रहीं (चार्ट III.39)। उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में 10.25 प्रतिशत की चीनी रिकवरी दर पर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इसे ₹340 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले आगामी चीनी सीजन 2024-25 के लिए, 9.5 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ न्यूनतम मूल्य ₹315.10 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा 14 मार्च 2024 को की गई थी, जिसमें पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की कमी की गई थी। इसके अलावा, 9 मार्च 2024 को एलपीजी की कीमतों में ₹100 प्रति सिलेंडर की कटौती की गई, जबकि मिट्टी के तेल (केरोसिन) की कीमतों में मार्च में अब तक वृद्धि हुई है (सारणी III.3)।

चार्ट III.38: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

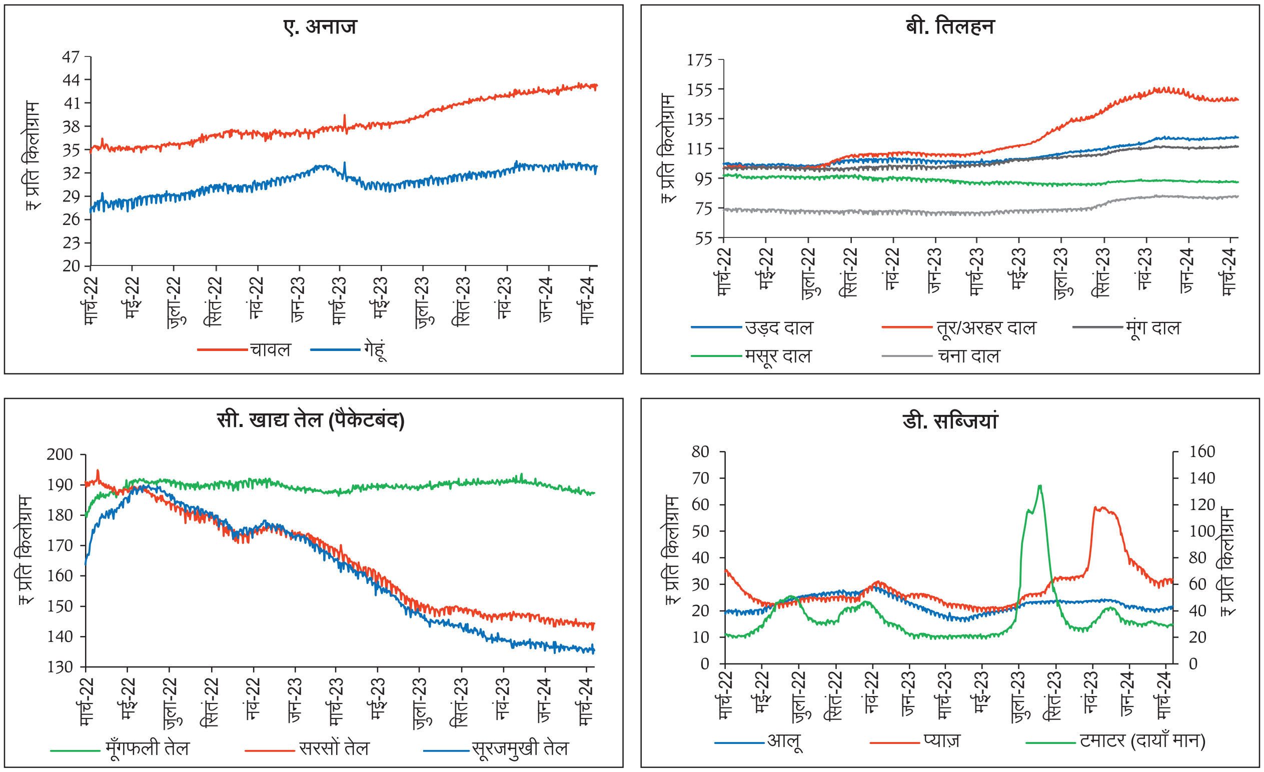

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

फरवरी 2024 के लिए, पीएमआई ने विनिर्माण क्षेत्र में इनपुट लागत में सबसे धीमी वृद्धि और अगस्त 2020 के बाद से सेवा क्षेत्र में तीसरी सबसे धीमी वृद्धि का संकेत दिया। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भी बिक्री कीमतों की वृद्धि में कमी आई (चार्ट III.40)।

चार्ट III.39: चीनी की घरेलू और वैश्विक कीमतें

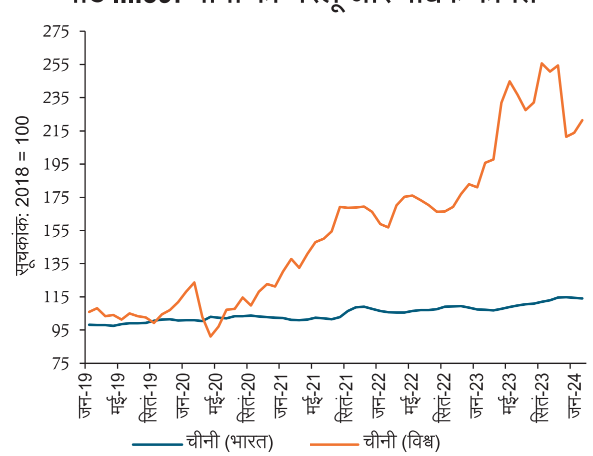

टिप्पणी: चीनी (भारत), डीसीए द्वारा चीनी का औसत खुदरा मूल्य है।
वर्ल्ड बैंक पिंक शीट के अनुसार चीनी (विश्व), अमेरिकी डॉलर में ₹/यूएस$ विनिमय दर से गुणा की गई चीनी की वैश्विक कीमत है।
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए), भारत सरकार; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

सारणी III.3: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		मार्च-23	फर-24	मार्च-24^	फर-24	मार्च-24^
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	102.92	102.79	0.0	-0.1
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	92.72	92.59	0.0	-0.1
मिट्टी का तेल (सब्सिडी प्राप्त)	₹/लीटर	54.21	49.43	49.79	-2.1	0.7
एलपीजी (सब्सिडी के बिना)	₹/सिलेंडर	1113.25	913.25	813.25	0.0	-10.9

^: 1-15 मार्च 2024 की अवधि के लिए।
टिप्पणी: केरोसिन तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.40: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें

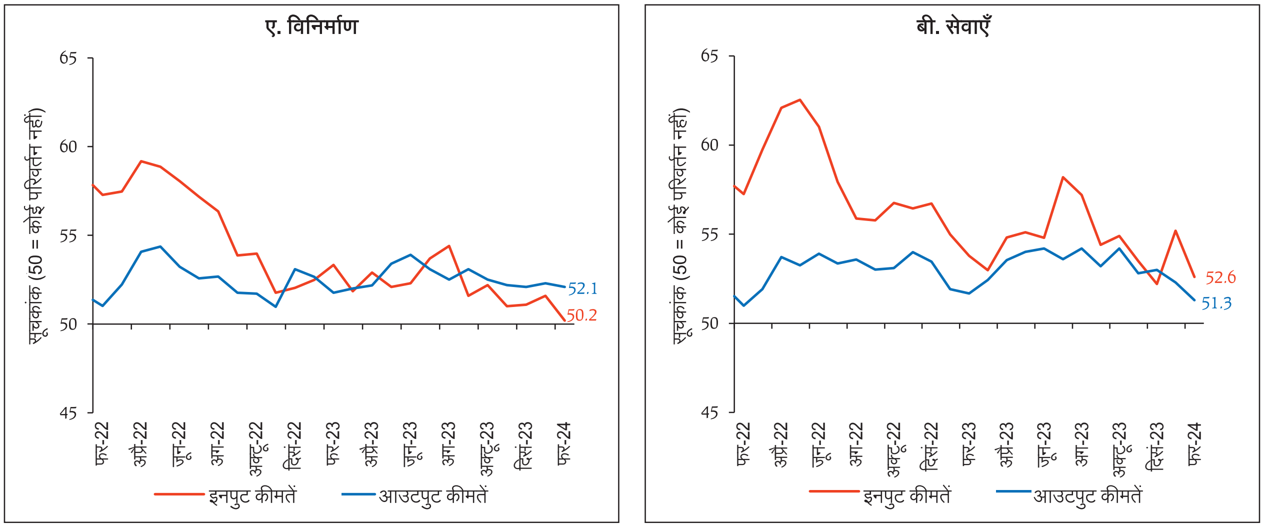

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)[28] 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान 3.8 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ा, जो पिछली तिमाही में 3.5 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 2.8 प्रतिशत था। क्रमिक आधार पर, एचपीआई में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें दस में से छह शहरों में वृद्धि हुई (चार्ट III.41)।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू खपत व्यय पर हाल ही में जारी तथ्य पत्र से पता चलता है कि पिछले दशक में परिवारों के खपत के स्वरूप में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसमें समग्र खपत में खाद्य की हिस्सेदारी में गिरावट आई है (बॉक्स बी)।

चार्ट III.41: आवास मूल्य सूचकांक का उतार-चढ़ाव

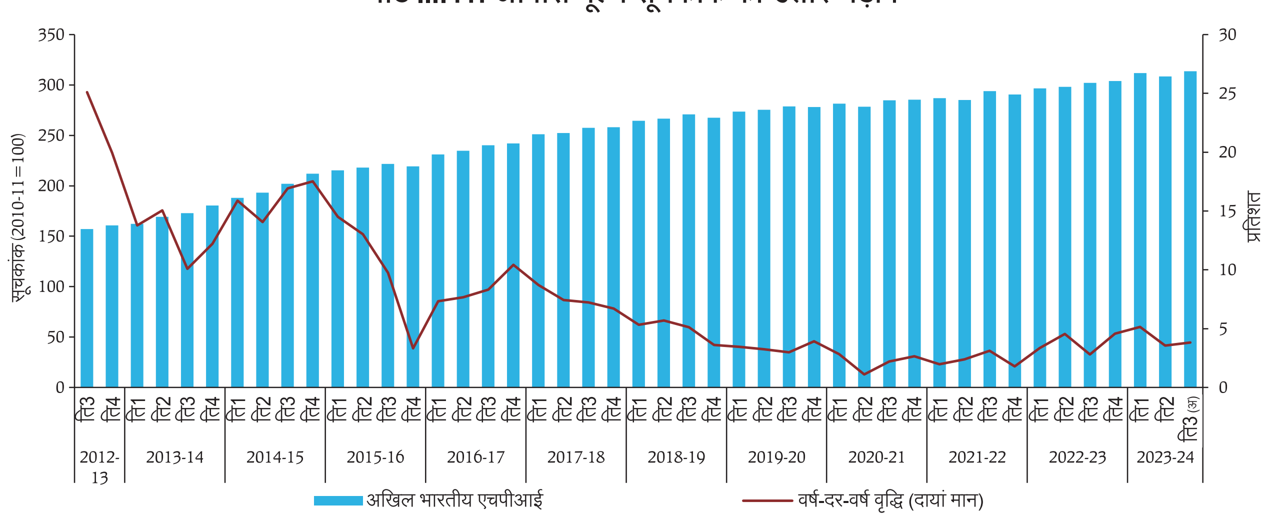

टिप्पणी: अ- अनंतिम

स्रोत: राज्य सरकारों; और आरबीआई के पंजीकरण अधिकारियों से आवास की कीमत का डेटा

[28] आवास मूल्य सूचकांक (आधार: 2010-11=100) दस प्रमुख शहरों (अर्थात-अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

बॉक्स बी: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के मुख्य तथ्य: 2022-23

2022-23 के लिए एचसीईएस के परिणामों के आधार पर एनएसएसओ की फैक्ट शीट भारत में घरेलू व्यय के स्वरूप और जीवन स्तर पर बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराती है, जो सीपीआई के लिए एक अद्यतन भारांक आरेख तैयार करने का आधार होगा। परिणामों से उभरने वाली कुछ प्रमुख बातें नीचे दी गई हैं।

मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 2011-12 और 2022-23 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 52.9 प्रतिशत से घटकर 47.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 42.6 प्रतिशत से घटकर 39.7 प्रतिशत हो गई है, जिसमें अनाज में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। भोजन के भीतर, हालांकि, फलों, दूध और तैयार भोजन जैसे उच्च मूल्य वाले खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (चार्ट बी 1 ए और बी 1 बी)। कुल मिलाकर आय बढ़ने के साथ उपभोक्ता सेवाओं, टिकाऊ वस्तुओं और वाहन जैसी गैर-खाद्य वस्तुओं की ओर खपत हिस्सेदारी का झुकना घरेलू प्राथमिकताओं

चार्ट बी1ए : एमपीसीई की ग्रामीण हिस्सेदारी

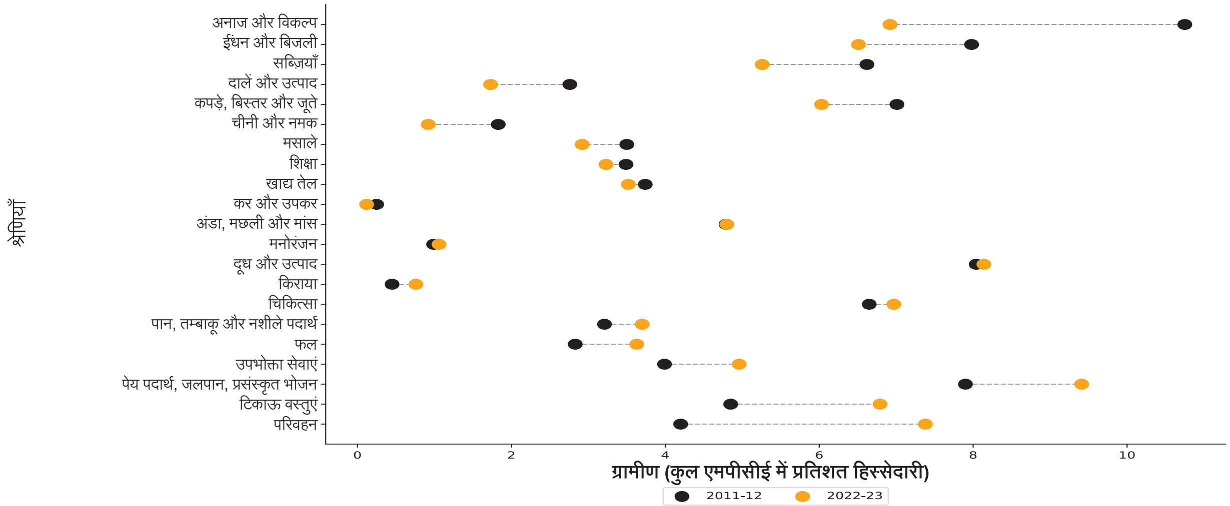

नोट: एमपीसीई हिस्सेदारी विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा मुफ्त प्राप्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्य आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं।
स्रोत: एचसीईएस, और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट बी1बी : एमपीसीई की शहरी हिस्सेदारी

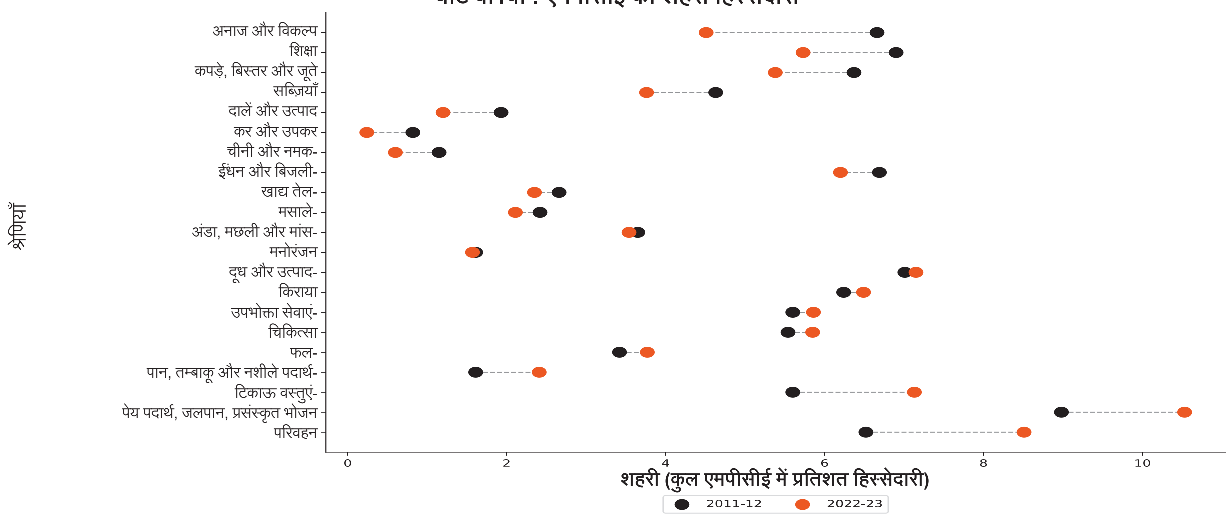

नोट: एमपीसीई हिस्सेदारी विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा मुफ्त प्राप्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्य आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं।
स्रोत: एचसीईएस, और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जारी..)

चार्ट बी2: एमपीसीई हिस्सेदारी में परिवर्तन का मुद्रास्फीति और अस्थिरता पर प्रभाव

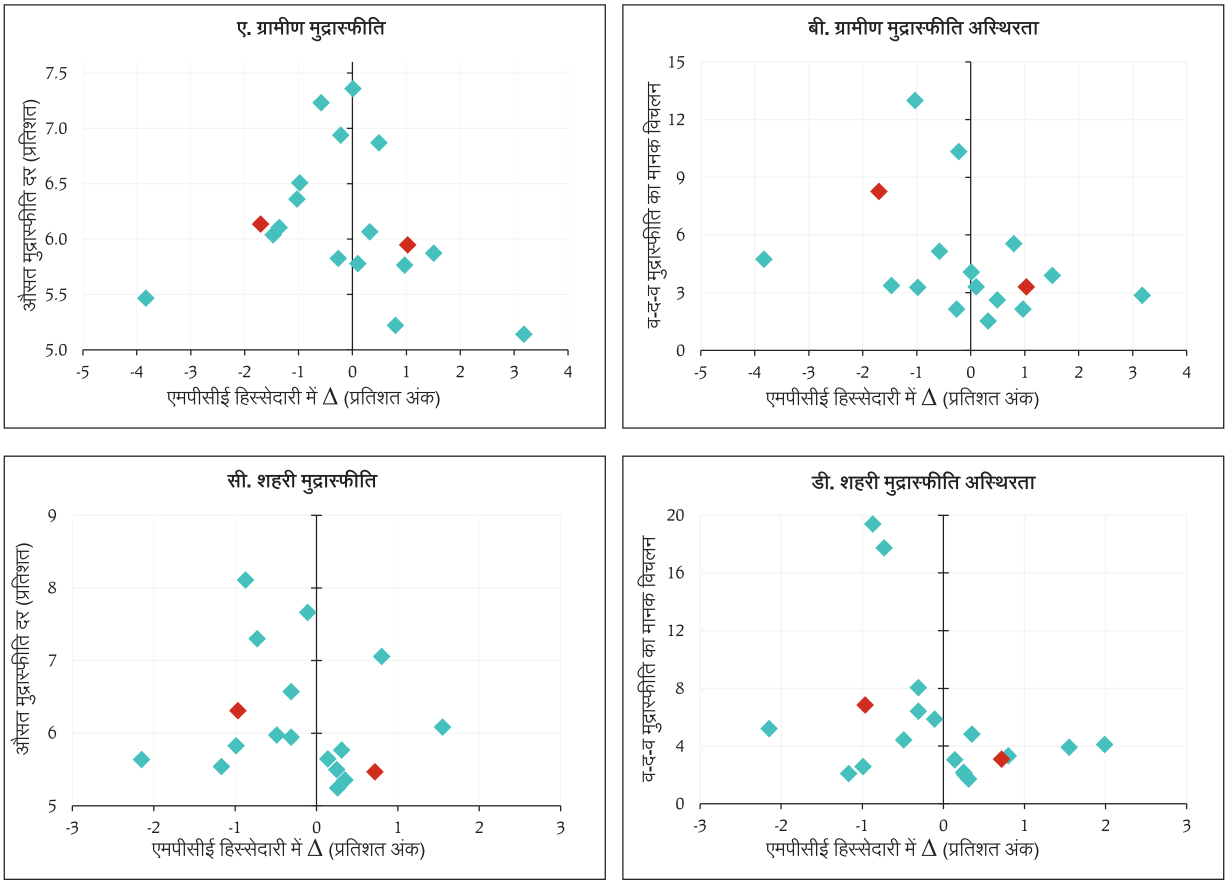

टिप्पणियाँ: 1. लाल डेटा बिंदु एमपीसीई के हिस्से में श्रेणियों के नकारात्मक परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. मुद्रास्फीति औसत और अस्थिरता जुलाई 2011 से जुलाई 2023 की अवधि संबंधी है।
3. उपभोग व्यय में परिवर्तन 2011-12 से 2022-23 तक का है।

स्रोत: एचसीईएस; एमओएसपीआई; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

में हो रहे परिवर्तन की ओर इशारा करता है।

चूंकि सीपीआई की गणना के लिए उपभोग हिस्सेदारी के आधार पर भारांक बनते हैं (मौजूदा सीपीआई के लिए 2011-12 एचसीईएस से भारांक प्राप्त किया गया है), इसलिए ये परिवर्तन खुदरा मुद्रास्फीति के माप को प्रभावित कर सकते हैं। यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तुलनात्मक रूप से उन वस्तुओं की औसत मुद्रास्फीति में जिनकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, और जिनकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है, कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । इसके बावजूद, बढ़ी हुई हिस्सेदारी वाली वस्तुएं काफी कम अस्थिरता (चार्ट बी2ए और बी2बी) प्रदर्शित करती हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए, बढ़ी हुई हिस्सेदारी वाली वस्तुओं के लिए औसत मुद्रास्फीति कम हिस्सेदारी वाली वस्तुओं की तुलना में कम (लगभग 70 आधार अंक) (चार्ट बी2सी)) है। इसी तरह, जिन वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है, उनमें अस्थिरता भी कम है (चार्ट बी2डी)। कुल मिलाकर, उच्च मुद्रास्फीति तथा अस्थिरता वाली वस्तुओं की हिस्सेदारी में पिछले दशक में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई है।

हाल के वर्षों में, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता से घरेलू खपत में वृद्धि हुई है और एचसीईएस सर्वेक्षण के वर्तमान दौर में उनके मूल्य को दर्शाया गया है। सामाजिक कल्याण वस्तुओं के उपभोग का मूल्य

(जारी..)

[29] सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में शामिल हैं (i) खाद्य पदार्थ: चावल, गेहूं/आटा, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, छोटे बाजरा, दालें, चना, नमक, चीनी, खाद्य तेल और (ii) गैर-खाद्य वस्तुएं: लैपटॉप/पर्सनल कंप्यूटर (पीसी), टैबलेट, मोबाइल हैंडसेट, साइकिल, मोटरसाइकिल/स्कूटी, कपड़े (स्कूल यूनिफॉर्म), जूते (स्कूल के जूते, आदि) परिवारों द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया जाता है। हालाँकि, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कल्याणकारी सेवाओं का मूल्य नहीं लगाया गया है।

चार्ट बी3: सभी व्यय वर्गों में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा बीमित उपभोग हिस्सा

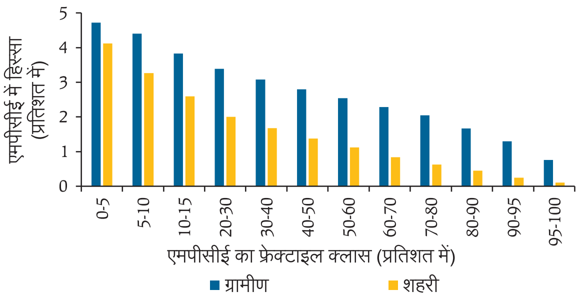

टिप्पणी: सामाजिक कल्याण वस्तुओं के उपभोग के मूल्य की गणना अनुमानित और वास्तविक व्यय के बीच अंतर के रूप में की जाती है।
स्रोत: एचसीईएस; और आरबीआई कर्मचारियों अनुमान।

उनके समग्र उपभोग के हिस्से के रूप में इस बात का संकेत देता है कि सामाजिक कल्याण वस्तुओं के प्रावधान द्वारा घरेलू बजट किस हद तक संरक्षित हैं। ग्रामीण परिवारों को अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है (उनके बजट के हिस्से के रूप में)। इसके अलावा कम संपन्न वर्गों को, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, मुफ्त कल्याणकारी वस्तुओं का अधिक हिस्सा प्राप्त होता है (चार्ट बी 3)।

संदर्भ:

1. एमओएस एवं पीआई (2024)। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस): 2022-23 फैक्ट शीट।

2. जी. वी. नथनएल, सुभद्रा शंकरन, शशि कांत, शाहबाज खान, रजनी दहिया और विश्वजीत मोहंती (2024)। हाउसहोल्ड कंजंप्शन एक्सपेंडीचर सर्वे, 2022-23: ए डीप डाइव, मिमेओ

IV. वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष के अंत में सरकारी व्यय बढ़ने से चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ है। रिज़र्व बैंक द्वारा 8 मार्च 2022 को आयोजित 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए यूएसडी/आईएनआर सेल बाय स्वैप नीलामी के रिटर्न लेग ने भी 11 मार्च 2024 को ₹42,800 करोड़ की चलनिधि उपलब्ध कराई। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में बदल गई और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत मार्च 2024 के दौरान अब तक (15 मार्च तक) ₹ 0.07 लाख करोड़ रुपए के दैनिक औसत दर से चलनिधि का शुद्ध अवशोषण किया गया, जबकि 16 - 29 फरवरी के दौरान औसत दैनिक निवल निविष्टी ₹1.91 लाख करोड़ थी (चार्ट IV.1)। 16 फरवरी और 15 मार्च के बीच रिज़र्व बैंक ने एक दिवसीय से लेकर सात दिवसीय परिपक्वता वाली पांच फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर नीलामियों के अलावा एक 13-दिवसीय तथा एक 15-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) मुख्य परिचालन आयोजित किया।

चार्ट IV.1: चलनिधि परिचालन

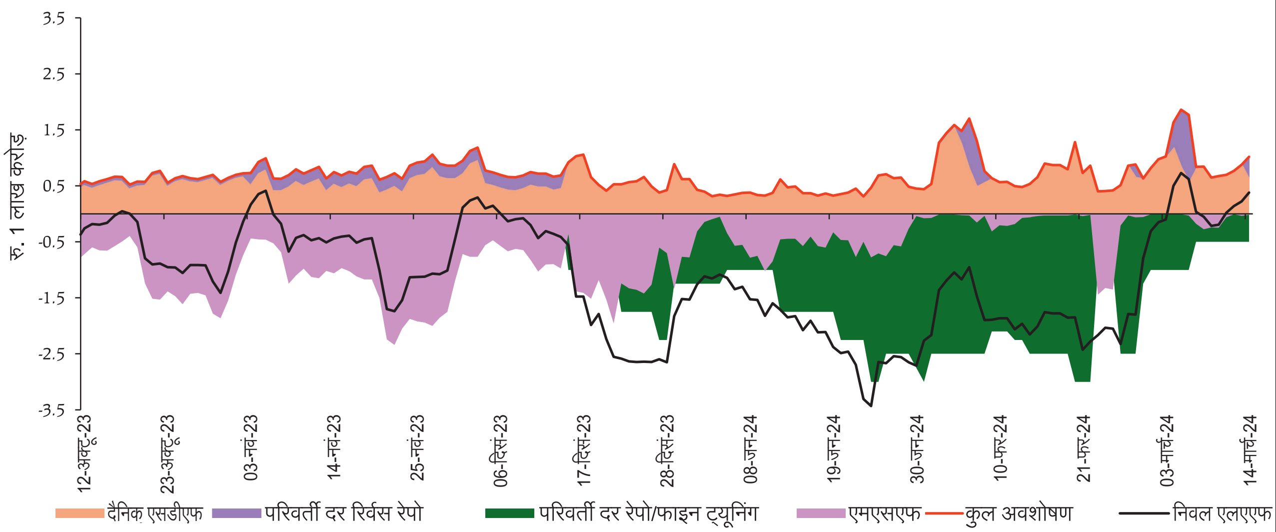

स्रोत: आरबीआई

चलनिधि स्थिति में सुधार के साथ सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत भी उधारी में गिरावट आई है। 0.88 लाख करोड़ रुपये के औसत कुल अवशोषण में से 87.5 प्रतिशत धन को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत रखा गया और शेष को परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) संचालन के माध्यम से प्राप्त किया गया। रिज़र्व बैंक ने अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में आठ फाइन ट्यूनिंग वीआरआरआर परिचालन किए। चलनिधि कमी की स्थिति के चलते मार्च में चलनिधि भंडारण के लिए बैंकों की संभावित प्राथमिकता को देखते हुए इनमें से पांच परिचालन एक दिवसीय परिपक्वता वाले थे।

चलनिधि स्थिति में इन परिवर्तनों के चलते भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) – जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है – नरमी की ओर झुकता दिखाई दिया। नीतिगत रेपो दर और डब्ल्यूएसीआर के बीच का अंतर 16 फरवरी – 15 मार्च 2024 के दौरान 7 बीपीएस हुआ, जो 15 जनवरी – 15 फरवरी 2024 के दौरान 20 बीपीएस था (चार्ट IV.2ए)। इसी दिशा में कोरेटरल क्षेत्र की भी दरें नरम हो गईं। सावधि मुद्रा क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए 3 महीने की अवधि वाले जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल बढ़ा हुआ रहा, जबकि 3 महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) का प्रतिफल अपने चरम से कम हो गया (चार्ट IV.2.बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3-माह वाला सीपी माइनस 91-दिवसीय टी-बिल) 16 फरवरी - 15 मार्च 2024 के दौरान 142 बीपीएस पर उच्च रहा।

प्राथमिक बाजार में सीडी निर्गम माध्यम से वित्त वर्ष के दौरान अब तक (8 मार्च तक) 7.89 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए जो एक साल पहले 6.33 लाख करोड़ रुपये थे। बैंकों ने ऋण की मांग को पूरा करने के लिए सीडी जारी करके उधार लिया। सीपी निर्गम वित्त वर्ष के दौरान अब तक (29 फरवरी तक) 12.2 लाख करोड़ रुपये पर काफी हद तक स्थिर रहा है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 12.5 लाख करोड़ रुपये था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) का प्रतिफल अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में कमी आ जाने के कारण अपने चरम से नीचे आया। भारतीय 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क पर प्रतिफल 15 मार्च को 7.06 प्रतिशत तक नरम हो गया, जो 15 फरवरी को 7.09 प्रतिशत था (चार्ट IV.3ए)। आय वक्र नीचे की ओर हो गया क्योंकि सभी अवधि प्रकारों के प्रतिफलों में गिरावट आई।

चार्ट IV.2 : नीति कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दर

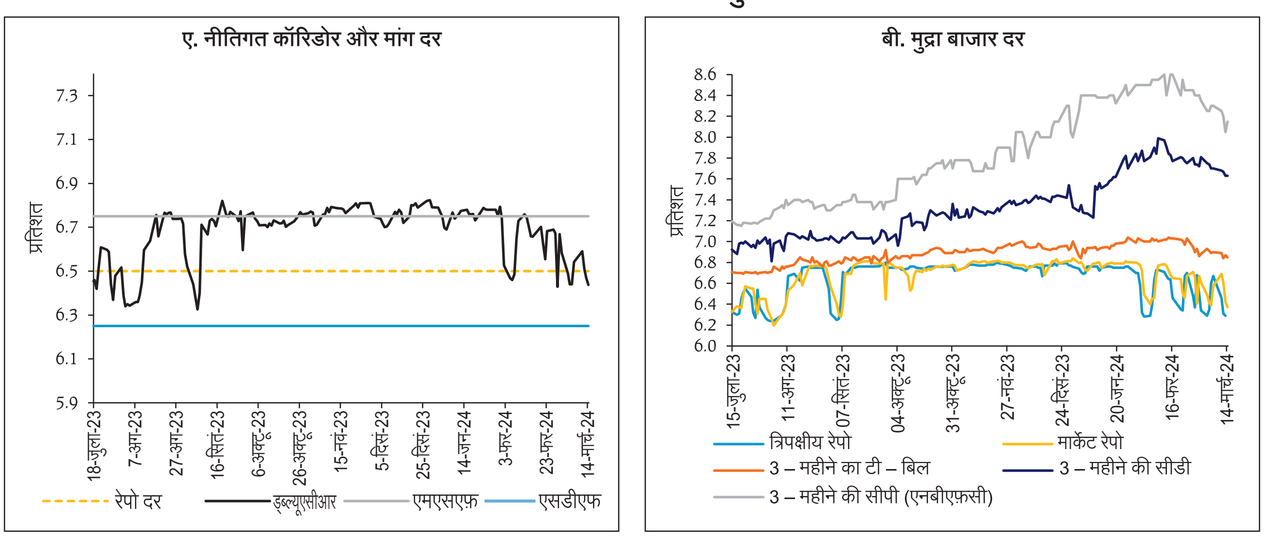

स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल और ब्लूमबर्ग।

चार्ट IV.3: जी-सेक बाजार की गतिविधियां

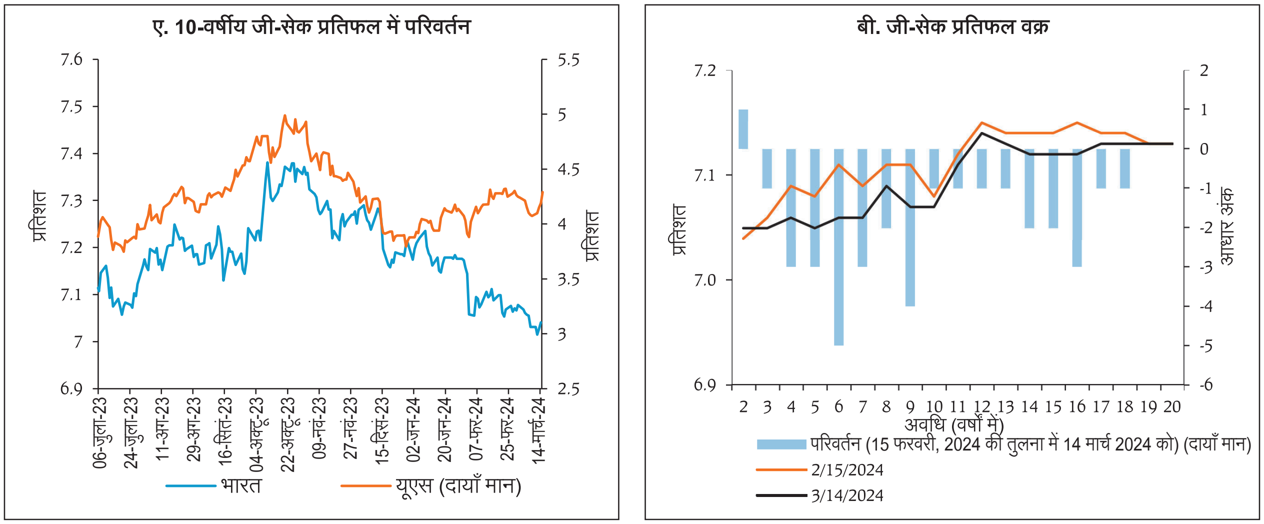

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल और संबंधित जोखिम प्रीमियम में 16 फरवरी - 13 मार्च 2024 के दौरान कभी उतार कभी चढ़ाव रहा (सारणी IV.1)। 2023-24 (फरवरी तक) के दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गमन तुलनात्मक रूप से बढ़कर ₹7.5 लाख करोड़ हुआ जो एक साल पहले ₹6.7 लाख करोड़ था। लंबी अवधि के प्रतिफल में नरमी और स्वस्थ आर्थिक परिदृश्य के बीच सरकारी बॉन्ड बाजार की सापेक्ष स्थिरता ने निवेशकों को ऋण निर्गमों के माध्यम से निवेश के लिए धन जुटाने के लिए प्रेरित किया।

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार बिन्दु) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 जनवरी 2024- 15 फरवरी 2024	16 फरवरी 2024- 13 मार्च 2024	अंतर	16 जनवरी 2024- 15 फरवरी 2024	16 फरवरी 2024- 13 मार्च 2024	अंतर
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	8.01	8.03	2	76	80	4
(ii) एएए (3-वर्ष)	8.00	7.96	-4	84	78	-6
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.81	7.83	2	63	64	1
(iv) एए (3-वर्ष)	8.61	8.55	-6	145	137	-8
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.26	12.19	-7	510	501	-9

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: फिम्डा; और ब्लूमबर्ग।

आरक्षित मुद्रा (आरएम) के तहत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, 8 मार्च 2024 तक 5.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (जो एक साल पहले 10.8 प्रतिशत थी) [चार्ट IV.4]। आरक्षित मुद्रा के सबसे बड़े घटक 'संचलनगत मुद्रा' (सीआईसी) की वृद्धि एक साल पहले के 8.3 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई, जो 2000 रुपए के बैंक नोटों की वापसी को परिलक्षित करती है।[30]

चार्ट IV.4: आरक्षित धन और प्रचलन में मुद्रा

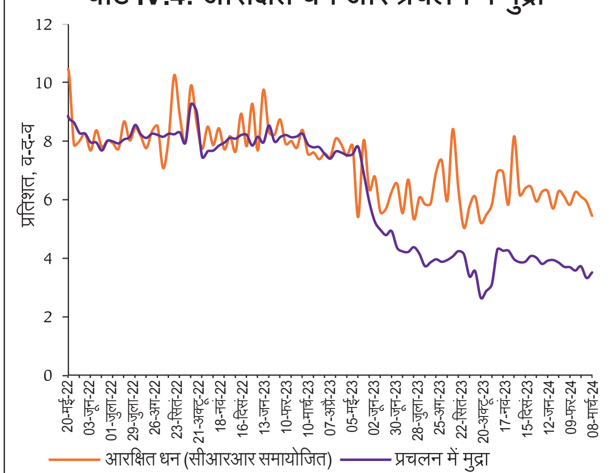

स्रोत: आरबीआई।

[30] 19 मई 2023 को घोषित

चार्ट IV.5: एम$_3$ वृद्धि और एससीबी की ऋण वृद्धि - आधार और गति प्रभाव

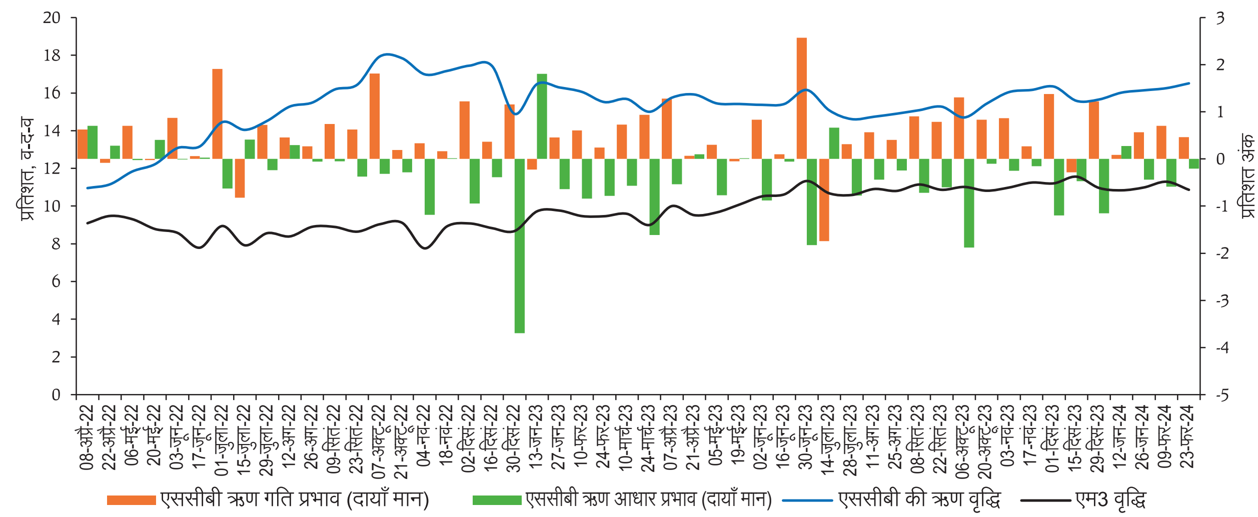

स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा आपूर्ति (एम3) 23 फरवरी 2024 तक 10.9 प्रतिशत से (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी (जो एक साल पहले 9.5 प्रतिशत थी)।[31] बैंकों के पास की सकल जमाराशि, जो एम3 का सबसे बड़ा घटक है, में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (जो एक साल पहले 9.7 प्रतिशत थी)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 23 फरवरी 2024 तक 16.5 प्रतिशत थी (जो एक साल पहले 15.5 प्रतिशत थी) [चार्ट IV.5]।

एससीबी की जमाराशि में वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) फरवरी 2024 में दोहरे अंकों में रही (चार्ट IV.6)।

चार्ट IV.6: एससीबी का सकल जमा और ऋण वृद्धि- वेज

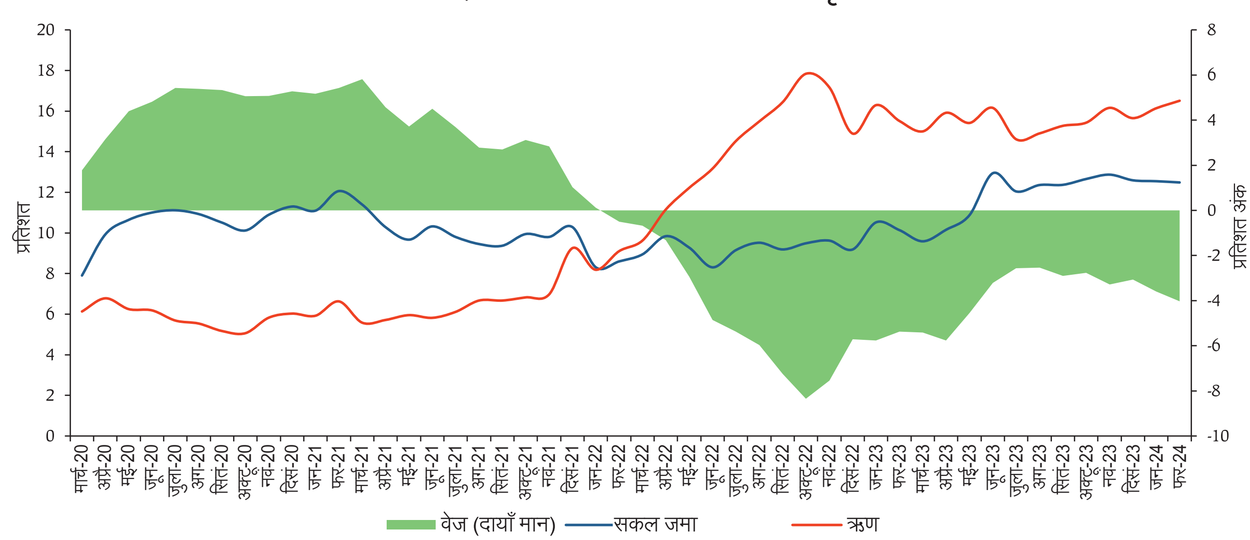

स्रोत: आरबीआई।

[31] एक गैर-बैंक का एक बैंक के साथ हुए विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई 2023 से प्रभावी)।

चार्ट. IV.7: वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

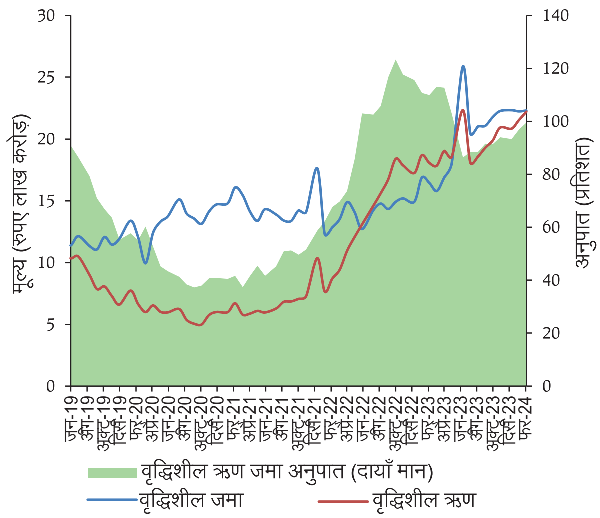

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.8: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) तथा वाणिज्यिक पत्र (सीपी) – पाक्षिक निर्गम

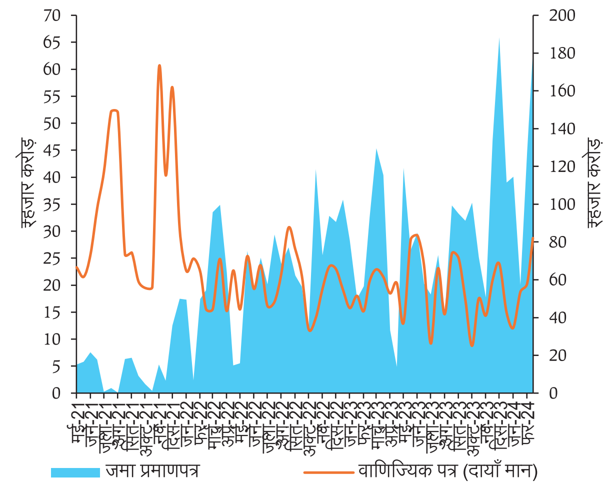

स्रोत: आरबीआई।

23 फरवरी 2024 तक वृद्धिशील क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 96.9 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि मार्जिन रखते हुए जमाराशियां ऋण मांग को पूरा करने में सक्षम रही हैं (चार्ट IV.7)।

4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की क्रमशः सीआरआर और एसएलआर की सांविधिक आवश्यकताओं के साथ लगभग 77 प्रतिशत जमाराशि 23 फरवरी 2024 तक ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली के पास उपलब्ध थी। जमाराशि आधार में सीडी निर्गम भी शामिल था (चार्ट IV.8)।

कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋण में वृद्धि दोहरे अंकों में जारी रही जो कोविड-19 महामारी के बाद 2023- 24 की तीसरी तिमाही के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी। उद्योग क्षेत्र के लिए बैंक ऋण भी पांच तिमाहियों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। आवास क्षेत्र के लिए बैंक ऋण का दोहरे अंकों में बढ़ना जारी रहा, हालांकि इसमें कुछ अंतरालों पर नरमी आई थी। गैर-आवास व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि, जो 2022-23 की दूसरी तिमाही में 27.2 प्रतिशत के शिखर पर थी, 2023-24 की तीसरी तिमाही में घटकर 19.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.9)।

निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को बैंक ऋण, जो कुल बैंक ऋण का लगभग एक चौथाई हिस्सा था, ने 2023-24 की दूसरी और तीसरी तिमाही में तेज वृद्धि दर्ज की (चार्ट IV.10)।

चार्ट IV.9: बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि- प्रमुख क्षेत्र

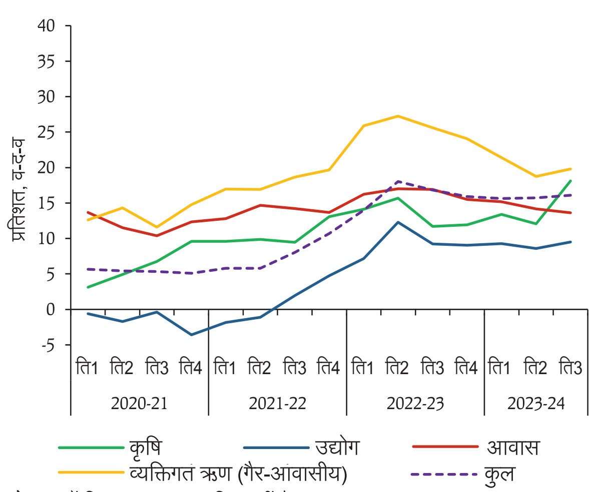

नोट: इनमें विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.10: वार्षिक ऋण वृद्धि- उधारकर्ताओं की प्रमुख स्वामित्व श्रेणी

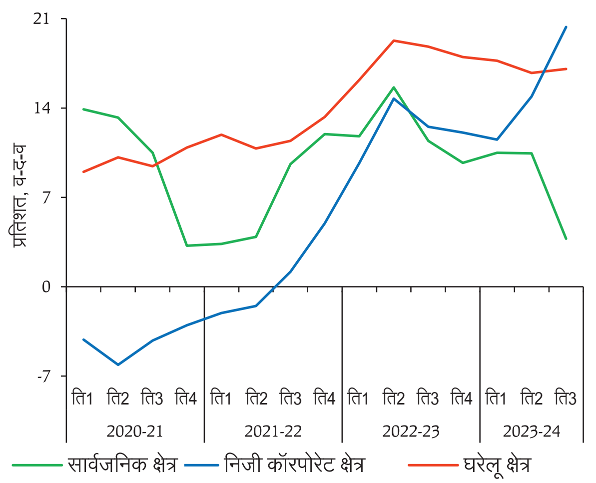

टिप्पणी: इसमें विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.11: वार्षिक ऋण वृद्धि – ऋण प्रकार

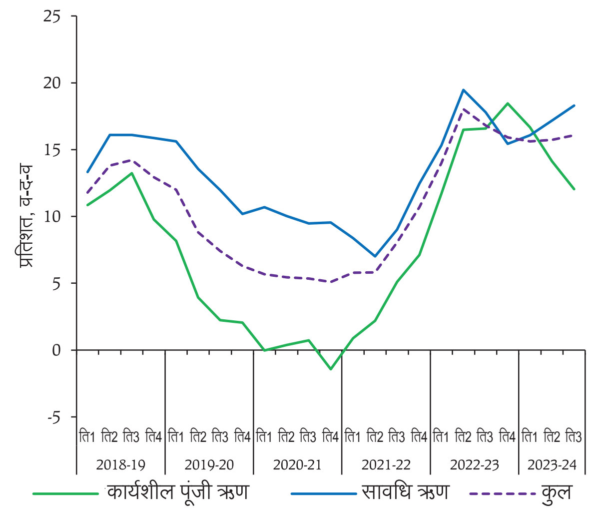

टिप्पणी: इसमें विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत: आरबीआई

हालांकि, कार्यशील पूंजी ऋण वृद्धि में कुछ मंदी दर्ज की गई (चार्ट IV.11)।

मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी वृद्धि के कारण मई 2022 से फरवरी 2024 के दौरान निधि आधारित उधार दर की 1-वर्षीय औसत सीमांत लागत (एमसीएलआर) में 169 बीपीएस की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप मई 2022 से जनवरी 2024 के दौरान नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 194 बीपीएस की वृद्धि हुई और बकाया रुपया ऋणों पर 113 बीपीएस की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान नई और बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएटीटीडीआर) में क्रमशः 240 बीपीएस और 181 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

मई 2022 – जनवरी 2024 के दौरान नए रुपये ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर का असर निजी बैंकों (पीवीबी) की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए अधिक था, जबकि निजी बैंकों के लिए बकाया रुपया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर का प्रभाव अधिक था। सावधि जमा के मामले में पीएसबी ने अपनी जमा दरों में पीवीबी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की (चार्ट IV.12)।

नीतिगत दर में वृद्धि के प्रभाव को परिलक्षित करते हुए 8.0 प्रतिशत से अधिक ब्याज दरों वाले बैंक ऋणों की हिस्सेदारी मार्च

सारणी IV.2: बैंक-जमा और ऋण दरों में रेपो दर का संचरण

(आधार अंकों में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर (बीपीएस)	सावधि जमा दरें (बीपीएस)		ऋण दरें (बीपीएस)			
		डब्ल्यूएडीटीडीआर - नया जमा	डब्ल्यूएडीटीडीआर -बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्ष एमसीएलआर (मीडियन)	डब्ल्यूएएलआर- नया रुपए ऋण	डब्ल्यूएएलआर- बकाया रुपए ऋण
		खुदरा और थोक जमा					
सहजता का दौर फरवरी 2019 से मार्च 2022	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्ती की अवधि मई 2022 से जनवरी 2024	+250	240	181	250*	169*	194	113

टिप्पणी: 1-वर्षीय एमसीएलआर से संबंधित आंकड़े फरवरी 2024 तक के लिए हैं।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.12: बैंक समूहों के बीच संचरण (मई 2022 से जनवरी 2024)

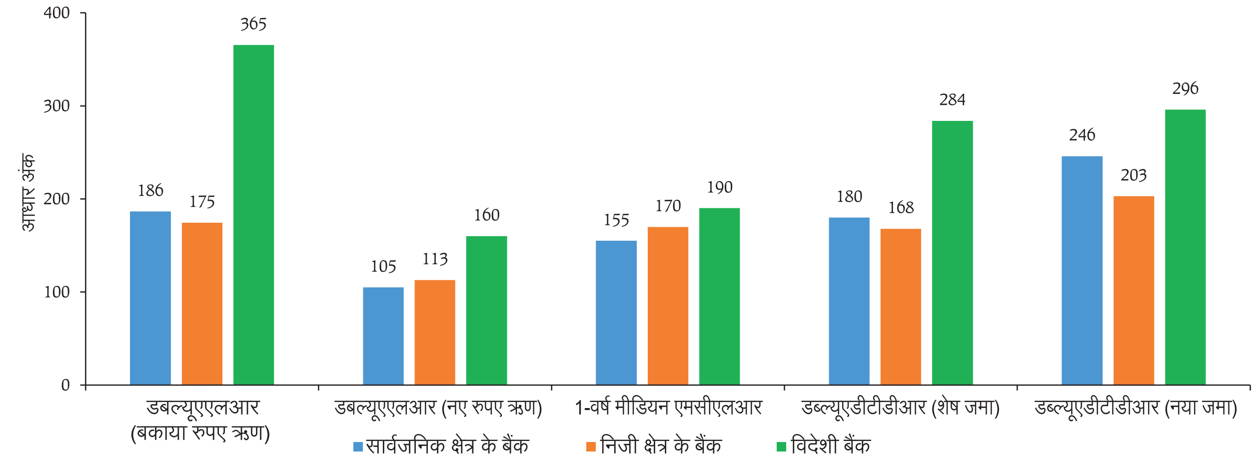

टिप्पणी: 1-वर्षीय एमसीएलआर से संबंधित आंकड़े फरवरी 2024 तक के लिए हैं।
स्रोत: आरबीआई।

2022 में 47.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 78.9 प्रतिशत और दिसंबर 2023 में 83.7 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.13)।

7 प्रतिशत और उससे अधिक ब्याज दरों की पेशकश करने वाली सावधि जमा की हिस्सेदारी भी दिसंबर 2023 में बढ़कर 61.4 प्रतिशत हो गई जो मार्च 2023 में 33.5 प्रतिशत और मार्च 2022 में 4.5 प्रतिशत थी (चार्ट IV.14)।

इससे बचत जमाराशियों की तुलना में सावधि जमाराशियों के प्रति आकर्षण बढ़ा है (चार्ट IV.15)।

फरवरी 2024 के पूर्वार्ध में अस्थिर रहने के बाद भारतीय शेयर बाज़ार ने लाभ दर्ज किया। कुल मिलाकर बेंचमार्क जनवरी के अंत से 1,345 अंक (1.9 प्रतिशत) बढ़कर 14 मार्च 2024 को 73,097 पर बंद हुआ (चार्ट IV.16)। वैश्विक बाजारों के

चार्ट IV.13: बैंक ऋण और अग्रिम- ब्याज दरें

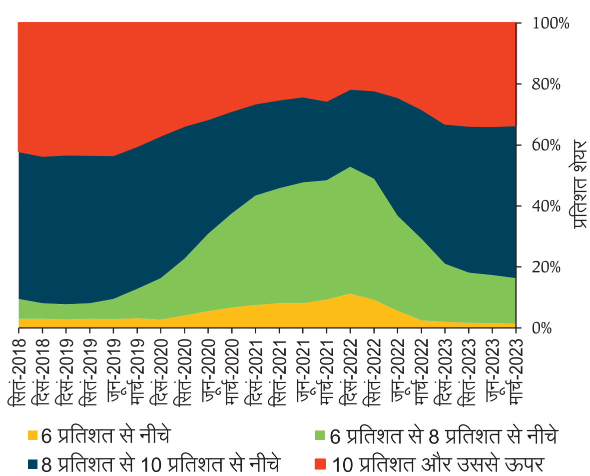

टिप्पणी: इसमें विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.14: बैंकों की सावधि जमाओं पर ब्याज दर के अनुसार हिस्सेदारी

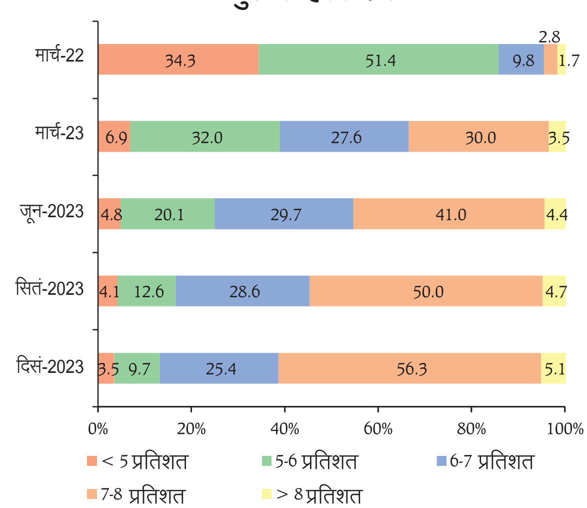

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.15: कुल जमा पर वार्षिक वृद्धि – जमा के प्रकार

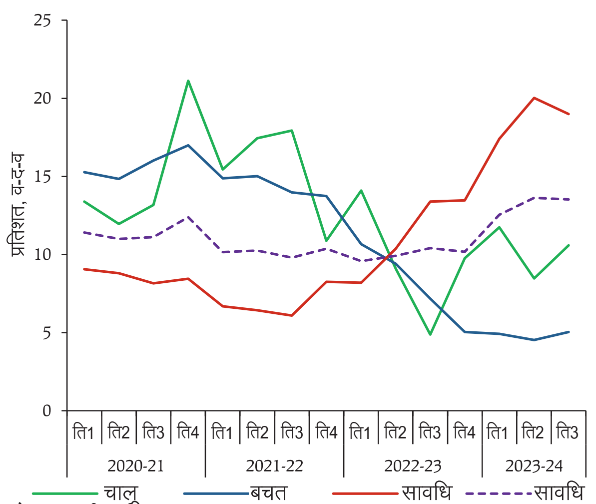

स्रोत: आरबीआई।

सकारात्मक संकेतों के साथ-साथ 2023-24 की तीसरी तिमाही के मजबूत घरेलू जीडीपी डेटा से बाजार उत्साहित थे। हालांकि, व्यापक बाजार सूचकांकों में बीएसई मिडकैप इंडेक्स और बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में फरवरी-मार्च 2024 के दौरान अब तक क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। फरवरी 2024 में ओपन-एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा कुल निवल पूंजी जुटाव 23.3 प्रतिशत माह-दर-माह बढ़कर 26,866 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि स्मॉलकैप और मिडकैप योजनाओं में निवेश 11 प्रतिशत घटकर 4,731 करोड़ रुपये रह गया।

अप्रैल 2023 – जनवरी 2024 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 3.6 प्रतिशत घटकर 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि के दौरान यह 61.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट IV.17ए)। विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाओं, बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों, वित्तीय सेवाओं और परिवहन का इसी अवधि के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में लगभग दो-तिहाई हिस्सा रहा। लगभग 80 प्रतिशत इक्विटी प्रवाह सिंगापुर, मॉरीशस, यूएस, नीदरलैंड, जापान और संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त हुए थे। अप्रैल 2023 - जनवरी 2024 के दौरान निवल एफडीआई एक साल पहले के 25.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण प्रत्यावर्तन में वृद्धि है। 2023 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह कमजोर रहने के बावजूद[32], जिसमें 2022 की तुलना में केवल 3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, भारत ने एशियाई साथियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट IV.17बी)।

चार्ट IV.16: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह

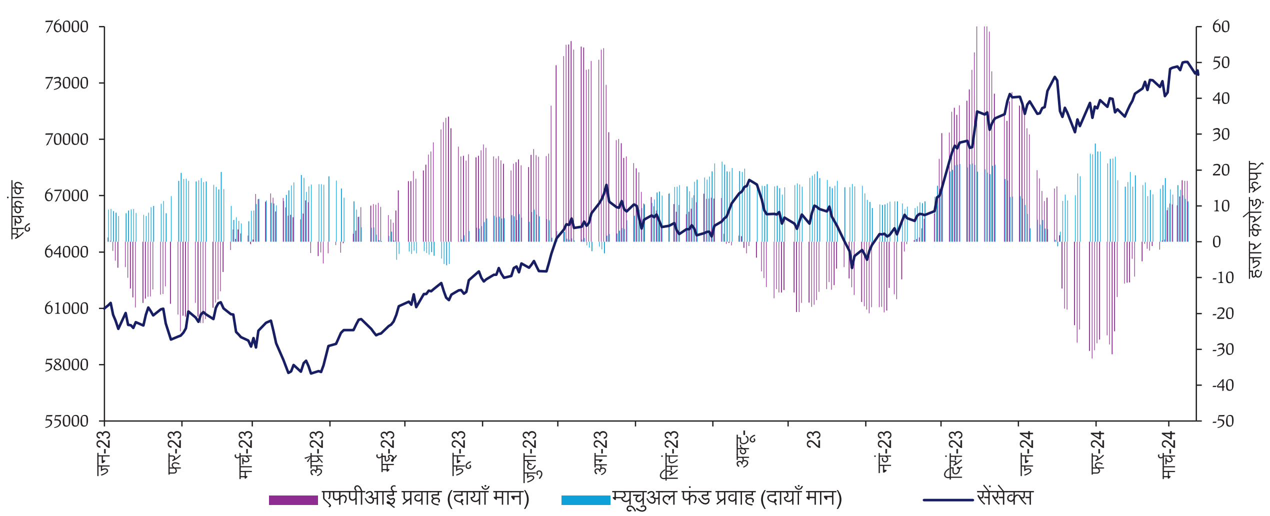

टिप्पणी: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और म्यूचुअल निधि (एमएफ) प्रवाह 15 दिनों के चक्रीय योग आधार पर दर्शाये गए हैं।
स्रोत : ब्लूमबर्ग।

32 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी), ग्लोबल इनवेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर, जनवरी 2024 के अनुसार

चार्ट IV.17 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

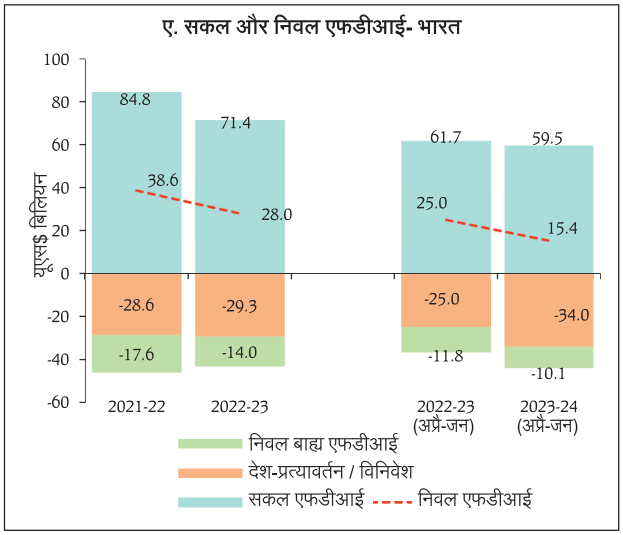

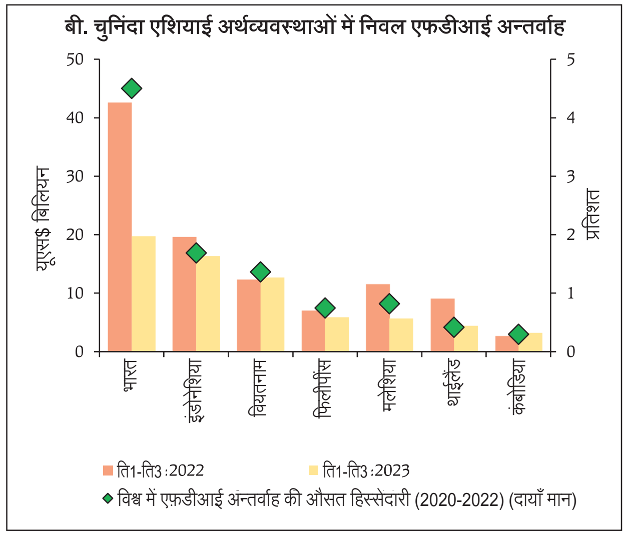

स्रोत : आरबीआई; यूएनसीटीएडी, आईएमएफ़ और सीईआईसी

भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह फरवरी 2024 में सकारात्मक हो गया, जो मजबूत घरेलू विकास दृष्टिकोण से प्रेरित था। फरवरी 2024 में निवल एफपीआई प्रवाह 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मुख्य हिस्सेदारी ऋण खंड की थी, और जिसके अंतर्गत फरवरी 2024 में 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए जो अप्रैल 2019 के बाद से सबसे अधिक है (चार्ट IV.18ए)। इक्विटी क्षेत्र में उपभोक्ता सेवाएं, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, स्वास्थ्य सेवा और पूंजीगत सामान फरवरी 2024 के दौरान अग्रणी एफपीआई प्राप्तकर्ता क्षेत्र थे (चार्ट IV.18बी)। मार्च 2024 (14 तारीख तक) के दौरान निवल एफपीआई प्रवाह 5.6 बिलियन यूएस डॉलर था। 2023-24 के दौरान अब तक (अप्रैल 01- मार्च 14), निवल एफपीआई प्रवाह 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2015-16 के बाद से सबसे अधिक है। भारत को चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-फरवरी) के दौरान उभरते बाजारों के बीच सबसे अधिक इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ।

चार्ट IV.18: निवल पोर्टफोलियो निवेश

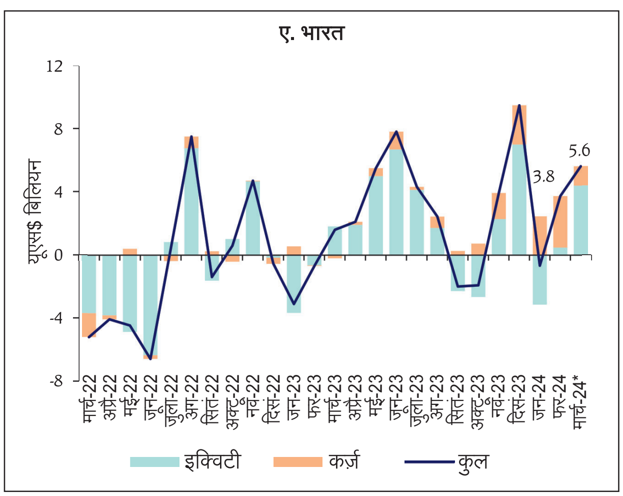

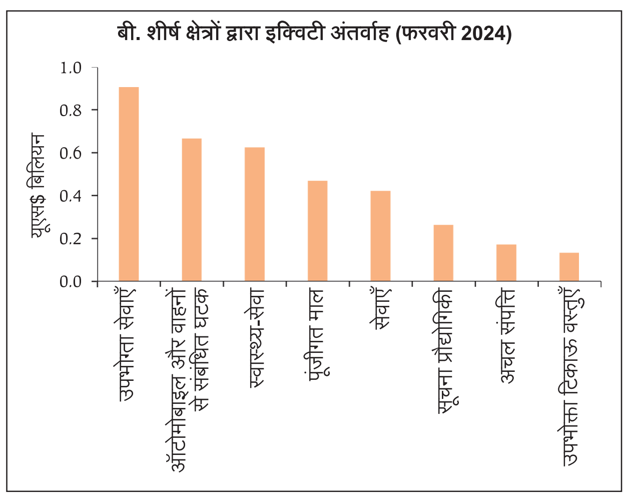

टिप्पणियाँ: 1. ऋण में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग और हाइब्रिड उपकरणों के तहत निवेश शामिल है।
2. *: 14 मार्च 2024 तक का डेटा।

स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड।

चार्ट IV.19 : बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण और प्रवाह

स्रोत: आरबीआई।

अनिवासी जमाराशियों में कुल निवल अभिवृद्धि अप्रैल 2023 – जनवरी 2024 के दौरान बढ़कर 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो एक साल पहले 6.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें विदेशी मुद्रा अनिवासी [एनसीएनआर(बी)] खाते, अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)ए] और अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाते शामिल हैं।

संचयी आधार पर अप्रैल 2023 – जनवरी 2024 के दौरान बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पंजीकरण (यूएस $ 39.2 बिलियन) और संवितरण (यूएस $ 30.1 बिलियन) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक थे। दूसरी ओर, इस अवधि के दौरान मूल चुकौती के कारण ईसीबी बहिर्वाह 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसके परिणामस्वरूप एक साल पहले 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह की तुलना में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ (चार्ट IV.19)।

अप्रैल 2023 – जनवरी 2024 के दौरान पंजीकृत कुल ईसीबी में से तीन-चौथाई से अधिक समझौतों को पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) उद्देश्यों (कैपेक्स के लिए ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग सहित) के लिए निर्धारित किया गया था [चार्ट IV.20]। इस वित्तीय वर्ष में अब तक नए ईसीबी की भारित औसत परिपक्वता 5.5 वर्ष (पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 5.8 वर्ष) थी।

हालांकि ईसीबी की समग्र लागत मुख्य रूप से वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दरों, जैसे कि सिक्यूअर्ड ओवरनाइट फाइनांसिंग रेट (एसओएफआर)[33] में वृद्धि के कारण पिछले दो वर्षों में बढ़ी है, भारित औसत ब्याज मार्जिन (डब्ल्यूएआईएम) (बेंचमार्क दरों से ऊपर) अप्रैल 2023 - जनवरी 2024 के दौरान घटकर 155

चार्ट IV.20 : पंजीकृत ईसीबी का अंतिम उपयोग

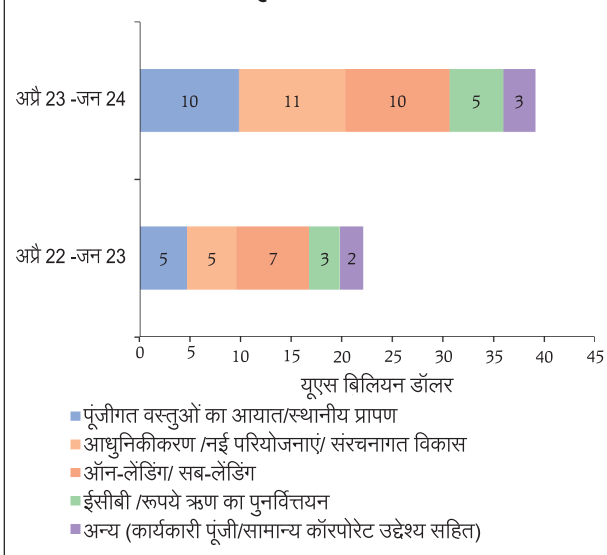

[33] वैश्विक मौद्रिक नीति की सख्ती रुक जाने से एसओएफआर जुलाई 2023 से लगभग 5.3 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।

चार्ट IV.21 : ईसीबी पर कुल लागत

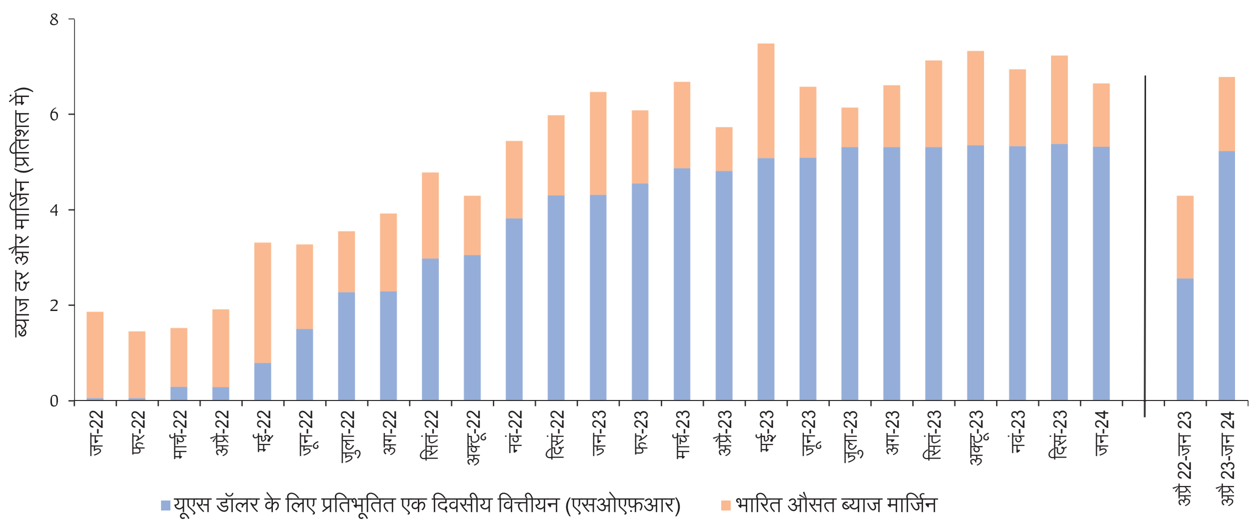

स्रोत: आरबीआई।

बीपीएस हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 173 बीपीएस था (चार्ट IV.21)।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 मार्च 2024 को 636.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023-24 के लिए अनुमानित 10.9 महीने के आयात और सितंबर 2023 के अंत में बकाया कुल बाहरी ऋण की 100 प्रतिशत की आवश्यकता से अधिक था (चार्ट IV.22ए)। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 57.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है, जो विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले प्रमुख देशों में दूसरा सबसे अधिक है (चार्ट IV.22बी)।

चार्ट IV.22: विदेशी मुद्रा भंडार

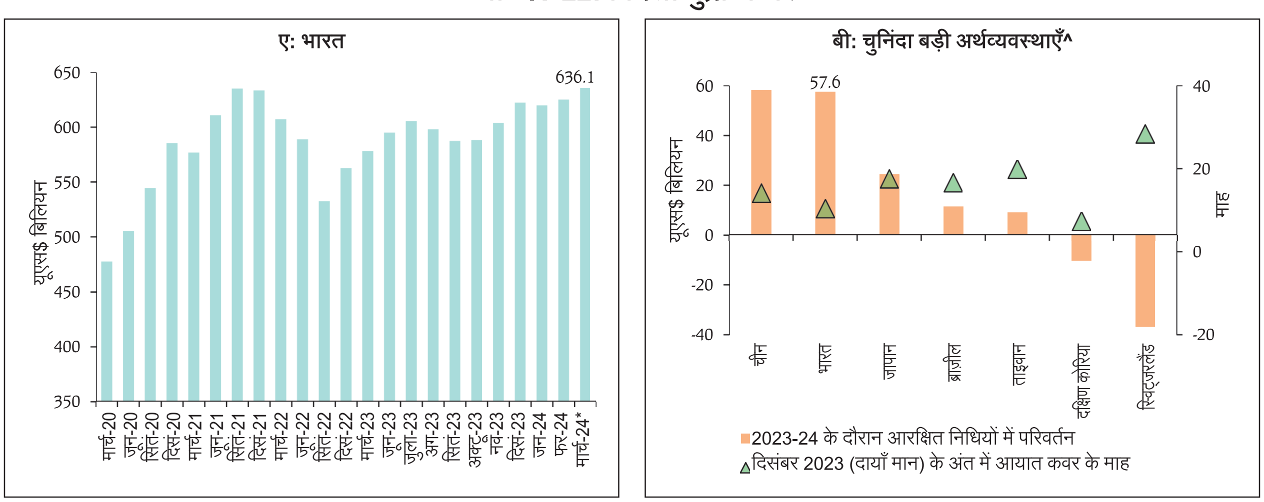

टिप्पणी: 1. * डेटा 8 मार्च 2024 के लिए है।
2. विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित नवीनतम डेटा भारत के लिए 8 मार्च 2024, स्विट्ज़रलैंड के लिए जनवरी 2024 के अंत और शेष देशों के लिए फरवरी 2024 के अंत के लिए है जबकि आयात कवर डेटा भारत के लिए सितंबर 2023 और अन्य देशों के लिए दिसंबर 2023 के लिए है।

स्रोत: आरबीआई; सीईआईसी; और संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें।

चार्ट IV.23: अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए और प्रमुख देशों की मुद्रा का उतार-चढ़ाव (जनवरी 2024 की तुलना में फरवरी 2024)

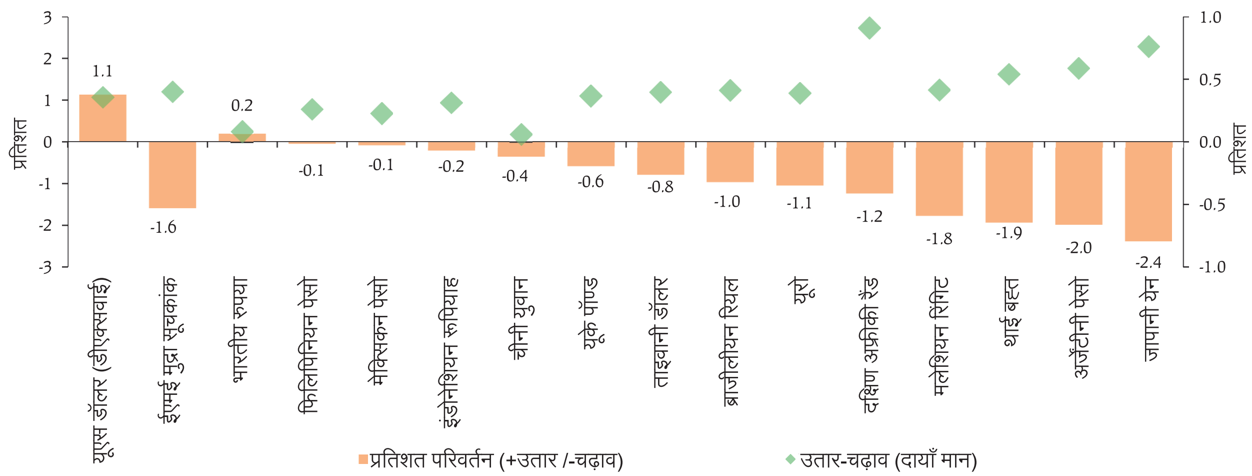

टिप्पणी: यूएस डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, यूके पॉण्ड, कनाडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक) के बास्केट की तुलना में यूएस डॉलर के उतार-चढ़ाव को मापता है

स्रोत: एफ़बीआईएल, थॉमसन रॉयटर्स और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

फरवरी 2024 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया (आईएनआर) 0.2 प्रतिशत (माह-दर-माह) बढ़ा, जबकि अन्य प्रमुख मुद्राओं ने मूल्यह्रास दबाव का अनुभव किया। इसके अलावा फरवरी 2024 के दौरान आईएनआर सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक था (चार्ट IV.23)।

फरवरी 2024 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में आईएनआर में 1.0 प्रतिशत (माह-दर-माह) में मजबूती आई, क्योंकि नकारात्मक सापेक्ष मूल्य अंतर से अधिक नॉमिनल इफेक्टिव संदर्भ में आईएनआर में मजबूती आई (चार्ट IV.24)।

चार्ट IV.24 : 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में उतार-चढ़ाव

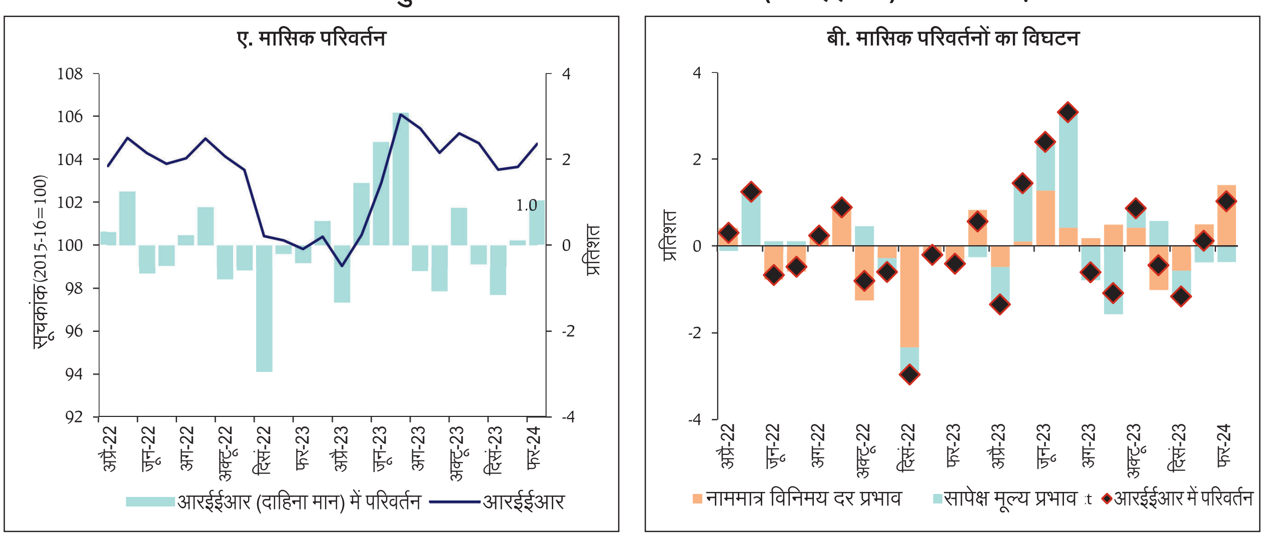

स्रोत: आरबीआई।

भुगतान प्रणाली

प्रमुख भुगतान प्रकारों में डिजिटल लेनदेनों ने फरवरी 2024 में बेहतर विस्तार (व-द-व) बनाए रखा (सारणी IV.3)। विशेष रूप से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) ने 29 फरवरी 2024 को एक ही दिन में अब तक का सर्वाधिक, 4.1 करोड़ लेनदेन संसाधित करते हुए एक मील का पत्थर हासिल किया। पिछले एक दशक (2013-14 से 2022-23) में एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) ने मात्रा के संदर्भ में क्रमशः 700 प्रतिशत और 200 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 670 प्रतिशत और 104 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने मार्च 2023 और जनवरी 2024 के बीच 6.65 करोड़ नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ते हुए महीने के दौरान सभी प्रकारों में सबसे अधिक मात्रा में वृद्धि दर्ज की।[34] इसके अलावा, यूपीआई सुविधा का उपयोग करके ग्रीस से भारत में सीमा पार भुगतान बढ़ाने और प्रेषण को सुव्यवस्थित करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड [एनआईपीएल] ने ग्रीस के एक अग्रणी बैंक, यूरोबैंक एसए, के साथ भागीदारी की है।[35]

व्यवसायों और उपभोक्ताओं द्वारा उपयोगिता बिल भुगतान और उच्च मूल्य लेनदेन के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), जो एक एकीकृत और इंटरऑपरेबल बिल भुगतान प्रणाली है, की उपयोगिता में वृद्धि के कारण मूल्य के संदर्भ में उसमें वृद्धि दर्ज हुई है। प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और अधिक भागीदारी को संभव बनाने तथा ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बीबीपीएस ढांचे में संशोधन किए गए हैं ताकि गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) को ऑपरेटिंग इकाइयों के रूप में प्रणाली में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान विकल्पों को सुविधाजनक बनाने, गति देने, किफायती बनाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैंक और गैर-बैंक जारीकर्ताओं को प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारी करने के लिए अधिकृत किया है ताकि विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान सुविधा उपलब्ध हो सके। क्रेडिट/डेबिट कार्ड के संबंध में बिलिंग चक्र लचीलापन, बैंकों और एनबीएफसी के बीच सह-ब्रांडिंग व्यवस्था, प्लास्टिक कार्ड के अलावा अन्य स्वरूपों[36] की अनुमति, चूक रिपोर्टिंग के संबंध में प्रक्रियाओं का पालन और कार्ड डेटा आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध सहित विनियमों को मजबूत करने के लिए मास्टर निदेशों में संशोधनों की एक शृंखला जारी की गई है।[37] रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के कार्य ढांचे को अद्यतन किया है, जिसमें विभिन्न चरणों के लिए संशोधित समय-सीमा और संस्थाओं को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता को शामिल किया गया है।

सारणी IV.3 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	जन-23	जन-24	फर-23	फर-24	जन-23	जन-24	फर-23	फर-24
आरटीजीएस	12.6	13.1	11.2	18.8	20.1	17.1	16.7	21.2
एनईएफ़टी	32.2	43.4	28.7	47.3	15.0	19.8	12.1	25.1
यूपीआई	74.1	51.8	66.4	60.6	56.1	41.7	49.5	47.9
आईएमपीएस	7.8	7.2	6.4	19.4	23.4	18.6	21.9	21.2
एनएसीएच	-10.5	22.8	67.3	13.1	13.1	21.5	35.2	15.6
एनईटीसी	30.2	10.2	18.4	12.1	33.6	15.5	29.0	19.2
बीबीपीएस	59.8	24.6	54.1	29.8	66.6	75.4	63.4	85.8

नोटः आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान; **एनईएफटी**: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण; **यूपीआई**: एकीकृत भुगतान इंटरफेस; **आईएमपीएस**: तत्काल भुगतान सेवा; **एनएसीएच**: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह; **एनईटीसी**: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह; और **बीबीपीएस**: भारत बिल भुगतान प्रणाली।
स्रोत : आरबीआई

V. निष्कर्ष

दुनिया संरचना और भावना संबंधी बड़े बदलावों का सामना कर रही है, जो या तो चल रही हैं या आसन्न हैं। भावी काल अनिश्चितता की परतों से घिरा हुआ है, जिसमें भू-राजनीतिक और चरम मौसम के जोखिमों के साथ-साथ विखंडित ताकतें भी जुड़ गई हैं। इसके विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अनुकूल व्यापक आर्थिक दौर से गुजर रही है जो इसके संवृद्धि मार्ग को बेहतर बनाने में एक नया आधार बन सकता है। 2021-24 की अवधि में संवृद्धि दर औसतन 8 प्रतिशत से ऊपर रही है; और अंतर्निहित बुनियादी बातों से संकेत मिलता है कि इसे बनाए रखा जा सकता है, और यहां तक कि इसे बनाया भी जा सकता है।

[34] 4 मार्च 2024 को आरबीआई, मुंबई द्वारा आयोजित डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह समारोह में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर का संबोधन

[35] एनपीसीआई परिपत्र, 29 फरवरी 2024.

[36] पहनने योग्य वस्तुएं जैसे कि घड़ी, कलाई पर पहने जाने वाले बैंड अथवा अंगूठी

[37] मास्टर निदेश – क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड, 7 मार्च 2014

मुद्रास्फीति उतार-चढ़ाव पर है; कोर मुद्रास्फीति में स्थिर गिरावट के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर जा सकती है बशर्ते छोटे-छोटे खाद्य मूल्य दबावों की पुनरावृत्ति न हो। जनवरी और फरवरी 2024 के सीपीआई आंकड़ों से पता चलता है कि सब्जियों की कीमतों में सर्दियों में आई नरमी अस्थायी और अल्पकालिक थी। अनाज की कीमतों में मजबूत गति बनी हुई है, और मांस और मछली की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। हेडलाइन पर खाद्य मूल्य दबावों को कोर अवस्फीति द्वारा शृंखला के सबसे निम्न स्तर पर नियंत्रित किया गया। कोर मुद्रास्फीति में नरमी व्यापक आधार पर रही है। ईंधन की कीमतें अपस्फीति में बनी हुई हैं और मार्च में लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमत में कमी के कारण यह और भी कम हो सकती हैं। कुल मिलाकर, हेडलाइन मुद्रास्फीति की गति फरवरी 2024 में सकारात्मक हो गई, जिससे अनुकूल आधार प्रभाव समाप्त हो गया। तदनुसार, मौद्रिक नीति को जोखिम कम करने का दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि संवृद्धि की गति को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के पास लाया जा सके।

अन्य संकेतक भी समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता का संकेत देते हैं। चालू खाता घाटा निम्नतर स्तर पर है, बाहरी बफर समुत्थानशील हैं और राजकोषीय समेकन लगातार तीसरे वर्ष में है, जबकि कॉरपोरेट अपने ऋणों को कम कर हैं और अपनी ऋण सेवा क्षमता में सुधार कर रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र में तुलन-पत्र मजबूत और स्वस्थ हैं, जो एक पुनरुत्थान अर्थव्यवस्था की उत्पादक ऋण आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए सुविधा प्रदान कर सकते हैं। वित्तीय बाजार इन अनुकूल संरचनाओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। भारत में निवेशकों की दिलचस्पी लौट आने से पूंजी प्रवाह फिर से शुरू हो गया है।

प्रौद्योगिकी अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनी है जो विकास के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। अब समय आ गया है कि अगले कुछ दशकों में इन अनुकूल कारकों को अवसर और शक्ति में बदलने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, मजबूत विनिर्माण आधार, उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति और सेवाओं में वैश्विक नेतृत्व का निर्माण किया जाए।